हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 फरवरी, 2009

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 19 फरवरी, 2009

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
विभिन्न सरकारी कालेजो/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन	(8)38

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(8)39
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(8)41
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन करना	(8)47
राज्यपाल से सन्देश	(8)47
वर्ष 2009–10 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)48
नियम 64 के अधीन वक्तव्य	(8)71
वर्ष 2009–10 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)72
बैठक का समय बढ़ाना	(8)93
वर्ष 2009–10 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)93
बैठक का समय बढ़ाना	(8)101
वर्ष 2009–10 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)101
बैठक का समय बढ़ाना	(8)106

वर्ष 2009–10 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)106
बैठक का समय बढ़ाना	(8)109
वर्ष 2009–10 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)109
वर्ष 2009–2010 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा मतदान	(8)112
विधान कार्य–	(8)118
दि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ शराईन बिल, 2009	(8)118
दि हरियाणा फायर सर्विस बिल, 2009	(8)118
बैठक का समय बढ़ाना	(8)121
दि हरियाणा फायर सर्विस बिल, 2009 (पुनरारम्भ)	(8)121
दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(8)122
पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटीज आफ हैल्थ साईंसिज रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(8)124

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 18 फरवरी, 2009

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

ताराकिंत प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Questions Hour.

Opening of I.T.1. in Village Nandgaon

***1071. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Industrial Training & Vocational Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I. in village Nandgaon in Bhiwani constituency as the village has offered a school building, 17 rooms and ground for the same; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी): श्रीमान जी, भिवानी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नन्दगांव में आई०टी०आई० खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में पहले ही पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

डा० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ

तथ्यों पर मंत्री जी विचार करेंगे कि एक तो नंदगांव मेन रोड से 17 कि०मी० की दूरी पर है और वहां पर गांव वाले 17 कमरे, एक बड़ा हाल और मैदान मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त इस गांव के आसपास 10 कि०मी० की दूरी तक दूसरी कोई आई०टी०आई० भी नहीं है। क्या मंत्री जी इन तथ्यों पर विचार करते हुए नंदगांव में आई०टी०आई० खोलने पर विचार करेंगे? नंदगांव में आई०टी०आई० खुलने से भिवानी और दादरी हल्के के बच्चों को बहुत फायदा होगा। **श्री ए०सी० चौधरीः** अध्यक्ष .महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने आई०टी०आई० खोलने के नार्म्ज रखे हुए हैं जिनमें दो बड़े प्रीरिक्यीजिट हैं। एक तो जहां पर आई०टी० आई० खोलनी है उसके आसपास कम से कम 20 कि०मी० तक कोई दूसरा इस प्रकार का संस्थान न हो। दूसरा जो जगह आई०टी०आई० खोलने के लिए प्रपोज्ड हो वह मेन रोड पर हो। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे माननीय साथी नंदगांव में आई०टी०आई० खोलने की बात कर रहे हैं वह नंदगांव मेन रोड से 17 कि०मी० की दूरी पर है। वहां के लिए मेन रोड से कोई रास्ता नहीं बनता। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस समय भिवानी में? आई०टी०आईज० चल रही हैं और 5 आई०टी०आईज० पाईपलाईन में हैं जो एप्रूव हो गई हैं। इन हालात में मुझे नहीं लगता कि नंदगांव मैं आई०टी०आई० बनानी वायबल होगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो 20 कि०मी० के दायरे का जिक्र किया है कि 20 कि०मी० के दायरे में ऐसा संस्थान न हो तभी आई०टी०आई० खोली जायेगी। इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या दूरी का क्राईटेरिया 20 कि०मी० का फिक्स है या आबादी का ख्याल रखते हुए दूरी कम भी कर दी जाती है। दूसरा मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि 17– 18 साल पहले 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान खेड़ी कलां और उकलाना में दो वोकेशनल सैंटर खोले गए थे। उसके बाद सरकार बदलने के बाद वे वोकेशनल सैंटर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए। यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक पब्लिक मीटिंग में भी उठा और उन्होंने ऐलान किया कि इन दोनों जगहों में से एक जगह पर वोकेशनल सैंटर नहीं तो एक आई०टी०आई० अवश्य खोली जाएगी। यह मुख्यमंत्री जी की अनाउसमैंट है। तकरीबन पीने चार साल हो गए अभी तक वहां पर आई०टी०आई० नहीं छनी है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर सरकारी बिल्डिंग भी बनी हुई है। इसलिए मंत्री जी कृपा बतायेंगे कि वहां पर कय तक आई०टी०आई० खोल दी जायेगी?

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दूरी का मतलब ही यह है कि आसपास कितने हायर सैकेण्डरी स्कूल हैं जहां से बच्चे पास आऊट होकर आई०टी०आईज० में दाखिला ले सकें। यदि कहीं पर

स्कूलों की संख्या ज्यादा होती है तो दूरी में मामूली सी कमी की जा सकती हे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आई०टी०आई० बनाने पर लगभग 10 करोड़ रुपये का खर्चा बिल्डिंग और मशीनरी पर लगता है और एक करोड़ रुपये सालाना उसका रैकरिंग खर्चा है। उसको जस्टीफाई करने के लिए हमारे पास उचित स्ट्रैंथ होना बहुत जरूरी है। जहां तक दूसरा प्रश्न है उसके जवाब में मैं बताना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने पहली बार जिक्र किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाऊंसमेंट हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। माननीय साथी ने इस बारे में मेरे से पहले कभी कोई जिक्र नहीं किया इसलिए माननीय साथी मुझे इस बारे में एक फोरमल सा नोट लिखकर दे दें तो मैं उस पर अपने विभागीय अधिकारियों को तुरन्त कार्यवाही करने के लिए बोल दूंगा।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, जब औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा का महकमा मेरे पास था तो मैंने तीन गांवों क्रमशः भौजी खालसा, इंद्री हल्का, जिला करनाल, सुलतानपुर, नीलोखेड़ी हल्का, जिला करनाल और कसान, हल्का पाई, जिला कैथल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर वोकेशनल एजूकेशन इंस्टीच्यूट्स की स्थापना करवाई थी जो कि 18 साल से वहां चल रहे थे। अब सरकार द्वारा उनकी तजमीम की गई है। ये' सभी तीनों स्टेशन नजदीकी मेन आई०टी०आई० से लगभग 18–20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह रिकवैस्ट है कि इनमें आई०टी०आई० खोल दी जाये

बेशक कम ट्रेडज की खोल दी जाये ताकि आसपास के गांवों के बच्चे जो कि टेक्नोक्रेट बनते जा रहे हैं उनको मौका मिले।

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, इस बारे में माननीय सदस्य को अलग से क्यैचन पूछना चाहिए था फिर भी मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहूंगा कि लेटेस्ट सैनेरियो को देखते हुए अब हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्किट बन चुका है और अब हमारे यहां पर सैंडविच कोर्सिज का कोई स्कोप नहीं है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत टेक्नोक्रेट्स और एक्सपरटाईज की है। इसलिए हमने जो वोकेशनल इंस्टीच्यूट्स जो कि सैंडविच टाईप के थे। उनको बंद करके उनमें जो इंफ्रास्टक्चर एकेडेमिक साईड का था उसको हमने एजूकेशन डिपार्टमैंट को दे दिया है और जो टेक्नोक्रेट्स थे उन्हें हमने आई०टी०आईज० में समायोजित कर दिया है। जिनकी बिल्डिंग किराये की थी या पंचायतों के साथ सांझी थी तो वे हमने टेक्नीकल एजूकेशन को दे दी और जो दूसरी थी वे हमने एजूकेशन डिपार्टमैंट को दे दी हैं as on date वे बिल्डिंग्स दी जा चुकी हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि इससे बच्चों का भविष्य जुड़ा है तो मैं इसको फिर से एग्जामिन करवा लूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः स्पीकर सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र नारनौल में स्थानीय लोगों ने 5–6 एकड़ जमीन पुर लगभग 10 लाख रुपये की लागत से एक शानदार बिल्डिंग बनाकर दी थी जिसमें वोकेशनल इंस्टीच्यूट चल रहा है। अब मुझे जानकारी मिली

है कि सरकार वोकेशनल इंस्टीच्यूट बंद करने जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि अगर उस वोकेशनल इंस्टीच्यूट को आई०टी०आई० में कन्वर्ट कर दिया जाये तो इससे वहां के विद्यार्थियों को फायदा हो जायेगा।

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पर कोई वायदा करना या देखने का एशोरैंस देना वाजिब होगा क्योंकि हमने आलरेडी 28 और आई०टी०आई० खोलने की घोषणा की है जो कि पाईपलाईन में हे। आप समझ सकते हैं कि उसमें हमारे पास कुल बजट 70 करोड़ रुपये का है जबकि लायबिलिटी जो कि इस वक्त पाईपलाईन में हैं वह 280 करोड़ रुपये की है। इस हालत में हम नहीं चाहते कि पिछली सरकार की तरह हम आगे लायविलिटी पास–ऑन करें इसलिए हम पहले अपने उन प्रोजैक्टस को पूरा करना ज्यादा उचित समझते हैं जो इस समय पाईपलाईन में हैं।

श्री साहिदा खानः स्पीकर सर, मेरा विधान सभा क्षेत्र तावडू है। उसके पास धारूहेड़ा, आई०एम०टी० मानेसर हैं, रोज का मेव और रिवाड़ी भी साथ में लगता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूँगा कि तावडू में एक आई०टी०आई० की सख्त जरूरत है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कोई आश्वासन देंगे?

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, अभी तक अपनी इस डिमाण्ड के बारे में माननीय साथी द्वारा लिखकर मेरे नोटिस में नहीं लाया गया इसलिए अगर ये मुझे सैपरेट नोटिस दें तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जो पिछड़ा इलाका है उसमें आई०टी०आई० खोलने के बारे में हम जरूर विचार करें।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, इसमें अगर नॉर्म्ज और क्राईटेरिया पूरे होते हों तो kinldy consider it.

श्री ए०सी० चौधरीः ठीक है स्पीकर सर। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं भी अर्ज करना चाहूंगा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार पहली सरकार है जिसने मेवात के इलाके के लिए बहुत ज्यादा विकास के काम किये हैं। स्पीकर सर, मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि मेवात के मामले में आज की कांग्रेस सरकार ने इतने प्रोग्रैसिव क्लम उठाये है कि हरियाणा की सबसे बड़ी आई०टी०आई० नूंह में खोली जा रही है और मेवात के शिक्षा के अभाव को महसूस करते हुए ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमने मेवात के लोगों के लिए 50 परसैंट सीटें रिजर्व कर दी हैं ताकि इन लोगों को एनक्रेज किया जाये और ये लोग मेन स्ट्रीम में आकर पूरी तरह से प्रदेश और देश के निर्माण में सहयोगी सावित हो सकें।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रादौर विधान

सभा क्षेत्र में भी कोई नई आई०टी०आई० खोलने का सरकार का विचार है?

श्री अध्यक्षः पलाका साहब, रादौर में पहले कितनी आई०टी आईज० हैं?

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, रादौर में पहले कोई आई०टी०आई० नहीं है। रादौर विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट सनाली गांव में है और ये चर्चा हो रही है कि सरकार वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूटस को बंद करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर पंचायत ने जमीन भी दी हुई हे, बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया है इसलिए उस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, सनाली को आई०टी०आई० में कन्वर्ट कर दिया जायं ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सिर्फ बिल्डिंग ही सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अर्ज किया है कि एक आई०टी०आई० पर एक करोड़ रुपये का रैकरिंग खर्च आता है। उसके अलावा हमें इनपुट भी देखनी होती है। साथ ही यह भी देखना होता है कि आस–पास के एरिया से कितने बच्चे पास आऊट होकर आ सक्ते हैं। अगर वे इंट्रैस्टिड ही और उनमें पढ़ने की लहर हो तो उस मामले में हम एग्जामिन कर सक्ते हैं या इस

बारे में कोई डिमांड आए। इस मामले में मुझे अब तक कोई डिमांड नहीं मिली है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी बता रहे हैं बिल्डिंग तो वहाँ पर पहले ही छनी हुई है उसको तो सिर्फ आई०टी०आई० में कन्वर्ट करने की ही बात है।

श्री अध्यक्षः इस सवाल का जवाब आ गया है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री. जी से जानना चाहूँगा कि रावलधी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत एक आई०टी०आई० बन रही है और पी०डब्ल्यू०डी० ने कहा है कि मई तक वह तैयार हो जायेगी। उसके अलावा स्टाफ के लिए क्या मंत्री जी कोई प्रबन्ध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि नंदगांव का प्रोजैक्ट अगर एप्रूव हो जाये तो उससे मेरे हल्के दादरी के बच्चों को भी काफी फायदा हो सकता है।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह सकता हूँ कि जहां तक माननीय सदस्य ने रावलधी के बारे में पूछा है उस बारे में मैं बताना चाहूँगा वह पहले ही हमारी एप्रूवल में है। हमने जो 28 आई०टी०आईज० की एप्रूवल दी है वह उनमें आती है। अध्यक्ष महोदय मुझे खुशी भी हो रही है कि भिवानी ही मात्र एक ऐसा जिला है जिसमें अब तक हम प्रावधानों के हिसाब से आईटीआई. की 4284 सीटें एलोकेट कर चुके हैं जिसमें से 1294

तो मौजूदा जो रनिंग वाले है उनमें हैं और 3 हजार के लिए स्टूडैंट्स का हमने और प्रावधान किया है। रही बात रावलधी की तो ज्यों ही साथ–साथ पैसा आता रहेगा तो मैं उसको प्रायरटी में रखूंगा।

श्री सुखवीर सिंह फरमाणाः अध्यक्ष महोदय, मेरा गांव फरमाणा, गोहाना, खरखौदा, रोहतक और सोनीपत के बीच में स्थित है। वहां पर कम से कम 9 हजार की आबादी है। वहां पर स्वर्गीय ची धरी देवीलाल जी ने बतौर उप–प्रधानमंत्री कॉलेज की आधारशिला रखी थी लेकिन वहां पर केवल दस कमरे बना कर ही छोड़ दिये गये थे। उनमें पहले वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोला हुआ था लेकिन अब वह भी बन्द हो चुका है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस बिल्डिंग में अगर आई०टी०आई० खोल दी जाये तो मेरे हल्के के बच्चों को उसका फायदा हो सकता है जिसके लिए मैने लिख कर भी दे रखा है।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्य से विनम्र निवेदन है कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारी रिक्यायरमैंट बहुत कम रही है। कमरे भी बहुत छोटे साईज के थे लेकिन आज के युग में बच्चे भी मॉडर्न हो गये हैं उनको इनवायरनमैंट का बड़ा ध्यान रहता है। छोटे घोसलानुमा कमरों में हम टैकनीकल एजूकेशन नहीं दे पायेंगे क्योंकि हमारी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम अपने हरियाणा के बच्चों को अव्वल दर्जे के टैक्नोक्रेट्स के रूप में देश को समर्पित करेंगे। मैं

माननीय साथी से कहना चाहता हूँ कि प्रश्न पूछने के बजाय वे अपनी डिमांड लिख कर भेज दें मैं उसको पूरी तरह से एग्जामिन करवा लूंगा और इनको बता दूंगा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं।

श्री रामकिशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के बवानी खेड़ा में एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलता था लेकिन वह बन्द कर दिया है, क्या मंत्री जी उसकी जगह कोई आई०टी०आई० खोलने का प्रावधान करेंगे क्योंकि वहाँ पर आबादी काफी है और आस–पास के बहुत से गाँव उससे जुड़ सकते हैं?

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अब जो 28 प्रोजैक्ट्स पाईपलाईन में हैं उनमें बवानीखेड़ा का नाम नहीं है क्योंकि अकेले भिवानी में 7 आई०टी०आई० पहले ही वर्किंग कंडीशन में हैं और 5 पाईपलाइन में हैं। फिर भी मैं माननीय साथी से कहना चाहूँगा कि अगर इनके ध्यान में कोई ऐसी बात है जो कि क्राइटेरिया पूरा करती हो तो मुझे लिख कर भिजवा दें, मैं उसको एग्जामिन करवा लूंगा।

Employees working on contract basis

***1046. Sh. Radhey Shyam Sharma Amar :** Will the Health Minister be pleased to state the names and addresses of the employees working on contract basis in the Civil Hospital, Narnaul during the period from January, 2006 to

date ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, the information is placed on the Table of the House.

Information

Sr. No	Name & Designation	Father/Husband	Name Addresses	Period
1.	Smt. Kusum Lata Saini, Staff Nurse	Sh. Sunil Saini	Gen. Hospital Campus, Narnaul	2-11-07 to 3 1 -3-08 2-4-08 to 19-8-08
2.	Smt. Saroj, Staff Nurse	Sh. Leela Ram	V.P.O. Meghot Halla, Mahendergarh	4-4-06 to 31-3;07 1-4-07 to 31-1-08 2-4-08 to 20-O-08
3.	Miss Poonam Yadav, Staff Nurse	Sh. Ram Parkash	V.P.O. Kanina, Mahendergarh	5-1 l -07 to 31-3-08 2-4-08 to 19-8-08
4.	Smt. Sunita, Staff Nurse	Sh. Ram Kishan	V.P.O. Pawera, Mahendergarh	4-4-06 to 31-3-07 3-4-07 to 31-3-08 2-4-08 to 7-9-08
5.	Sh. Sandeep Kumar Lab	Sh. Chander	V.P.O. Gannaur,	4-4-06 to 31-3-07 3-4-07 to 31-3-08

	Technician	Singh	Sonipat	2-4-08 till date
6.	Sh. Rajesh Kumar Lab Technician	Sh. Banwari Lal	Vill. Sareli	6-3-2000 till date
7.	Sh. Rajesh Saini Lab Technician	Sh. Sadhu Ram	Vill. Bhungarka, Mahendergarh	14-12-05 till date
8.	Sh. Lalit Kumar Counsellor	Sh. Om Parkash	Gandhi Road, Sampla, Rohtak	12-8-08 till date
9	Smt. Rajesh, Data Entry Operator	Sh. Sunil Kumar	Mohalla Chanduwara, Narnaul	10-8-06 to 15-4-08 15-4-08 till date

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों ने जो सूचना उनको दी है यह अधूरी ओर गलत है। जो फोर्थ क्लास का स्टाफ है उसका जवाब में कोई वर्णन नहीं किया गया हे।

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, जो सही पोजीशन हे वह आप बता दें।

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है वह इसलिए गलत है क्योंकि उनको जी०पी०एफ० नहीं देते हैं और उनको पूरा वेतन भी नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या पूरी सूचना दे कर और जो जी०पी०एफ० में गड़बड़ हो रही है तथा कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है क्या शोषण करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी .अनुमति से माननीय साथी और सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि 27 ऐसे व्यक्ति हैं जो आउटसोर्सिग पालिसी के तहत जनरल हॉस्पीटल, नारनौल में हमने लगाए हैं अगर उनकी तनख्वाह को ले कर माननीय सदस्य जी को कोई शक है तो इनकी बात को वाजिब मानते हुए हम इसकी जांच करवा लेंगे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर कोई कोताही पाई गई तो हम ऐसे सर्विस काण्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे . और यह सुनिश्चित भी करेंगे कि सभी को पूरी तनख्याह मिलती रहे।

Transfer of P.W.D. (B&R) and HUDA Roads to M.C. Gurgaon

***1115. Sh. Dharmbir :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to transfer PWD (B&R) and HUDA Roads within the old Municipal Limits to the newly

created Municipal Corporation, Gurgaon ?

Urban Development Minister (Sh. A.C. Chaudhary): No, Sir.

श्री धर्मवीरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि (विघ्न) इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है अगर हम सारा काम एक ही डिपार्टमैंट को ट्रांसफर कर दें। नम्बर दो अगर यह ट्रांसफर हो जाती है तो हमारे सारे काम एक ही एजैंसी के नीचे आ जाते हैं और हमें हरेक के आगे रिक्वैस्ट नहीं करना पड़ेगी। यह भी एक फैक्ट है कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है।

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मैम्बर की चिन्ता से भी परिचित हूँ और इस बात को महसूस करता हूँ कि सड्कों के मामले में जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है उससे लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं लेकिन मैं यह अर्ज कर दूं कि बाई एण्ड लार्ज हुड्डा, पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) और म्पूनिसिपल कारपोरेशन जो अभी मैल्टिंग स्टेज पर हैं उनके पास जो मशीनरी और स्टाफ है वह हम से बैटर है और जो आलरेडी सारी स्टेट का काम कर रहे हैं, वह अपने कार्य में दक्ष भी हैं, जो गुड्ज डिलिवर कर सकते हैं। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब गुड़गांव गए थे उस वक्त ऑनरेबल मैम्बर साहब ने भी और उनके साथ कुछ लोग भी थे उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से दो सड्कों के लिए बात की थी। उस बारे में मैं हाउस को

आगाह करना चाहूँगा और मेरे ऑनरेबल साथी इस बात पर खुश होंगे कि भले ही वह सड़क बी. एण्ड आर. की थी लेकिन उनकी इम्पोटैंस को देख कर और अपने साथी की ईगरनैस को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और हरियाणा में एकमात्र पहली बार सीमैंट कंक्रीट की रोड्ज गुड़गांव में बी० एण्ड आर० के होते हुए भी हमने अपने पार्ट पर ली हैं। जो सड़कें हैं, एक तो रेलवे रोड वाया माता मसानी रोड है जो कि 1.6 किलो मीटर है उस पर छ करोड़ 80 लाख 43 हजार रुपये खर्च होंगे और दूसरी सड़क रेलवे स्टेशन रोड है जिसकी वाईडनिंग एण्ड स्ट्रैंग्थनिंग की जानी है। यह सड़क तकरीबन 1.8 किलोमीटर है और उस सड़क पर 10 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च आएगा। उसके लिए हमने ऑलरैडी टैंडर भी कर दिया है और नैगोसिएशन के बाद वर्क्स आर्डर भी हमने दे दिया है। स्पीकर सर, मेरा ख्याल है कि सैशन के बाद मैं उसको खुद चौक करने के लिए भी जाऊंगा।

श्री धर्मबीरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसको ये परमानैंटली एक बार ट्रांसफर क्यों नहीं करते हैं इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या हे? (विघ्न)

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमने इसके लिए 19 करोड़ रुपये दे दिये हैं। मैं अब भी कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि हम सबकी एनाजाईटी यह होनी चाहिए कि हमें सिविल एमिनिटीज मिलें क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरैडी उन विभागों के चार्ज में हैं

और ऑलरैडी वे इनको देख रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सखावत कहूँगा कि सब एमिनिटीज एक डिपार्टमैंट की लायब्लिटी है। हमारी सारी स्टेट में पब्लिक हैल्थ का काम तथा वाटर सीवरेज का जो काम है वह पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट का है। रोड् ज का काम पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) कर रहा है और जहां हुड्डा की कॉलोनीज हैं वहां हुड्डा ही कर रहा है। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूँगा कि हम एक्का लायब्लिटी लेने के बजाए सिविक फण्ड्ज लोगों को और सुविधाएं देने में लगाएं इस बात का चिन्तन भी हम सब को करना चाहिए।

श्री अमीर चन्द मक्कडः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुछ सड़कें नगरपालिका की लिमिट में हें, कुछ मार्किटिंग बोर्ड की लिमिट में हैं और कुछ बी० एण्ड आर० की लिमिट में हैं। इसमें हमेशा यही झगड़ा रहता है कि कौन सी सड़क कौन बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक श्मशानघाट की सड़क है और उसको बनाने के लिए भी 2 साल से झगड़ा चल रहा है कि इसको कौन बनाएगा। क्या मंत्री जी हमारे यहां पर श्मशानघाट की सड़क को बनवाने का कष्ट करेंगे?

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, नार्मल कोर्स में एक तो 12 फुट की और दूसरे 18 फुट की सड़क होती है। जो सड़क बी० एण्ड आर० की है उसको वे ही बनाएंगे और जो हमारी है उसको हम ही बनावाएगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कल ही मंत्री जी ने पूरे

प्रदेश का खाका यहां पर पढ़ कर सुनाया था कि कितनी सड़कें बन गई हें और कितनी सड़कें बननी हैं। सर, 5 हजार किलोमीटर सड़कें रिपेयर होने से रहती हैं और हो सकता है इनकी श्मशानघाट वाली सड़क भी उसी में आती हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बी० एण्ड आर० से निवेदन करूंगा कि इनके यहां पर श्मशानघाट की सड़क को प्रायोरिटी पर बनवाएं।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में पांच सड़कें ऐसी हैं जो हुड्डा ने ली

श्री अध्यक्षः यह प्रश्न लोकल बॉडीज विभाग का है जबकि आप हुड्डा की बात कर रहे हैं।

Sewerage System in Dadri Town

***1106. Maj. Nirpender Singh Sangwan :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that the existing sewerage lines of Dadri town are badly chocked with silt over the last many years; if so, the time by which the cleaning and up-gradation of the said system is likely to be completed; and

(b) the time by which the ongoing work of sewerage system throughout the city is likely to be completed ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, Sir. The overall sewerage system of Dadri Town is working properly except silting problems in some

pockets where the work of desilting with bucket type Sewer Cleaning Machine is in progress and this problem will be set right before coming monsoon. The work of cleaning the Sewerage System is in progress and will be completed by June, 2009. There is no requirement of upgrading the Sewerage System in the old town at present.

(b) On-going works of Sewerage System in the various colonies where the works have been taken up during 2008-09 are likely to be completed by March, 2010.

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमने 16 शहरों को लिया है। उनमें से 25 करोड़ रुपए की राशि दादरी के लिए अलग से निर्धारित की है। हमने मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर इसमें छोटे शहरों को लिया है। हमने काफी पैसा दादरी में सीवरेज और ड्रिकिंग वाटर के लिए अलाट किया है। जब भी वह पैसा आ जाएगा तब दादरी में आऊटर, इनर, ओल्ड टाऊन और जो भी न्यू कालोनिज हैं उन सबकी प्रोब्लम हल हो जाएगी।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो इन्फर्मेशन इनके अधिकारियों ने इनको दी है वह पूरी तरह से सही नहीं है। जो इन्होंने कहा है कि ओवर आल सिस्टम काम कर रहा है उस बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि काम तो कर रहा है लेकिन कई जगहों पर वह बिल्कुल ही चोक ? हो गया है। सर, वह सिस्टम एक साल से चोक्ड है। इन्होंने कहा है कि सीवरेज

सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। सर, कई जगहों पर 8 इंच की पाईप्स और कई जगहों पर 10 इंच की पाईप्स हैं और चोक्ड हैं। मैं पिछले कई साल से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वे पाईप्स खुली नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि इन पाईप्स को अपग्रेड करके नई पाईप्स डालने का काम करवाएं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, मेरे काबिल दोस्त की बात बिल्कुल वाजिब है। इनके शहर में रेलवे रोड है, इसके इलावा कोसली रोड, मुथडी रोड, रविदास बस्ती, गांधी नगर, झज्जर घाटी और झारू सिंह चौक के जो एरिए हैं वहां पर सिल्ट आई हुई है। पिछले साल बाढ़ आने की वजह सें वहां पर स्टार्म वाटर के साथ सिल्ट और दूसरे मैटिरियल सिवरेज में चले गए थे। जिसकी वजह से वे चोक्ड हैं। उसे हम बकेट टाईप सीवर क्लीनिंग मशीन से क्लीन करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने हमें कह दिया है और हम सुपर सकर मशीनें फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से खरीदने जा रहे हैं। इनमें से एक मशीन हम भिवानी, हिसार और दादरी के एरिए में परमानैटली स्टेशन्ड करने वाले हैं ताकि जो भी समस्या भिवानी या दादरी में आए तो हम वहां पर मशीन से कलिनिग करवा दें, यह मेरा इनको आश्वासन है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1178

(इस समय माननीय सदस्य श्री सोमवीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

ITI at Kalayat

***1208. Smt. Geeta Bhukal :** Will the Industrial Training & Vocational Education Minister be pleased to state :-

(a) the time by which the construction work of I.T.I. at Kalayat will be started; and

(b) whether the year 2008 was declared education year by the Government; if so, the number of I.T.I.'s that havebeen opened during the said year ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री एसी. चौधरी): श्रीमान जी,

(क) आई०टी०आई० कलायत के लिये भवन निर्माण का निर्माण कार्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाने उपरान्त शुरू किया जा सकता है। इस स्थिति में समय सीमा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(ख) हां, वर्ष 2008 शिक्षा वर्ष घोषित किया गया था। इस वर्ष के दौरान 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं।

Smt. Geeta Bhukal : Speaker Sir, it is for the information of the Hon'ble Minister that this announcement was made by the Hon'ble Chief Minister on 26th October, 2006 and 7.5 acres of land was given by the Municipal Committee to the Technical Education Department to open an I.T.I. there. Around an amount of Rs. 1.00 crore for this land had been paid to the Municipal Committee, Kalayat, which remained in the account of Municipal Committee Kalayat for one year.

Now, we have received a letter from the Technical Education Department that this land is non-feasible. Sir, I would like to say that when once this land has been declared as feasible by the Hon'ble Minister then how the department can say that this land is non-feasible ? Now, they are asking for another land. It is not the duty of the M.L.A. only hut it is also the duty of the officers of this department to arrange land for this purpose. Kalayat is declared as educationally backward area. I think these types of announcements should be taken very seriously. The other thing is that in case this I.T.I. does not start now, classes for the I.T.I. Kalayat should be started in the I.T.I. Kaithal or in the I.T.I. Narwana.

Shri A.C. Chaudhary : Speaker Sir, I appreciate the anxiety ofthe Hon'ble Member but we have to go by law alone. Be that this was an announcement made by the Hon'ble Chief Minister because this is the only ground where by the entire issue was taken in hand. The land so-allocated in Kalayat was a part of a pond and the moment this was transferred to us, just offered to us, we gave approval to the Municipal Committee. But the moment we got technical report as to non-viability of the land, we immediately withheld the sanction and directed the Deputy Commissioner concerned to give us an alternate land. **I** quite concede that this is not the entirely business of an MLA but we are also doing our job fully-well. We had already written a letter to Deputy Commissioner and a reminder was send only on 16th of this month that he should give us land. Prior to that also we were not slumbering over this issue. We had been following it and the Hon'ble Member will be quite convinced that the moment this was rejected, we asked for alternate land and the land was also suggested in

village Pinjupura and we directed the Municipal Committee and Deputy Commissioner to get us a resolution from the concerned Panchayat. As yet, we have to get it. The moment we get it, we will see that this is taken up.

Smt. Geeta Bhukal : Speaker Sir, actually the new land proposal has already been sent to the department. So, it is my personal request as the Government is doing too much for the technical education and especially for the backward area of Kalayat, new courses may be started as early as possible. This is my personal request and for part (b) of my question, only 27 numbers of I.T.Is have been shown in the list. I.T.Is opened in the other areas also should be listed in the list.

Shri A.C. Chadhary : Speaker Sir, quite conceived. As MLAs, we are part of a fraternity and we are supposed to see the interest of each other and that's why I am committed, my Government is committed. We will see that the moment we get the proposal, we will put it on priority.

ताराकिंत प्रश्न संख्या 1054

(इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Un regularized Colonies at Karnal

***1197. Sint. Sumita Singh :** Will the Urban Lacal Bodies Minister be pleased to state the number of such unregularized colonies contiguous to National Highway and HUDA in Karnal where the facilities of drinking water,

electricity, sewerage, roads and drains etc. have been completed together with the reasons for which these colonies have not been regularized ?

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : There are 7 unregularized colonies identified by Director, Town and Country Planning, contiguous to National Highway and HUDA in Karnal. These colonies have not been regularized on account of CWP No. 1006 of 2007 and 17002 of 2006 as the matter is sub-judice. Out of 7 colonies, only one colony namely Dayanand colony adjoining Sector 12, Part-II enjoys all the facilities such as Puccka road, water supply, sewerage, drainage and electricity. However, all these seven colonies have the facility of electricity,

10.00 बजे

श्री अध्यक्षः इसमें लिखा है जो माननीय सदस्या ने पूछा है कि these colonies have not been regularized और इसके रीजंज क्या हैं?

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है कि यह केस सब–जूडिस है। कोर्ट में केस चल रहा है। पिछले पूरे हफ्ते में अलग–अलग दिनों में इस मांग के बारे में पूछा गया है उनकी मैंने पूरी डिटेल बताई है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस केस में स्टे दे रखा है।

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी सै जानना चाहती हूं कि ऐसी अनअथोराइज्ड

कालोनीज डिवैलप होने के क्या कारण हैं। क्यों ऐसी कालोनीज डिवैलप होती हैं? दूसरे जिन आफीसर्ज के कारण ऐसी कालोनीज डिवैलप होती हैं चाहे म्युनिसिपल कमेटी के हैं या टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट के अफसर हैं क्या उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया? अगर एक अनअथोराइज कालोनी में आप सभी सिविक अमैनिटीज दे देंगे तो बाकी कालोनीज के लिए क्या कर रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहूँगी कि फ्यूचर में आप इसके रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं ताकि ऐसी कालोनीज डिवैलप न हों।

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी ही सीरियस समस्या है क्योंकि आज की प्रौग्रेसिव स्टेट के आकड़े अगर आप देखेंगे तो आप सहमत होंगे कि शहरों में इण्डस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है और उनकी फिग्गर्ज रोजाना मेरे कई विधायक साथी व मेरे कैबिनेट कुलीग्ज यहां पर दे रहे हैं। ज्यों ज्यों इण्डस्ट्रीज पनपती हैं, मजदूर फैक्ट्रीज में काम करते हैं और डिफरैंट आर्गेनाइजेशज में लगते हैं वे शहरों के अंदर के हिस्सों में मकान नहीं ले पाते क्योंकि मकानों के इतने ज्यादा किराए दे पाने में वे सक्षम नहीं होते और फलस्वरूप मशरूमी ग्रोथ शहरों के बाहर झुग्गियों के रूप में, हटमैंट के रूप में और स्लम्स के रूप में उभर रही है। इस समस्या के बारे में जैसे आदरणीय बहन जी ने सवाल किया हे उसी तरीके से हम सीरियसली लेते हैं तो यह सारी बात हमारे अन्य

एम०एल०ए० साथियों पर आ जाएगी। जिन–जिन के एरिया में से हम आदमियों को उठाने की कोशिश करेंगे या फिर जिन एरियाज में भी झुग्गी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह बात मानवता के आधार पर गलत होगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्या का जो सवाल है वह यह है कि जब अनप्लाड ग्रोथ हो रही है उसमें वाटर कनैक्शज दिए जा रहे है, बिजली के कनैक्शन भी दिये जा रहे हैं उसमें वोटर कार्ड पो बनाए जा रहे हैं और उनसे हाउस टैक्स भी लिया जा रहा है तो ये पूछना चाहती हैं कि जो अनप्लांड तरीके से ग्रोथ हो रही है तो क्या वह आफिसर्ज की नॉलेज में होती है या इसके लिए कोई ऐसा ऐक्शन खान बनेगा कि कुछ नया बने तो उसके लिए ये रिक्यायरमैंट हैं, ये कडीशज हैं, ये क्राइटेरिया हैं और उस हिसाब से ग्रोथ हो, ये पूछना चाहती हें।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो जितनी भी जो कालोनीज हैं जौ सो–काल्ड अनएप्रूव्ड कालोनीज होती हैं उनमें लोग रहते हैं, वे भी हमारी लायबिलिटीज हैं और वे डिफरैंट टैक्सिज भी देते हैं व कमेटी, कार्पोरेशन, असैंबली व पार्लियामैंट के लिए वो लोग वोट भी डालते हैं लेकिन हम कानून से बंधे हैं। जब अप्रवल के बगैर लोग मकान बना देते हैं। (विघन)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्या पूछ रही हैं कि ऐसे मकानों को बनते समय क्यों नहीं रोका जाता है और जो आफिसर्ज इस काम के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कोई ऐक्शन लिया जाता है?

श्री बलवंत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एडमिट तो कर रहे हैं कि वोट के कारण हम नहीं करा सकते। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें एम०एल०ए० साहेबान का दबाव आयेगा।

श्री ए०सी० चौधरीः सढौरा जी, आप इतने पढ़े–लिखे नहीं हो कि मेरी बात को अपने मुँह मे डाल सके।

श्री अध्यक्षः मिस्टर सढौरा, कोई गरीब आदमी है या लेबरर है या कोई किसान है जो गांव से आकर अपने बच्चों को कहीं न कहीं पढ़ाना चाहता है, कहीं तो वे रहेंगे ही। लेकिन उसके लिए certain plain of action होना चाहिए कि इसमें अगर कहीं पर भी कोई मकान बनेगा या बसेगा तो उसके लिए प्लान होनी चाहिए।

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। इस बात को देखते हुए सबसे पहले मैं आदरणीय सदस्य की उस टिप्पणी को खण्डित करूंगा कि यह एक कन्टीन्यूस प्रोसैस है और हर सरकार के वक्त से यह चौनल में आते रहे हैं बनते रहे हैं। कालोनीजे बनती रही हैं और किसी एक सरकार के समय में

या किसी एक व्यक्ति के समय में नहीं बनी हैं। मैंने यह कहा था कि अगर हम इन कालोनिज को डिमोलिश करने के लिए ड्रास्टिक स्टैप्स लेते हैं तो यह एम०एल०एज० साहेबान को परेशान करेगा। स्पीकर सर, जहां तक आपने इस बारे में सम्मराईज किया है उसके लिए मेरी सरकार चिन्तित है। कल शाम को ही हमारे अधिकारियों की मॉटिग हुई है कि किस तरीके से अर्बन लोकल बॉडिज को इम्पावर किया जाए, जिससे कोर्ट के स्टे आर्डर को वैकेट करवा लिया जाए। मैं हाउस की जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट ने बड़े अजीब तरीके से स्टे आर्डर किये हैं कि 'अगर ये अनअप्रूवड कालोनीज बगैर अथोरिटी के पास की गई हैं या अथोरिटी द्वारा पास की गई हैं तो उनको अगर कोर्ट इजाजत दे तब ही उनको एप्रूवड किया जाए। स्पीकर सर, फिर ये अनअप्रूवड अथोराईजेशन कैसे हुई? लेकिन अब हमने जो कमेटी बनाई है जिसमें हुडा और अर्बन लोकल बॉडिज के सीनियर अधिकारी लिए हैं और वे इस बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका कोई कानूनी तरीका निकाल सकते हैं। इसके लिए चाहे हमें रूल्ज में भी एमेंडमैंट क्यों न करनी पड़े और दूसरे एडीशनल स्टैप्स लेने पड़े, हम लेंगे ताकि हम लोगों को राहत दे सकें लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आदरणीय सदस्य इस बात को मन में रख लें कि जहां हमें गलियां, नालियां, सड़कें, सीवरेज और पानी के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी तो उन कालोनिज के मामले में कोई डिमाण्ड भी न करे क्योंकि वहां पर संभव नहीं होगा लेकिन जल्दी से जल्दी उसके लिए हम कोई न कोई वे–आऊट निकाल लेंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने इस बारे में विस्तार से बता दिया है। मैं सदन की जानकारी के लिए एक जानकारी और देना चाहूँगा। यह बात पिछले सत्र में भी आपके नोटिस में लाए थे जिस दिन पिछले चुनाव के लिए नोटिफिकेशन हुई उसी दिन पिछली सरकार द्वारा 1267 के करीब अन–अप्रूवड कालोनिज को अप्रूवड करने के लिए एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर जारी किया गया था। जबकि माननीय सदस्य सढौरा जी अब कह रहे थे कि इन 'अन–अथोराईज्ड कालोनिज को क्यों एथोराईज कर रहे हैं। उन कालोनिज के लिए कोई पैसा नहीं, कोई वित्तीय ऐलोकेशन की व्यवस्था नहीं, कोई बजट नहीं। जब वर्तमान सरकार ने सत्ता संभाली तो हमने इस बात को मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाया तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस आदेश को देखा और कहा कि चाहे आर्डर किसी ने भी इश्यू किया हो। सरकार हर कालोनी में सुविधा देने के लिए बाध्य हैं और यह सरकार की जिम्मेवारी है। यही कारण है कि पिछले चार साल में उन अधिकतर कालोनिज को सरकार ने सीवरेज, पीने का पानी, सड़क, बिजली की लाईन, बिजली के खम्भे और दूसरी बेसिक एमेनिटीज पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास किया है। अब इस बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। गांव का आदमी कहां जायेगा? गांव का आदमी रोजी–रोटी से अपना पेट भरने के लिए और अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए गाँव से शहर में आता है और कई बार गाँव में ही अपनी शहर के साथ लगती खेत की जमीन में

ही अपना मकान बना लेता है। हमारा रवैया सहानुभूतिपूर्ण है। मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अनुरोध किया था। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने एक बैठक भी बुलाई है। इस बारे में मंत्री जी बोल चुके हैं। विपक्षी पार्टी के एक ऐसे एलीमेंट ने जिसने पहले हांसी बुटाना नहर के बनने के लिए कोर्ट में चुनौती दिलवाई, उसी प्रकार का एक और एलीमेंट अब फिर कोर्ट में चला गया। वहां पर कहा कि हरियाणा में जो अन–एथोराईज्ड कालोनीज हें वे रेगूलराईज नहीं होनी चाहिए। जब ये भाई विपक्ष की तरफ बैठ जाते हैं तो इनको पीड़ा होती है कि लोगों का भला क्यों हो रहा है। पैंशन क्यों दी जा रही है, नहर क्यों बनाई जा रही है, कालोनीज को क्यों रेगूलराईज किया जा रहा है। ये लोग हरियाणा के लोगों का भला नहीं होने देना चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी इस बारे में हल अवश्य निकालेंगे, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा। कोई भी हल निकलेगा वह कोर्ट के माध्यम से निकलेगा। हम इसका हल अवश्य निकलवायेंगे।

डॉ० सुशील इन्दौराः सर, माननीय संसदीय मंत्री हमारे नेता का नाम लै रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने इनका नाम ही नहीं लिया। डॉ० इन्दोरा तो बगैर नाम लिए ही खड़े हो जाते हैं।

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा था बल्कि मंत्री जी ने खुद यह माना था कि एम०एल०एज० पर दबाव आयेगा इसलिए हम कालोनीज को तोड़ नहीं सकते। जो कालोनियां हमने रिकमैंड की थी, पूरे डाटा के साथ, पूरे प्रोजैक्ट के साथ उनको एप्रूव किया था। इस सरकार ने आते ही उनको खत्म किया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हम 200 गज का कोई प्लाट अपने बच्चों की शादी के लिए लेकर रख लेते थे लेकिन आज हम उनको बेच नहीं सकते क्योंकि 4 साल से रजिस्ट्रियां बंद है। यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी जमीन को बेच सकें। जो 200 गज का प्लाट किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए लिया था उसको आज वह अपनी जरूरीयात पूरी करने के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए न ही उसको बेच सकता है और न ही उसको गिरवी रख सकता है क्योंकि लगातार 4 सालों से रजिस्ट्रियां बन्द हैं और हमारे सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं।

श्री अध्यक्षः सढौरा जी, इसको इस प्रश्न से कोई रैलीवैंसी नहीं है।

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आन दी फ्लोर आफ दि हाउस कहा था कि हम ये कालोनियां तोड़ेंगे तो एम०एल०एज० को दिक्कत आएगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सढौरा जी गलत ब्यानी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने सारी कालोनियों को रैगुलराइज करने के लिए बजट में प्रावधान किया था। अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस की कमेटी बनवा दें जो यह बता देगी कि क्या सही है और क्या गलत है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई बजट में प्रोवीजन नहीं किया और न ही कोई नक्शा बनाया था। केवल चुनावी स्टंट के तौर पर इनके नेता ने आखिरी दिन एक आर्डर पास कर दिया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर ये खरे उतरने के लिए तैयार हैं तो हाउस की कमेटी बना दीजिए जो यह बता दे कि इन्होंने बजट एलोकेशन किया था या नहीं। वह कमेटी जिसको गलत ठहराए उसको सजा मिलें।

श्री बलवन्त सिंहः .....

श्री अध्यक्षः सढौरा जी, जो अब कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बलवंत जी फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं, इन्होंने जो कहा है कि हम नहीं तोड़ेंगे या तोड़ नहीं सकते क्योंकि एम०एल०ए० को सिरदर्दी होगी। यह इन्होंने गलत कहा है जबकि मैंने यह कहा है कि मैं एक सरकार की नहीं कहता बल्कि जब से हरियाणा बना है तब से पिछली सरकारों को अनअथोराज्ड कालोनियों को रैगुलर करने के

प्रौसैस में इंडस्टीज के साथ–साथ झुग्गी झोपड़ी निवेश भी विरासत में मिला है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जहां तक रजिस्ट्रियों की बात की है तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जमीन ली जाए तो उसका एक कानून है कि वह अपने तौर पर सी०एल०यू० करवा ले, उसके बाद उसका नक्शा दे दे और पास करवा ले इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात क्लीयर कर दूं कि हमने यह कभी नहीं कहा था कि हम तोड़ेंगे तो एम०एल०ए० की सिरदर्दी होगी। मैंने तो यह कहा था कि जो एम०एल०एज० बार–बार कहते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी क्यों बन रही है वे यह जरूर सोच लें कि कल लगी–झोपड़ी वाले इस बात को उनकी नैगेटिव सोच मानेंगे इसलिए यह सरकार प्रोग्रैसिव सरकार होने के नाते कमिटिड है कि आबादी के अंदर और शहर के अंदर बसने वाले मिलियन्ज और बिलियन्ज को जितनी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं उतनी फैसेलिटीज लगी–झोपड़ी वालों को देने के लिए भी हम कमिटिड हैं लेकिन हमारे हाथ कानून से बंधे हैं और जिस दिन हमें इस कानून से छुटकारा मिल जाएगा उस दिन यह इशू भी रेज करने का किसी को मौका नहीं देंगे।

श्री धर्मबीरः 'अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह प्रोग्रैशन जितनी होती है वह दो रीजन से होती है एक एजूकेशन और दूसरा एम्पलायमैंट से, न कि इंडस्टायलेशन से होती है। इन साथियों से मैं एक बात कहूंगा ये मेहरबानी करके नाराज न हों कि आज से 40 साल पहले हमने 4 कालोनियां रैगुलराइज करवाई

थी लेकिन चौटाला जी ने आते ही उन सभी कालोनियों को अनअथोराइज्ड कर दिया उनमें एक भिवानी इन्कलेव है और एक कालोनी चौटाला जी के पिता के नाम से देवी लाल कालोनी है। ये आप लोग नोट कर लें फिर आप कहेंगे कि हमने यह नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी सबमिशन यह है कि चौधरी साहब बार–बार कह रहे हैं हमारे हाथ कानून से बंधे हैं। कानून हमने ही ठीक करना है और इसको ठीक करने कोई बाहर से तो नहीं आएगा। इस कानून में आप अमैंडमैंट लाइए और इसको ठीक करें। अध्यक्ष महोदय, 50–50 साल कलोनियों को बने हुए हो गए हैं, ये आज तक कह रहे हैं कि हम अनअथोराइज्ड कालोनियों को रैगुलर करने जा रहे हैं। बिजली उनके पास है, पानी उनके पास है लेकिन और कोई फैसिलिटीज नहीं है। कम से कम हमारे गुड़गांव में तो न सड़कें हैं और न सीवरेज हैं। हम इस बारे में कह– कह कर थक गए। हमारे यहां के लोग बेचारे डिवैल्पमैंट के लिए पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। आप जो भी रेट मुकर्रर करें चाहे म्युनिसिपल कमेटी के रेट हों और चाहे हुड्डा के रेट हो लेकिन मेहरबानी करके इस समस्या को टालो मत और इन अनअथोराइज्ड कालोनियों को रैगुलर करने में देर न करें। वोट तो आप ले लेते हो।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य की भावना का आदर करते हुए मैं कोई कहावत नहीं कहूँगा जो

मैंने लास्ट टाईम कही थी। उसको true perspective में न लेकर उन्होंने इसे पर्सनेलाइज कर दिया था।

श्री अध्यक्षः कहावत क्या थी?

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मेरे मुंह से निकल गया था कि little knowledge is a dangerous thing उसकी फिर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की और अगले दिन आपके समक्ष भी बात रखी थी जबकि उससे पहले मैंने पूरी तरह से उसका समाधान किया था। Never meant of insulting and injuring of his feelings. एक लफ्ज उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है तो मैंने मेरी नालेज के ऊपर थोड़ी बहुत बात कही थी। आज फिर वही बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और हमने आलरैडी मीटिंग भी होल्ड कर ली है और we are on job. कोई एक्ट में अमैंडमैंट करनी है या कोई ऐक्शन लेना हे जिससे समस्या का हल हो जाये इस बारे में हम पूरी तरह से सजग हैं। इसमें नई बात क्या कह रहे हैं यह तो मैं आलरेडी कह चुका हूँ।

Gramin RojgarGuarantee Yojana

***1142. Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) the yearwise details of total amount spent under the 'Gramin Rojgar Guarantee Yojana' in District Sirsa

during the period from April, 2006 till date;

(b) viilagewise amount made availabe by the Government during the period as referred to in para (a) above in Dabwali constituency under the above said scheme separately togetherwith details of work and amount spent thereon; and

(c) yearwise total number of persons who have got themselves registered under the said scheme in District Sirsa togetherwith the number of persons employed annually during the period as referred to in para (a) above ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The year-wise details of total amount spent under the NREGA in district Sirsa during the period from April 2006, till 31.12.2008 are as under :-

Sr. No.	Year Amount	spent (Rs. in Lac) under NREGA
1.	2006-07	2127.906
2.	2007-08	1734.473
3.	2008-09 (upto 31.12.2008)	1618.629

	Total	5481.008

(b) The details have been given in Annexure "A".

(c) Yearwise total number of persons who have got themselves registered under the said scheme in District Sirsa together with the number of persons employed annually during the period as referred to in para (a) above ?

Sr. No.	Name of Block	Total No. of persons Registered till date	Yearwise No. of persons employed		
			2006-07	2007-08	2008-09
1.	Baragudha	7931	4727	1857	1922
2.	Dabwali	12748	5368	2555	3044
3.	Ellenabad	8574	3594	2967	5241
4.	N.Chopta	11275	3127	4155	4139
5.	Odhan	4931	3077	1394	2881
6.	Rania	10900	5651	5881	4222
7.	Sirsa	9298	5969	3028	345

	Total	65657	31513	21837	21794

ANNEXURE 'A'

Detail of works taken up, amount made available and expenditure incurred under NREGA in Dabwali Constituency during 2006-07.

Sr. No. of village	Sr. No. of works	Name of Village	Name of Scheme	Amount made available the Gram Panchayat (Rs. in Lacs)	Amount spent in Rs. in Lacs
1	2	3	4	5	6
		Block Odhan			
1	1	Assir	Digging of Pond	1.760	1.760
	2	Assir	Dipping of pond near G/ghar	1.430	1.430
	3	Assir	Dipping of pond near School	2.990	2.990
	4	Assir	CC Street	1.820	1.820
			Sub Total	8.000	8.000
2	1	Chatha	Land Dev.	3.090	3.090

	2	Chatha	Digging Pond	3.550	3.550
	3	Chatha	Land dev. in water works	0.900	0.900
			Sub Total	7.540	7.540
3	1	Chukerian	Digging of Pond	2.990	2.990
	2	Chukerian	Digging of Pond	2.670	2.670
	3	Chukerian	Land Dev. near School	0.300	0.300
			Sub Total	5.960	5.960
4	1	Desu malkana	Digging of Pond	1.960	1.960
	2	Desu malkana	Digging of Pond	4.820	4.820
			Sub Total	6.780	6.780
5	1	Hassu	Digging of Pond	1.890	1.890
	2	Hassu	Land Dev.	4.670	4.670
	3	Hassu	6 nos CC Street	1.320	1.320
			Sub Total	7.880	7.880
6	1	Jagmalwali	Digging of Pond	2.770	2.770
	2	Jagmalwali	Digging of Pond	2.530	2330

	3	Jagmalwali	3 nos of CC Street in Bazigar Basti	1.860	1.860
			Sub Total	7.160	7.160
7	1	Jalalana	Digging of Pond	3.000	3.000
	2	Jalalana	Digging of Pond	4.440	4.440
	3	Jalalana	E/filling in Govt. Building	0.809	0.809
			Sub Total	8.249	8.249
8	1	Kalanwali village	Water Harvesting Pond	3.860	3.860
	2	Kalanwali village	Samlat land Dev.	1.150	1.150
	3	Kalanwal i village	CC Street	3.550	3.550
			Sub Total	8.560	8.560
9	1	Khokhar	Digging of Pond	0.620	0.620
	2	Khokhar	Land Dev.	3.710	3.710
			Sub Total	4.330	4.330
10	1	Makha	Land Dev.	5.760	5.760
11	1	Mithri	Cleaning Minor	0.070	0.070

	2	Mithri	Digging of Pond	3.530	3.530
			Sub Total	9.360	9.360
12	1	Norang	Digging of Pond	1.580	1.580
	2	Norang	Land Dev. (Kabristan)	3380	3380
	3	Norang	Land Dev. in P/Iand	1.810	1.810
	4	Norang	Mithu Singh to main road	0.840	0.840
			Sub Total	7.610	7.610
13	1	Pipli	Digging of Pond	3.900	3.900
	2	Pipli	Land Dev. Near WW	2.540	2.540
	3	Pipli	CC Street	1.300	1300
			Sub Total	7.740	7.740
14	1	Tappi	Digging of Pond	1.600	1.600
	2	Tappi	Land Dev. P/land	4.460	4.460
	3	Tappi	Digging of Pond (P/land)	2.920	2.920
	4	Tappi	2 nos CC Street	1250	1.250
			Sub Total	10.230	10.230

15	1	Tigri	Water Harvesting pond	2.680	2.680
	2	Tigri	Digging of Pond	4.990	4.990
	3	Tigri	CC Street	1280	1280
			Sub Total	8.950	8.950
		Block Dabwali			
16	1	Abubshahar	DisltingofMinor	0224	0224
	2	Abubshahar	Digging of pond	2.900	2.900
			Sub Total	3.124	3.124
17	1	Alikan	Digging of Pond	8.800	8.800
	2	Alikan	Land Develop	0200	0200
	3	Alikan	Dislting of Minor	0.160	0.160
			Sub Total	9.160	9.160
18	I	Asa Khera	Digging of Pond	1.800	1.800
	2	Asa Khera	Dislting of Minor	0.190	0.190
			Sub Total	1.990	1.990
19	1	Bharu Khera	Dislting of Minor	0.090	0.090
	2	Bharu	Digging of Pond	2.900	2.900

		Khera			
			Sub Total	2.990	2.990
20	1	Chakjalu	Digging of Pond	2.200	2.200
21	1	Chautala	Dislting of Minor	0.400	0.400
22	1	Diwan Khera	Land Develop	4.800	4.800
23	1.	Ganga	Land Develop	4500	4.500
	2	Ganga	Digging of Pond	1.400	1.400
	3	Ganga	Digging of Pond	2.000	2.000
	4	Ganga	Digging of Pond	2.000	2.000
	5	Ganga	Digging of Pond	L700	1.700
	6	Ganga	Digging of Pond	1.300	1.300
	7	Ganga	Digging of Pond	1200	1200
	8	Ganga	E/Filling in Road	7.300	7.300
			Sub Total	21.400	21.400
24	1	Gidder Khera	Land Develop	3.500	3.500
25	1	Goriwala	Digging of Pond	3.450	3.450
26	1	Habuana	Land Develop	1.700	1.700

27	1	Jandwala	Digging of Pond	6.500	6.500
		Bishnoian			
28	1	Jhuthi Khera	Digging of Pond	2.000	2.000
29	1	Jogewala	Digging of Pond	1.400	1.400
30	1	Khuiyan Malkana	Land Develop	8.000	8.000
	2	Khuiyan Malkana	Digging of Pond	2.000	2.000
			Sub Total	10.000	10.000
31	1	Lakhuana	Dishing of Minor	0260	0.260
	2	Lakhuana	Land Develop	1.300	1.300
			Sub Total	1.560	1.560
32	1	Larmbi	Land levelling	3.700	3.700
33	1	Lohgarh	Earth filling both side in khal	2.100	2.100
34	I	Mangiana	Land Develop	2.900	2.900
	2	Mangiana	Digging of Pond	2.400	2.400
	3	Mangiana	Matwal	0.350	0.350
			Sub Total	5.650	5.650

35	1	Masitan	Land Develop	9.000	9.000
	2	Masitan	Dislting of Minor	0.130	0.130
			Sub Total	9.130	9.130
36	1	Mathdadu	Digging of pond	4.300	4.300
	2	Mathdadu	Land Develop	5200	5200
			Sub Total	9.500	9.500
37	1	Modi	Digging of pond	6.100	6.100
38	1	Moonawali	Digging of pond	2.000	2.000
39	1	Moujgarh	Land Develop	14.500	14.500
	2	Moujgarh	Disiting of Minor	0.800	0.800
			Sub Total	15.300	15.300
40	1	Nillianwali	Land Develop	3.300	3.300
41	1	Panna	Land Develop	4.850	4.850
	2	Panna	Dishing of Minor	0.034	0.034
	3	Panna	Land Develop	2.500	2.500
			Sub Total	7.384	7.384
42	1	Panniwala Morikan	Land Develop	0.700	0.700
43	1	Panniwala	Dishing of Minor	0.028	0.028

		Ruldu			
	2	Panniwala Ruldu	Digging of Pond	1.000	1.000
			Sub Total	1.028	1.028
44	1	Phullo	Land Develop	2.400	2.400
	2	Phullo	Dislting of Pond	1.000	1.000
			Sub Total	3.400	3.400
45	1	Rajpura Majra	Land Develop	2.200	2.200
46	1	Sakta Khera	Dislting of Minor	0.150	0.150
	2	Sakta Khera	Digging of Pond	4.000	4.000
			Sub Total	4.150	4.150
47	1	Sawant Khera	Digging of Pond	1.385	1.385
48	1	Shergarh	Digging of Pond	1.520	1.520
	2	Shergarh	Land Develop	0.980	0.980
	3	Shergarh	Land Develop	0.810	0.810
	4	Shergarh	Digging of Pond	1.500	1.500
	5	Shergarh	Digging of Pond	2.700	2.700
			Sub Total	7.510	7.510

49	1	Sukhera Khera	Dislting of Minor	0.100	0.100
50	1	Teja Khera	Digging of Pond	2.400	2.400
	2	Teja Khera	Dislting of Minor	0.047	0.047
			Sub Total	2.447	2.447
			Grand Total	277.367	277.367

Detail of works taken up, amount made available and expenditure incurred under NREGS in Dabwali Constituency during 2007-08.

Sr. No. of village	Sr. of works	No. Name of Village	Name of Scheme	Amount made available to the Gram Panchayat (Rs. in lacs)	Amount spent in Rs. in Lacs
1	2	3	4	5	6
		Block Odhan			
1	1	Assir	Land Dev.	0.855	0.855
	2	Assir	Land Dev.	0.615	0.615

	3	Assir	Earth Work for Plantation in Shamshan Land	0.554	0.554
			Sub Total	2.024	2.024
2	1	Chatha	Pts Land Dev.	2.025	2.025
	2	Chatha	Land Dev.	2.616	2.616
	3	Chatha	Deepening of Pond Near Community Centre	0.792	0.792
	4	Chatha	Cost. of Cow Ghat, CC Street	1.482	1.482
	5	Chatha	Cost. of Cow Ghat, CC Street	0272	0.272
			Sub Total	7.187	7.187
3	1	Chukerian	Digging of Pond Near Mini Bank	3.450	3.450
	2	Chukerian	Land Dev. Mud B/Wall of Panchayat Land	0.790	0.790
	3	Chukerian	Land Dev. Mud B/Wall of Panchayat Land	0.790	0.790

	4	Chukerian	Minor Irrigation-Laying of Pipeline for Pond from Canal to Primary School	0.775	0.775
	5	Chukerian	Pond pipe line	0.775	0.775
			Sub Total	6.580	6.580
4	1	Desu malkana	Rural Connectivity	0.167	0.167
	2	Desu malkana	Land Dev.	0.517	0.517
	3	Desu malkana	Deepening of Pond Near H/o Sh. Jangir Singh	1.490	1.490
	4	Desu malkana	Land Dev., Shamshan	1210	1210
			Sub Total	3.384	3.384
5	1	Hassu	Digging of Pond	0.474	0.474
	2	Hassu	Desilting of Channel	1520	1.520
	3	Hassu	Land Dev.	1.860	1.860
	4	Hassu	Minor Irrigation work-Strengthening of	2.780	2.780

			Berms		
	5	Hassu	Land Dev. Panchayat Land M.No. 91 K.No. 7,6,14,15/1	1.860	1.860
	6	Hassu	Land Dev. Panchayat Land M.No. 68 K.No. 13,16/1/2, 23 East Side	4.640	2320
	7	Hassu	RCC Pipe	1.706	1.706
			Sub Total	14.840	12.520
6	1	Jagmalwali	CC Street	0.477	0A77
7	1	Jalalana	Digging of Pond	4.960	4.960
	2	Jalalana	CC Street	3.149	3.149
			Sub Total	8.109e	8.109
8	1	Kalanwali village	Pts Land Dev.	0.833	0.833
	2	Kalanwali village	Digging of Pond	5.810	5.810
			Sub Total	6.643	6.643
9	1	Khokhar	Land Dev. Panchayat Land	0.685	0.685

			M.No. 140 K.No. 16, 17		
10	1	Mithri	Digging of Pond Near G.T. Road	4.990	4.990
11	1	Naurang	Land Dev. Panchayat Land Chatha Wala Rasta M.No. 18 K.No. 12, 13	2.380	2380
	2	Naurang	Land Dev. Panchayat Land Bhagua Wala Rasta. M.No. 2 K.No. 19,20,21,22,25/1	2.850	2.850
			Sub Total	5.230	5.230
12	1	Pipli	Digging of Pond	3.070	3.070
	2	Pipli	Land Dev. Near Peer Khera	0.231	0.231
			Sub Total	3.301	3.301
13	1	Tappi	Desilting of Pond	1.988	1.988
	2	Tappi	Land Dev.	2.045	2.045
	3	Tappi	CC Street	1 777	1.222

			Sub Total	5.255	5.255
14	1	Tigri	Pts. Land Dev.	1.073	1.073
	2	Tigri	Pts. Land Dev.	2274	2274
	3	Tigri	Minor Irrigation-E/Filling on both side of W/Course Mogga No. (33000-R)	0.943	0.943
	4	Tigri	Minor Irrigation-E/Filling both side Mogga No. (2750-R)	0.968	0.968
	5	Tigri	CC Street	1.642	1.642
			Sub Total	6.900	6.900
		Block Dabwali			
15	1	Abubshahar	Renovation. of Existing Water	0.980	0.980
	2	Abubshahar	Earth filling in Sadak	3.100	3.100
			Sub Total	4.080	4.080
16	1	Alikan	Land Dev.	2.890	2.890

	2	Alikan	Land Dev.	4.840	4.840
	3	Alikan	CC Street	5.080	5.080
			Sub Total	12.810	12.810
17	1	Asha Khera	Digging of Pond	1.500	1.500
	2	Asha Khera	Pay of Street	1.505	1.505
			Sub Total	3.005	3.005
18	1	Bharu Khera	Digging of Pond	3.660	3.660
	2	Bharu Khera	Land Dev.	2.600	2.600
	3	Bharu Khera	Land Dev.	2.300	2300
			Sub Total	8.560	8.560
19	1	Chakjalu	Deeping and Desilting of Pond	0.590	0.590
	2	Chakjalu	Land Dev.	0.460	0.460
	3	Chakjalu	Land Dev.	2.700	2.700
			Sub Total	3.750	3.750
20	1	Chautala	Digging of Pond	3.800	3.800
	2	Chautala	Land Dev.	4.000	4.000

	3	Chautala	Land Dev./Mud Wall	0.390	0390
			Sub Total	8.190	8.190
21	1	Dabwali Viilage	Digging of Pond	2.320	2.320
	1	Dabwali Viilage	Const of Mud Wall	0.400	0.400
			Sub Total	2.720	2.720
22	1	Desujodha	Digging of Pond	2.400	2.400
23	1	Diwan Khera	Digging of Pond	1.300	1300
	2	Diwan Khera	CC Street	2.850	2.850
			Sub Total	4.150	4.150
24	1	Ganga	CC Phirni	11.590	11.590
	2	Ganga	Earth filling in Rasta	2.090	2.090
			Sub Total	13.680	13.680
25	1	Gidder Khera	Land Development	0.400	0.400
	2	Gidder Khera	CC Street	0.440	0.440

			Sub Total	0.840	0.840
26	1	Goriwala	Land Dev.	1.500	1.500
	2	Goriwala	CC Street	4.150	4.150
			Sub Total	5.650	5.650
27	1	Jandwala Bishnoian	Land Dev.	0.600	0.600
28	1	Jogewala	Land Dev.	4.300	4300
		Jogewala	Land Dev. and Mud Wall	1.000	1.000
			Sub Total	5.300	5.300
29	1	Jottanwali	Strengthening of berms of Canal	2.100	1.400
	2	Jottanwali	Excavation of Pipe line Flood Water	0.100	0.100
			Sub Total	2.200	2.200
30	1	Jutti Khera	Land Dev.	1.200	1.200
31	1	Khuiyan Malkana	Digging of Pond	1.700	1.700
	2	Khuiyan Malkana	Land Dev.	0.540	0.540

	3	Khuiyan Malkana	Land Dev. Panchayat Land	1.500	1.500
	4	Khuiyan Malkana	CC Phirni	8.700	8.700
			Sub Total	12.440	12.440
32	1	Lakhuana	Land Dev.	1.000	1.000
33	1	Lambi	Cleaning of Waterworks	1.000	1.000
	2	Lambi	Land Dev.	1300	1300
	3	Lambi	Pay of Street	2.040	2.040
			Sub Total	4.340	4.340
34	1	Lohgarh	Digging of Pond	2.700	2.700
	2	Lohgarh	Road Connectivity	0200	0.200
			Sub Total	2.900	2.900
35	1	Mangeana	Digging of Pond	2.000	2.000
	2	Mangeana	Earthwork for Plantation	0.500	0.500
	3	Mangeana	CC Street	8225	8225
			Sub Total	10.725	10.725
36	1	Masitan	Levelling and	0.742	0.742

			Plantation		
	2	Masitan	CC Street	5.550	5.550
	3	Masitan	E/Filling in Rasta	0.700	0.700
			Sub Total	6.992	6.992
37	1	Mathdadu	Land Dev.	1.400	1.400
	2	Mathdadu	Land Dev.	1.700	1.700
	3	Mathdadu	Pay. of Street	2.030	2.030
			Sub Total	5.130	5.130
38	1	Modi	Minor Irrigation Strengthing of Berms	3.020	3.020
	2	Modi	Strengthing of Berms	0.410	0.410
	3	Modi	Land Dev. SC Land	0.866	0.866
			Sub Total	4.296	4.296
39	1	Moujgarh	Land Dev.	14.100	14.100
	2	Moujgarh	Land Development	1.850	1.850
	3	Moujgarh	CC Street	3.180	3.180

			Sub Total	19.130	19.130
40	I	Munnawali	Digging of Pond	1.900	1.900
	2	Munnawali	Earth work for Plantation	1.400	1.400
	3	Munnawali	Strengthening of berms of Canal	0.760	0.760
	4	Munnawali	Deeping of Pond Near Gurudwara Sahib	2.000	2.000
	5	Munnawali	Land Development	2.000	2.000
	6	Munnawali	Land Dev.	0.470	0.470
			Sub Total	8.530	8.530
41	1	Panna	Land Dev. Mud Wall	0200	0200
	2	Panna	CC Street	2.660	2.660
			Sub Total	2.860	2.860
42	1	Panniwala Morikan	Digging of Pond	2.000	2.000
	2	Panniwala Morikan	Const. Mud Wall	0.200	0200

			Sub Total	2.200	2.200
43	1	Panniwala Ruldu	Land Dev.	1.500	1.500
	2	Panniwala Ruldu	Land Dev.	2.000	2.000
			Sub Total	3.500	3.500
44	1	Phullo	Digging of Pond	1.100	1.100
	2	Phullo	Land Development	1300	1.300
			Sub Total	2.400	2.400
45	1	Rajpura Majra	Minor Irrigation Strengthing of Berms	1.200	1.200
46	1	Sakta Khera	Pavement of Street	3200	3200
	2	Sakta Khera	Land Dev.	3300	3.300
			Sub Total	6.500	6.500
47	1	Sawant Khera	Land Dev.	1.000	1.000
48	1	Shergarh	Water Channel	2.700	2.700
	2	Shergarh	Const. of Khal	2300	2.300

	3	Shergarh	Land Dev.	1.500	1.500
	4	Shergarh	Land Dev.	2.060	2.060
	5	Shergarh	CC Street	6.640	6.640
			Sub Total	15.200	15.200
49	1	Sukhera Khera	Land Dev.	4.000	4.000
	2	Sukhera Khera	Land Dev.	0.709	0.709
	3	Sukhera Khera	Land Dev.	2225	2225
			Sub Total	6.934	6.934
50	1	Teja Khera	Minor Irrigation and Strengthening of Berms	0.150	0.150
	2	Teja Khera	Land Dev.	0.600	0.600
	3	Teja Khera	Land Dev.	1500	1.500
	4	Teja Khera	Land Dev.	0.780	0.780
	5	Teja Khera	CC Street	1.150	1.150
			Sub Total	4.180	4.180
			Grand Total		273.877

			276.197		

Detail of works taken up, amount made available and expenditure incurred under NREGS in Dabwali Constituency during 2008-09 (upto Dec., 08)

Sr. No.	Name of Village	Name of Scheme	Funds released to Gram Panchayats (Rs. in Lac)	Total Expendi-ture
1	2	3	4	5
		Block Odhan		
1	Asir	Land Dev. Panchayat Land M.No. 44 K.No. 9/2, 10. 11/2, 12	3.130	3.130
	Asir	Minor Irrigation Deweeding of Pana Minor Burji No. 11626 to 34500	0.125	0.125
		Sub Total	3.255	3.255

2	Chatha	Deepening of Pond near Community Centre	1.584	1.584
	Chatha	E/Work of Plantation in Shamshanghat Kashar No. 78	2.620	2.620
	Chatha	C.C. Street from, H/o Sukhmander Singh to H/o Bhadar Singh Chowkidar	1.130	1.130
	Chatha	C.C. Street from Rama Mandi Rasta to H/o Jangir Singh	0.550	0.550
	Chatha	Laying of Pipe Line RCC Pipe for Village Pond	0.810	0.810
		Sub Total	6.694	6.694
3	Chukeria	Drought Proofing Earth work of Plantation Shamshan Ghat (Kabrestan)	1.800	1.800

	Chukeria	Land Dev. Panchayat land M.No. 5 K.No. 5,6,15	3.680.	3.680
	Chukeria	Land Dev. & Mud Wall	0.790	0.790
		Sub Total	6.270	6.270
4	Desu Malkana	Digging of Pond near Purana Gurudwara	2.960	2.960
	Desu Malkana	Minor Irrigation Deweeding of Pana Minor Burji No. 0 to 11625	0.080	0.080
	Desu Malkana	Deepening of Pond	2.980	1.490
	Desu Malkana	P/ment of Street	0.167	0.167
	Desu Malkana	Land Dev.	1.305	1305
	Desu Malkana	Land Dev. Shamshan Bhumi	2.110	2.110
		Sub Total	9.602	8.112
5	Hassu	Brick P/ment	0.600	0.600

		from Main Road to H/o Muktair Singh, Firni to Gurdharan Singh S/o Bachiter Singh, Main Road to Dera		
	Hassu	Brick P/ment from Firni to H/o Gurcharan Singh, S/o Kaka Singh, H/o Buta Singh to H/o Mehshi Kumar, Asir Road to Shamshan Ghat	1.650	1.650
	Hassu	P/ment of main Street	1.000	1.000
	Hassu	Minor Irrigation-Deweeding of Chatha Minor Burji No. 0 to 2500	0.012	0.012
		Sub Total	3.262	3.262
6	Jagmalwali	Digging of Pond	1.650	1.650
	Jagmalwali	Land Dev. Panchayat Land	0.735	0.735

		Mud B/wall M.No. 83, 84		
	Jagmalwali	Land Dev. Panchayat Land of Land Leveling	1.785	1.785
		Sub Total	4.170	4.170
7	Jalalana	E/Filling	1.260	1.260
	Jalalana	Minor Irrigation-Deweeding of Chormar Burji No. 13750 to 32750	0.104	0.104
		Sub Total	1.364	1.364
8	Kalanwali Village	C.C. Street from Nahar Singh to H/o Lehna Singh	2.947	2.947
	Kalanwali Village	Deepening of Pond Bhohran wala Pond	2.475	2.475
		Sub Total	5.422	5.422
9	Khokar	Land Dev. Panchayat Land M.No. 141 K.No. 22, M.No.147	4.670	4.670

		K.No. 2		
	Khokar	Land Dev. 2007-08	0.685	0.685
		Sub Total	5.355	5.355
10	Naurang	Deepening of pond Near Panchayat Ghar	1380	1.580
	Naurang	Minor Irrigation-Digging of Water Channel Panchayat Land	0.168	0.168
	Naurang	Laying Pipe line from Hassuwala Johar to Gurudwara Johar	0.238	0.238
	Naurang	C.C. Street from Khokhar Road to H/o Baldev Singh S/o Maila Singh	0300	0.500
	Naurang	Land Leveling at Panchayati Land Near Water Works M.No. 115, 123 K.No. 22, 29.	2.490	2.490

	Naurang	Minor Irrigation-Deweeding of Chatha Minor Burji No. 2500 to 17500	0.023	0.023
		Sub Total	4.999	4.999
11	Pipli	Land Dev. Near Peerkhana	2377	2.377
	Pipli	Minor Irrigation-Deweeding of Pana Minor Burji No. 0 to 11600	0.061	0.061
		Sub Total	2.438	2.438
12	Tappi	Desilting of Pond	3.977	3.977
	Tappi	Land Dev. Panchayat Land M No. 3	4.740	4.740
	Tappi	Land Dev. Panchayat Land at West side of Patina Road K No. 18,23,14, 15,16,17,24	2.165	2.165
	Tappi	Minor Irrigation-Deweeding of	0.087	0.087

		Math Minor Burji No. 11601 to 25000		
	Tappi	Land Dev.	2.045	2.045
		Sub Total	13.014	13.014
13	Tigri	Deepening of pond in Panchayat Land	4.900	.4.900
	Tigri	Land Dev. Panchayat Land along Khuhwala Pond	0.624	0.624
	Tigri	C.C. Street from Dabwali Rajbaha to Pond	2.320	2.320
	Tigri	C.C. Street from Main Road to H/o Dalbal Singh Sarpanch	0.427	0.427
	Tigri	C.C. Street from Sh. Chand Singh to H/o Nachatar Singh H/o Bhag Singh	2.000	2.000
	Tigri	C.C. Street from	1.800	1.800

		H/o Nachatar Singh to H/o Bhag Singh		
		Sub Total	12.071	12.071
		Block Dabwali		
1	Abubshahar	E/Filling of Rasta (Jarnaili Sadak)	2.300	2.300
2	Alikan	Land Dev. Panchayat Land Near Sakta Khera Rastaa	4.843	0.800
3	Bharu Khera	Land Dev. (Earth work for plantation)	4.730	2.582
	Bharu Khera	Const. of CC Street from SC Chuapal to Phirniwala park at Part 1	4.263	2.842
	Bharu Khera	Land Development Panchayat Land M. No. 81 K.No. 23,24 :	4.980	2.000

		Sub Total	13.973	7.424
4	Chautala	Const. of CC Street from H/o Sh. Dharampal to H/o Sombatt in Jawahar Colony	4.930	3.037
	Chautala	Const. of CC Street from H/o Wami Ji Kothi to Shop of Santokh Singh	2.921	1.800
	Chautala	Land Dev. Panchayat Land on Bharu Khera Road M.No. 420 K.No. 12 to 15	4.866	3.896
	Chautala	Mud B/Wall around Panchayat Land M.No. 420,443,442,421 K.No.1 to 5, 23 to 25, 1,10,20,11,1,10,	1.111	0.240

		11,20,21		
	Chautala	Minor Irrigation Strengthening of Berm of Channel at RD 55415 R outlet from Chautala Minor	1.584	0.746
	Chautala	Minor Irrigation and Strengthening of Berm RD 65000 from Teja Khera Minor	2.540	1205
	Chautala	Land Dev. - Jungle Clearance	1.340	1.340
	Chautala	Minor Irrigation Strengthening of Berms RD 59000 outlet	0.780	0.602
	Chautala	Digging of under Ground water tank Chautala Village	1.860	0.452
		Sub Total	21.932	13.318
5	Desujodha	Land Dev. Jungle Clearance and	0.553	0.553

		leveling of Shamshan Bhoomi		
	Desujodha	Minor Irrigation-Strengthening of Berms of Channel RD 60400(R) and (L)	0.445	0.440
	Desujodha	Minor Irrigation-Strengthening of Berms of Channel RD 60400(R) and (L)	0.682	0.670
		Sub Total	1.680	1.663
6	Diwan Khera	Earthwork for Plantation and Mud Wall of Shamshan Bhumi and Jungle Clearance	0.657	0.310
	Diwan Khera	Deeping of Pond Near S.C. Choupal	1.750	1.740
	Diwan Khera	Land Dev. Panchayat land M.No. 104 K.No.	3.838	2.000

		9,12,19,22		
		Sub Total	6.245	4.050
7	Ganga	Digging of Pond (Chuharsager)	3.421	1.700
	Ganga	Land Dev. Jungle Clearance and Leveling of Shamshan Bhoomi Sardrowali	2268	2.000
		Sub Total	5.689	3.700
8	Gidder Khera	Land Dev.	0.987	0200
	Gidder Khera	Land Dev. Earth work for Plantation	1.480	1.480
		Sub Total	2.467	1.680
9	Goriwala	Land Dev.	3.056	2.985
	Goriwala	Land Dev. Levelling of Bhoomi	1270	0.800
		Sub Total	4.326	3.785
10	Haibuana	Land Dev. &	1.254	1.000

		Panchayat Land		
	Haibuana	Land Dev. Panchayat Land M.No. 74 K.No. 2,3,4,9	2392	1.500
		Sub Total	3.646	2.500
11	Jandwala Bishnoia	Land Dev.	4.980	1.392
12	Jogewala	Arrear of Land Dev.	1.700	1.700
	Jogewala	Const. of CC Street from 1-1/o Lakhbir Singh to Sh. Om Parkash via Sita Singh	3.459	3.430
	Jogewala	Const. of CC Street from H/o Jaswant Singh to Desujodha Road	4.620	4.600
	Jogewala	Land Dev. Panchayat Land M.No. 56 K.No. 4,5,6,7	2.046	1.000
		Sub Total	11.825	10.730

13	Juttanwali	Minor Irrigation and Strengthening of Berms	0.501	0.501
	Juttanwali	Land Levelling of Shamshan Bhumi	3.108	2.832
	Juttanwali	Strengthening of Water Channel from village to East North side	4.650	4.650
		Sub Total	8.259	7.983
14	Khuiyan Malkana	Const. of CC Street from H/o Shri Ram to Mitri Road	3248	3248
	Khuiyan Malkana	Const. of CC Street from H/o Budh Ram to Siya Ram Kutia	4.060	3.945
	Khuiyan Malkana	Land Dev. Panchayat Land M.No. 82 K.No. 21,22	3.574	3.040
	Khuiyan Malkana	Land Dev. Panchayat Land	3.598	3.198

		M.No. 82 K.No. 11,83/15 -		
		Sub Total	14.480	13.431
15	Lakhuana	Land Dev. Panchayat Land M.No. 9 K.No. 21,22,23,24	2322	2.000
	Lakhuana	Minor Irrigation Strengthening of Berms RD 9280, 8166 from Lohgarh Road	0.907	0.600
		Sub Total	3.229	2.600
16	Lambi	Deeping and Digging of Pond near Shamshan Ghat	3.080	3.080
17	Lohgarh	Jungle Clearance of Minor-Lohgarh-iii	0.695	0.695
	Lohgarh	Jungle Clearance of Lohgarh Minor Channels	1.155	1.155
		Sub Total	1.850	1.850

18	Mangeana	Land Dev. Desu Jodha Road	3.390	1.895
19	Maujgarh	Land Dev. of Panchayat Land	1.890	1.500
	Maujgarh	Const. of CC Street from H/o Darshan Singh to Mahender Singh	4.990	3.000
		Sub Total	6.880	4.500
20	Modi	Land Dev. SC Land	1.732	0.785
	Modi	Minor Irrigation Strengthening of Berms of Channel at RD 27800	0.545	0.481
	Modi	Land Dev. SC Land of Sh. Kartar Singh S/o Sh. Sawan Singh	2.425	1.736
		Sub Total	4.702	3.002
21	Munawali	Land Dev. of Panchayat Land	4204	0.934
	Munawali	Land Dev. Panchayat Land	1.590	1.550

		Bhattewali Bhoomi		
	Munawali	Digging of Pond Levelling old Pond to Durawala Johar	2.257	0.800
		Sub Total	8.051	3.284
22	Nillianwali	Const. of CC Street from H/o Pritam Singh to Sukhpal	3.859	3.859
	Nillianwali	Land Dev. Panchayat Land Bhattewali Bhoomi M.No. 6, K.No. 9,10	2290	0A40
	Nillianwali	Unloading of E/work from the Bank of Maujgarh from 52000 to 55000/R	0.492	0.492
	Nillianwali	Minor Irrigation-Strengthening of Berms RD 57650 from Maujgarh	0.567	0303

		Minor		
		Sub Total	7.208	5.094
23	Parma	Jungle clearance of the Berms of Channel RD 39462, 34500, 41050, 36500	1.905	1.653
24	Panniwala Morika	Land Dev.	0.784	0.307
25	Panniwala Ruldu	Land De v.	3.842	1.300
26	Phullon	Minor Irrigation Strengthening of	1.475	0.600
27	Sakta Khera	Berms RD 50000 L Part I & 11 Land Dev.	1217	1200
	Sakta Khera	Const. of CC Street from Lohgarh Road to H/o Bhagirath	2.046	2.046
	Sakta Khera	Land Dev. Panchayat Land M.No. 116 K.No. 11,14,16,17,24,25	4358	4358

	Sakta Khera	Minor Irigation-Strengthening of Berms	0.653	0.350
		Sub Total	8.274	7.954
28	Sawant Khera	Earthwork for Plantation in Shamshan Bhoomi	4.829	4.829
29	Shergarh	Land Dev. Panchayat Land	2.085	2.065
	Shergarh	Land Dev. Panchayat Land M.No. 62, 68 K.No. 5,6,19,20	2318	2318
	Sakta Khera	CC Street from Harijan Dharamshala to Mahila Sochalya	4.606	4.605
	Sakta Khera	E/Filling in CC Street at Village Shergarh	0.760	0.750
		Sub Total	9.769	9.738
30	Sukhera Khera	Land Dev. Panchayat Land on Teja Khera	3.982	3.170

		Rasta		
31	Teja Khera	Const. of CC Street	3286	3286
	Teja Khera	Land Dev. Mud Wall with an-ear	1.813	1.000
	Teja Khera	Minor Irrigation Strengthening of Berms RD 45400 from Teja Khera minor	0.760	0.700
		Sub Total	5.859	4.986
		G Total	263.670	211.024

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन राष्टीय रोजगार योजना के तहत काम मिलने के लिए हुई उनकी संख्या 65657 है। लेकिन वर्ष 2006–07 के दौरान 3151 छ लोगों को रोजगार मिला और वर्ष 2007–08 के दौरान 21857 लोगों को रोजगार मिला। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि इसमें ज्यादातर फर्जी बिलों से भुगतान होता है। इसमें जो ज्यादातर काम हुए हैं वे अर्थ वर्क के हुए हैं।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, स्पैसीफिक सवाल पूछें। आप दिक्कतों को एक्सप्लेन कर रहे हो। आपके पास पूरा डाटा आ गया है।

डा० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। मेरे हल्के में एक गांव गंगा है। उस गांव में 6 तालाब सरपंच ने खुदवा दिए। जब मैंने इस बारे में वहां के सरपंच से बात की तो उसने कहा कि अधिकारियों ने कहा है कि इस सारे पैसे को खर्च करना है चाहे आप किसी तरीके से खर्च करो। इसलिए मैंने बिना जरूरत के तालाब खुदवा दिए। अध्यक्ष महोदय, वे तालाब ऐसी जगह खुदवा दिए जहां न तो बरसात का पानी पहुंच सकता है और न ही गांव का पानी पहुंच सकता है। इस तरीके से वहां मिस यूज ऑफ फंड्ज हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नरेगा बहुत अच्छी योजना है, भविष्य में इस प्रकार से इसके फइस का मिस यूज न हो क्या ये उसकी प्रोपर प्लानिंग करेंगे? इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस स्कीम के तहत जिनको काम मिलना चाहिए उन्हीं को काम मिले और क्यालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा हो उसकी भी क्या मंत्री जी प्रोपर लानिंग करेंगे?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने दो प्रश्न पूछे हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि नरेगा स्कीम पूरे हिन्दुस्तान में सबसे नायाब स्कीम है। यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा

पहुंचाने के लिए और गरीबों और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए देश की यू०पी०ए० सरकार ने शुरू की थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की एक चिंता बिल्कुल वाजिब है क्योंकि यह नई स्कीम है इसमें हमारे यहां ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में पेमैंट्स ईशू करने पर सवाल अराईज हुए हैं। जब भी इस प्रकार की कोई नई स्कीम आती है तो उसमें कुछ पिलफ्रेज की शिकायतें आयेंगी। लेकिन इसमें अब हम वैसा ही करने जा रहे हैं जैसा आध्रप्रदेश में किया गया है। अब हमारे यहां एक भी पैसा मौके पर अंगूठा लगाकर कैश नहीं दिया जायेगा जो चिन्ता माननीय सदस्य ने जाहिर की है उस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया है कि नरेगा की सभी पेमैंट्स काम करने वालों को पोस्ट आफिस या बैंक में एकाउंट खुलवाकर दी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है और आज तक 1 ,37 ,623 रुपये की पेमैंट बैंक या पोस्ट आफिस द्वारा की जा चुकी है। इतनी बड़ी एक्सरसाईज हम कर चुके हैं। इस स्कीम के जो लाभानुभोगी हैं उनके एकाउँट पोस्ट आफिस या बैंक में खुलवा दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, अब तो नई टैक्नीक भी आ गई है जिसको बायो मैट्रिक्स टैक्नीक कहते हैँ जिसके बोरे में मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश भी दिए हैं। अब तो बैंक आपके घर तक जा सकता है और आलरैडी उनके कम्यूटर पर अंगूठे का इम्प्रैशन होता है तो वे वहीं मौके पर जाकर पेमैंट कर सकते हैं। इस प्रकार का अनुबंध हम कुछ बैंकों से कर भी चुके

हैं। यह प्रक्रिया हम बहुत जल्दी ही पूरे प्रान्त में लागू कर देंगे और फिर कोई पिलफ्रेज की कोई शिकायत नहीं आयेगी। एक लाख 37 हजार से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स हम खोल चुके हैं। दूसरा उन्होंने पूछा है कि पैसा खर्च करने के क्या मापदण्ड हैं? स्पीकर सर, पैसे का खर्च भारत सरकार की गाईडलाईन्स के मुताबिक निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। जहां–जहां से शिकायतें आती हैं उनके लिए भी हमने निर्णय कर लिया है कि उन शिकायतों के लिए एक टोल फ्री सुविधा पूरे स्टेट के अन्दर शुरू करेंगे। स्पीकर सर, हमने ग्रिवैंसिज के रिड्रैसल के लिए पूरे हरियाणा में टोल फ्री हैल्प लाईन बनाई है जिसके नम्बर हैं 18001802023 1 दिसम्बर, 2008 से ही यह टोल फ्री हैल्पलाईन बनाई है और जो भी कम्पलेंट्स अब आती हैं हम उनका मौके पर रिहैसल करने की कोशिश करते हैं। किसी भी माननीय सदस्य को मैं खुले मन से कहना चाहूँगा कि इस नरेगा की कामयाबी में आपकी, हमारी और इस प्रान्त के सभी ढाई करोड़ लोगों की रुचि है इसलिए जहां शिकायत लगे आप कृपया करके दो लाईन लिखकर मुझे या माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जहां पर शिकायत होगी उसको दुरुस्त किया जाये।

Special Grant for Development of Village Ramrai

***1136. I.G. Sher Singh :** Will the Urban Lacal Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give

special grant for the development of pilgrim facilities of religious centre at Village Ramrai under the Kurukshetra Development Board ?

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : No, Sir.

डॉ० सुशील इन्दौराः .....

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Mr. Indora. please don't interrupt the proceedings of the House

आई०जी० शेर सिंह. अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में रामराय एक तीर्थ स्थल है जो कि कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड के अधीन आता है। स्पीकर सर, वहां पर साल में दो बार श्रद्धालु आते हैं। वहां पर एक भी पैसा विकास के लिए नहीं लगाया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या रामराय तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड में शामिल नहीं है। अगर शामिल नहीं है तो इसे कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड में शामिल किया जाये।

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, लोगों की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में ही 1 .8. 1968 में कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड का गठन किया गया था और कुरुक्षेत्र सहित आसपास के पांच जिलों कैथल, जीन्द, करनाल और पानीपत की परिधि में आने वाले धार्मिक स्थलों को कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड का एरिया ऑफ ऑपरेशन माना गया। इन पांच जिलों के इलाके को स्थानीय भाषा

में मठ कोसी भी कहा जाता है। इनमें से रामराय जो तीर्थस्थल है यह भी उसका एक हिस्सा है। स्पीकर सर, हमारे लिए समस्या यह है कि कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड का अपनी आय का कोई साधन नहीं है और बोर्ड द्वारा मात्र सरकार द्वारा दी गई ग्रांट से ही अपने सारे काम किये जाते हैं। इस लिहाज से जितना पैसा तीर्थ स्थलों के लिए अपेक्षित होता है सरकार समय–समय पर उसे रिलीज करती रहती है। इस मामले में हम इस बात से परिचित हैं कि जब धार्मिक स्थलों पर लोग आते हैं तो उनकी भी कुछ अपेक्षायें होती हैं। स्पीकर सर, मैं इस बात को मान्यता देते हुए यह बात कहूँगा कि जब भी समय–समय पर कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड द्वारा एडीशनल फण्डज मांगे गये हमने रीजनेबल फण्डज रिलीज किये हैं। स्पीकर सर, मैं अपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अब भी इस बात पर आन जॉब हैं और हमने चीफ आर्कीटैक्ट, हरियाणा को इसका नया प्लान बनाने के लिए कह दिया है जिसमें सारे के सारे 48 कोसी के तीर्थस्थल आयेंगे। इसमें हमने साथ ही साथ यह भी तय किया है कि बी० एण्ड आर० डिपार्टमैंट से हम इनके सारे एस्टीमेट्स बनवा लें और उसके मुताबिक बोर्ड यह तय करेगा कि किस काम को प्रॉयरटी बेसिज पर करवाना है क्योंकि साधन न होने की वजह से एट ए टाईम सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। स्पीकर सर मैं आदरणीय सदस्य से भी यह कहूँगा कि ये अपने तौर पर भी कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड को अपना यह मैसेज कनवे कर दें कि वे

उसमें इंट्रस्टिड हैं तो मैं भी देख लूंगा कि हम इनके लिँए क्या कर सकते हैं।

विभिन्न सरकारी कॉलेजों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूँगा कि गवर्नमैंट कॉलेज फार बूमैन, करनाल, गवर्नमैंट कॉलेज, जीन्द, गवर्नमैंट कॉलेज, सफीदों, गवर्नमैंट कॉलेज, इसराना, नैशनल कालेज, शाहबाद मारकंडा तथा राजीव गांधी महाविद्यालय, उचाना के छात्र–छात्राएं दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही को देखने के लिए मौजूद हैं। मैं जहाँ सदन बई। तरफ से उनको शुभ कामनाएं देना चाहता हूँ ये आशा भी करता हूँ कि मेरे पक्ष और विपक्ष के साथी सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से चलायेंगे। सदन में संसदीय प्रणाली की कार्यवाही को देखने के लिए ये सब छात्र और छात्राएं आये हैं। सदन की कार्यवाही को चलाते हुए हम इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि सदन की मान मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाये क्योंकि यह कल की पीढी है, इस देश का भविष्य है, इस प्रान्त का भविष्य उन्हें अपनी कलम से लिखना हे। उनको इस सदन में भी और इस सदन से बाहर भी कल को एक रचनात्मक क्रियाशील भूमिका निभानी है हम उनको शुभ कामनाएं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके इलावा श्री अतर सिंह सैनी, पूर्व बिजली और सिंचाई मंत्री व श्री रामकिशन बैरागी जी भूतपूर्व

एम०एल०ए० भी स्पीकर गैलरी में मौजूद हैं मैं उनसे सदन को अवगत करवाना चाहूँगा तथा इनका अभिनन्दन करना चाहूँगा।

ताराकिंत प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सदन में हमने मंत्री जी से कहा था कि हमारा कलायत कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड की जो 48 कोस भूमि है उसमें आता है। वहां पर सरस्वती नदी का पानी भी निकला है और कलायत में कपिल मुनि माईनर का निर्माण हो चुका है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड का कि उनकी तरफ से वहा पर 2 साल से पवित्र कपिल मुनि सरोवर पर कार्य भी चल रहा है। लेकिन उस सरोवर में पानी डालने और निकालने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सरोवर का पानी काफी खराब हो गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि क्या उस सरोवर में पानी डालने और पानी निकासी का कोई प्रावधान करेंगे।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बात इसकी कम्पलीशन के साथ जुड़ी है जैसे ही इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जायेगी तो हम इसमें दो पाईप, एक आऊट गोइंग के लिए और एक इन–पुट के लिए डाल देंगे। मैं आदरणीय बहन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आज ही मैसेज दे दूंगा कि उनके पानी की निकासी सुनिश्चित करें।

Upgrading the High School at Madlodha

***1163. Smt. Raj Rani Poonam :** Will the Education Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Boys High School, Madlodha to Government Boys Senior Secondary School; and

(b) if so, the time by which the said school is likely to be upgraded ?

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta):

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise. But keeping in view the demand made by the Hon'ble Member, I would like to inform that it is likely to be upgraded in the next academic session.

श्री अध्यक्षः मैडम जी, क्या आप अपने सवाल के जवाब से सैटिस्फाईड हैं?

श्रीमती राज रानी पूनमः हां सर, मैं सैटिस्फाईड हूँ शुक्रिया।

Land acquired for Eastern Periphery Highway

***1155. Shri Mahender Partap Singh :** Will the P.W.D. (B & R) Minister be pleased to state :-

(a) the names of the villages and total area of land acquired or being acquired for eastern Periphery Highway

leading from Palwal to Ballabgarh upto Yamuna/U.P. border via Faridabad together with the total amount of compensation/solatium including interest etc. paid or being paid to the farmers; and

(b) whether any other benefit is also being provided to the farmers for the acquired land it; if so, the details thereof ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, a statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Details of villages, land acquired and compensation paid :—

Name of villages	Total Area	Position of Notification	Amount of Compensation
Rehrana, Bahraula, Khusropur, Attohan, Asawta, Hoshangabad, Chhajju Nagar, Akbarpur Dakora, Khedla Farijpur, Pelak, Sujwadi, Alawalpur, Kurara Shahpur, Dadauta, Katesra, Gopikhera, Jalhaka, Mohna, Chhainsa, Maujpur, Atali, Mothuka, Aduwa,	427.421 hectares (approx.)	Out of this, '3D' notification under National Highway Act 1956 for acquir- ing 354.56 hectares land has already been	For the land notified under section '3D' the award amount of Rs. 138.82 crores has been paid to the Competent Authority cum District Revenue Officer, Faridabad. Out of this, an amount of Rs. 128

Faizupur Khadar, Sahupura, Shahjahanpur.		published.	Crores has already been disbursed to affected persons.

(b) No, Sir.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इस्टर्न पेरीफेरी हाईवे के लिए तकरीबन 30 गांवों की 354 हैक्टेयर भूमि के लिए अधिसूचना जारी की है जो एक्यायर कर ली गईहै और उसके लिए 138 करोड़ 82 लाख रुपये इन्होंने रिलीज किया हे उसमें से कुछ पहले ही बांट दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, (ख) का जवाब इन्होंने दिया है नहीं'। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा कितना पड़ता है दूसरा इन्होंने जो कुछ दिया है उसके अतिरिक्त भी क्या अन्य कोई लाभ किसानों की जमीन के साथ जा रहा है या नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का यह ऐलान है कि 15 हजार रुपये प्रति एकड़ और उससे ज्यादा हर साल 33 साल तक देंगे।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, यह तो आ ही चुका है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, यह जो इस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रैस हाईवे है इसके बारे में हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि जो नये फ्लोर रेट थे। इसमें 16 लाख का सोलेशियम लगा कर यह मुआवजा दिया गया है जो कि तकरीबन 138.82 करोड़ रुपये जिसमें से 128 करोड़ रुपये दे दिये गये हैं।

इन्होंने फार्मर्ज को अलग बैनिफिट देने के बारे में जो कहा है उसके बारे में मैं इन्हें यह बताना चाहूँगा कि क्योंकि एन०एच०आई० की पॉलिसी नहीं है कि.....

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Questions Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रंश्नो के लिखित उत्तर

Maintenance of Tails of Distributories Minors

***1169. Shri Tejendra Pal Singh Mann :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :-

(a) the remedial measures taken by the Government to ensure the maintenance of tails of various distributories and minors specially in district Kaithal; and

(b) whether there is any proposal to involve the Police on a regular basis for night patrol to check the theft of canal water in higher reaches ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) विभिन्न रजबाहों तथा माईनरों के, विशेषकर जिला कैथल में, अन्तिम छोरों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पग उठाये गए हैं – (।) चौनलों पर चोरी की घटनाओं को कम करने तथा अनुशासन

सुनिश्चित करने के लिए गश्त आवश्यक कर दी गई है और अधीक्षक अभियन्ता स्तर तक के अधिकारियों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।

(2) रजबाहों तथा माईनरों की सफाई साल में दो बार करवाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ताकि अन्तिम छोरों पर पानी पहुंचता रहे।

(3) हमने गत वर्षो की तुलना में भाखड़ा प्रणाली से पानी की अधिक आपूर्ति प्राप्त करने हेतु सफलता प्राप्त की है जिसने अन्तिम छोरों पर अधिक पानी पहुंचाने में सहायता की है।

(ख) ही श्रीमान जी। नहरी पानी तथा बिजली की चोरी को रोकने के लिए विशेष पुलिस थाने बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Electricity Store at Pundri

***1189. Shri Dinesh Kaushik :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to establish an electricity store at Pundri ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

नहीं, श्रीमान।

Extension of Minor

***1218. Shri Ram Kishan Fauji :** Will the Irrigation

Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the Khanak minor upto village Nalwa and Siwani Minor from Siwani to the southern side towards the Hisar-Rajgarh Road by 5 Burji; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to extend both the Head and tail of Siwani-Gadhwa Distributory in Gaindawas ?

सिंचाई पत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) (1) नहीं, श्रीमान जी, खनक माईनर से विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) ही, श्रीमान जी, सिवानी माईनर के 5000 फीट के विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) (1) हां, श्रीमान जी, गढ़वा रजबाह के हेड रेगुलेटर की क्षमता बढ़ाने की प्रस्तावना है।

(2) नहीं, श्रीमान जी, गैंदावास में गढ़वा रजबाह के पूर्ववत अन्तिम छोर के विस्तार की कोई प्रस्तावना नहीं है।

To take over the Pitamah Kanha Singh College

***1228. Shri Naresh Yadav :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the Pitmah Kanha Singh College, Kanina; if so, the time by which

the above said college is likely to be taken over ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे सम गुप्ता): नहीं, श्रीमान जी।

Promoting of Education

***1222. Shri S.S. Surjewala :** Will the Education Minister be pleased to state whether Kaithal district is one of the most backward in the field of education, particularly female education; if so, whether it is also a fact that there are no Government Girls Senior Secondry Schools in most of the large villages; if so, the steps taken by the Government to promote female education and for making this area among first rate districts of Haryana together with the number of schools opened/upgraded in the Kaithal Assembly Constituency after the formation of present Government ?

शिक्षामंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):

श्रीमान जी, इस विषय में एक वक्तव्य सदन पटल पर रखा है।

वक्तव्य

1 श्रीमान जी, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, महिला एवं पुरुष साक्षरता दर में कैथल जिला राज्य के अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में से एक है।

2. राज्य के 1490 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से 276 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लड़कियों के लिए

हैं। इसी प्रकार से कैथल जिले के 74 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से 12 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं।

3. महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम.

(1) अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों के विद्यार्थियों के लिए मासिक वजीफा योजना में लड़कियों को लड़की से अधिक दर पर वजीफे दिए जा रहे हैं।

(2) जिले में विद्यार्थियों को शिक्षा उनके घर के नजदीक ही उपलब्ध है। जिले में 996 राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं, 77 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 68 राजकीय उच्च विद्यालय एवं 74 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। इसके साथ ही कैथल जिले में काफी संख्या में निजी विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(3) पिछले वर्ष तक केवल लड़कियों एवं अनुसूचित जाति के लड़की को मौलिक स्तर तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही थी। वर्तमान में सभी लड़के एवं लड़कियों को पाठ्य पुस्तकें. एवं कार्य पुस्तिकाएं मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छठी कक्षा की उन छात्राओं को, जिनके लिए 1.6 किलोमीटर तक कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं हे, साईकिलें प्रदान की गई हैं।

(5) राजौंद शैक्षिक तौर पर एक पिछड़ा खण्ड है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है। 4. (1) कैथल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 के दौरान खोले गए राजकीय विद्यालयों की संख्या –

वर्ग	विद्यालयों की संख्या
राजकीय प्राथमिक विद्यालय	4

(2) कैथल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 के दौरान स्तरोन्नत किए गए राजकीय विद्यालयों की संख्या –

वर्ग	विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय	9
माध्यमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय	2
उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	5

***1094. Dr. Sushii Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any special arrangements have been made by the Government to prevent the terrorist attacks in Haryana State keeping in view the terrorist attacks in the country; if so, the details thereof together with the steps taken for reforms in the police ?

मुख्यमंत्री (थी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

देश में उग्रवादी हमलों के मध्यनजर राज्य में उग्रवादी हमलों को रोकने के लिए निमलिखित उपाय किए जा रहे हैं:–

1. संगठित अपराध तथा उग्रवादी मामलों पर बेहतर प्रयवेक्षण तथा कार्यकुशलता के लिए हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी के अधीन राज्य अपराध शाखा का गठन किया है। उनकी सहायता के लिए एक पुलिस महानिरीक्षक, दो उप पुलिस महानिरीक्षक तथा अन्य स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में एक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को पुलिस महानिरीक्षक (आपरेशन) के पद पर नियुक्त किया गया है।

2 राज्य में पांच इन्टरस्टेट इन्टैलीजैंस स्पोर्ट टीमों का प्रत्येक मण्डल के लिए अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा फरीदाबाद में उप पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर विभाग के नेतृत्व में तथा मुख्यालय

पंचकूला पर पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा के अधीन गठन किया गया है, जो पड़ौसी राज्यों की आई०एस०आई०एस०टी० के साथ उग्रवाद की समस्या, तकनीकी आपरेशन तथा आसुचना के विशेष पहलुओं पर विचार विमर्श तथा वांछित तालमेल हेतू बनाई गई हैं।

3. मधुबन में बम निरोधक दस्ते के अतिरिक्त एक और बम निरोधक दस्ता पूर्ण साजो सामान के साथ गुड़गांव में तैनात किया गया है।

4. पंचकूला, मोहाली तथा चण्डीगढ़ में किसी प्रकार की उग्रवादी घटनाओं को संयुक्त रूप से निपटने के लिए चण्डीगढ़ पुलिस, मोहाली पुलिस तथा एस०आई०टी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से पारस्परिक तालमेल स्थापित किया गया है।

5 जिला गुड़गांव के लिए व्यापक सुरक्षा योजना कार्यन्वित की जा. रही है।

8. गुज सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए केन्द्रीय तथा राज्य आसुचना ईकाइयों के बीच अन्तर्राज्जीय गोष्ठी/बैठकों का समय–समय पर आयोजन किया जा रहा है। 7. राज्य में शांति भंग करने वाले असमाजिक तत्वों की कोशिश को रोकने तथा उनका मुकाबला करने के लिए हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हें तथा अथक प्रयत्न कर रहे हैं।

हरियाणा राज्य में पुलिस सुधार के लिये उठाये गये कदमः—

1. पुलिस विभाग की पुर्नसंरचना की गई तथा हरियाणा में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 25 उप पुलिस अधीक्षक, 116 निरीक्षक, 356 उप निरीक्षक, 625 सहायक उप निरीक्षक, 1250 प्रधान सिपाही तथा 5000 सिपाही (कुल 7372 पद) स्वीकृत किए गए हैं।

2. थाना प्रबन्धकों के 161 पदों को निरीक्षक स्तर का अपग्रेड किया गया है।

3 न्यायिक वैधिक प्रयोगशाला मधुबन में नए टोक्सीकोलोजी विंग को स्वीकृत किया गया है तथा डी०एन०ए० टैस्ट सुविधा शुरू की गई है, जो उलझे अभियोगों की जांच में सहायक होगी।

4. पिछले चार सालों में 52 नए पुलिस थाने स्थापित किये गये हैं, जिनमें 22 यातायात थाने तथा 5 रेलवे थाने शामिल हैं।

5. जिला गुड़गांव में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है।

6. हरियाणा पुलिस की आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए उधार धनराशि प्रदान की गई है।

7. पुलिस कर्मियों की लम्बी तथा कठिन ड्यूटी के कारण पैदा होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए उनकी आवास सुविधाओं के लिए काफी धनराशि दी गई

8. राज्य में 5 बम निरोधक दस्ते स्वीकृत किये गये हैं, जिनका मुख्यालय प्रत्येक मण्डल स्तर पर तथा एक मधुबन में रखा गया है।

9. पुलिस के मनोबल को बढ़ाने तथा पुलिस के विभिन्न पदों पर उन्नति में शिथिलता को दूर करने के लिए प्रत्येक पद की उनति के लिए निर्धारित समय सीमा को काफी कम कर दिया गया है। अब सिपाही पहले 16 वर्षों की तुलना में 12 वर्ष में विमुक्त मुख्य सिपाही के पद पर पदोन्नत हो सकेगा, विमुक्त मुख्य सिपाही 50 वर्ष की तुलना में 22 वर्ष में विमुक्त सहायक उप निरीक्षक पदोन्नत हो सकेगा तथा विमुक्त सहायक उप निरीक्षक 35 वर्ष की तुलना में 30 वर्ष मैं विमुक्त उप निरीक्षक पदोन्नत हो सकेगा।

10. नया हरियाणा पुलिस अधिनियम बनाया गया है तथा पुराने पंजाब पुलिस नियमावली, 1954 के स्थान पर नई पुलिस नियमावली तैयार की जा रही है।

Construction of ROBs in Bhiwani

***1072. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that two ROBs were sanctioned for Bhiwani, if so, the status of construction work of said ROBs together with the time by

which these are likely to be competed ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): हां श्रीमान जी। तोशाम सड़क पर उपरगामी पुल का कार्य प्रगति पर है और जुलाई, 2010 तक पूर्ण होने की संभावना है। हांसी सड़क पर सड़क उपरगामी पुल का कार्य तोशाम सडक उपरगामी पुल के पूर्ण होने के बाद धन की उपलब्धतानुसार शुरू किया जाएगा।

Completion of Kundli Manesar and Palwal Road

***1116. Shri Dharam Bir :** Will the Industries Minister be pleased to state the time by which the Kundli-Manesar and Paiwal road is likely to be completed ?

उद्योगमंत्री (श्री लक्ष्मन दास अरोड़ा): रियायत प्राप्त कर्ता के साथ क्रियान्वित रियायती अनुबंध के अनुसार, कुंडली–मानेसर–पलवल एक्सप्रैस–वे के कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 29.7.2009 है। हालांकि, कार्यस्थल पर कार्य की प्रगति विभिन्न कारणों से धीमी है। परन्तु प्रगति पर लगातार पूरा ध्यान दिया जा रहा है और प्रोजैक्ट कार्य में तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इस समय कार्य पूरा करने का निश्चित समय बताना मुश्किल है।

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, keeping in view the volume of pending business before the House, it would be appropriate to rescind the decision taken by the House on

17th February, 2009 in respect of transaction of business on 20th February, 2009 which was to be taken up on 18th February, 2009 (2nd Sitting).

Now, the sitting of the House on 20th February, 2009 will commence at 2.00 P.M. and adjourn after conclusion of the business entered in the List of Business for the day as per report of the Business Advisory Committee already adopted in the House.

Is it the pleasure of the House to hold sitting on 20th February, 2009 ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The decision is approved with the sense of the House. Now, the sitting of the House on 20th February, 2009 will commence at 2.00 P.M. and adjourn after conclusion of the business entered in the List of Business for the day as per report of the Business Advisory Committee already adopted in the House.

राज्यपाल से सन्देश

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a communication from His Excellency Dr. A.R. Kidwai, Governor of Haryana on 17th February, 2009 which reads as under :

"I have received your demi-official communication dated 13th February, 2009, No. HVS-LA-38/2009/2117, alongwith a copy of 'Motion of Thanks' passed by the Haryana Vidhan Sabha on my Address on 6th February, 2009.

Please do convey my sincere appreciation and

acknowledgement regarding the same to all the esteemed Members of the Haryana Vidhan Sabha.

With kind regards."

वर्ष 2009–2010 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on Budget Estimates for the year 2009-2010 will be resumed.

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी): स्पीकर सर, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे हरियाणा के बजट पर बोलने का समय दिया। स्पीकर सर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने हरियाणा का वर्ष 2009–10 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अच्छा बजट है। जहां तक मैं समझता हूँ यह केवल आकड़ों का खेल नहीं बल्कि यह बजट प्रदेश के विकास को एक नयी दिशा देगा क्योंकि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व और श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर सरकार ने विकासात्मक बजट बनाया है। सबसे खुशी की बात यह है कि पिछले चार साल में प्रदेश के किसानों के लिए जो सरकार ने किया है आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। (विघ्न) स्पीकर सर, इस प्रदेश में राज हथियाने के लिए किसानों का बहुत इस्तेमाल किया गया है। अगर किसानों के हितों के कार्य किसी ने किए हैं तो वह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने और इनकी सरकार ने किए हैं। यह सब जानते हैं कि पहले सैन्टर में एनडी.ए. की सरकार थी और हरियाणा में इण्डियन नैशनल लोकदल की सरकार थी। स्पीकर

सर, श्री ओम प्रकाश चौटाला के साढ़े पांच साल के कार्यकाल में गेहूं का जो रेट बढ़ा था वह सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल ही बड़ा था। (विघ्न) इन्दौरा जी, इस तरह से आखें क्यों दिखा रहे हो मैं तो आकड़ों की बात कर रहा हूं। (इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल पदासीन हुए।) चेयरमैन सर, अगर आज की सरकार के चार सालों का हिसाब देखें तो इस सरकार द्वारा गेहूं का 400 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दिया गया है। चेयरमैन सर, मुख्यमंत्री जी ने बजट से पूर्व सदन में बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, विधवाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए जो घोषणाएं की हैं उससे हरियाणा के हर व्यक्ति के चेहरे पर रौनक आई है। इन घोषणाओं में किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है। चेयरमैन सर, बजट को तो बहुत कम लोग समझते है लेकिन मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को हर व्यक्ति समझता है। चेयरमैन सर, हमारा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। आज हरियाणा प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। इस राज से पहले के राज में गेहूं की और जीरी की इल्ड बहुत घट गई थी और हर साल घटती जा रही थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद इस सरकार के और वैज्ञानिकों के प्रयासों से वह पैदावार दोबारा से बड़ी है। इसमें किसानों की मेहनत भी है। चेयरमैन सर, पैदावार बढ़ने के साथ–साथ उनकी पैदावार के रेट भी बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से किसानों को इन चार सालों में बहुत लाभ हुआ है। आज किसान खुशहाल है किसान' के चेहरे पर रौनक है। चेयरमैन सर, विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता औन् और

जो उनकी पार्टियां हैं आज उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। आज इस वजह से ये बहुत ही हताश हैं, इनकी हवा निकल गई है। (विघ्न) चेयरमैन सर, इनको दुख होना स्वाभाविक ही है। चेयरमैन सर, हरियाणा प्रदेश में हमेशा से यह परम्परा रही है कि यहां पर जो विपक्षी पार्टी होती है वह यह सपना देखा करती है कि अगले पांच साल के लिए हमारा राज आएगा। लेकिन मैं इस सदन में आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि इन पाच सालों के साथ लोगों ने अगले पांच साल का भी निश्चित कर दिया है कि कांग्रेस का ही राज आएगा। इनको तो अब घर में बैठ जाना चाहिए। मैं तो इनको यह कहना चाहूँगा कि हरियाणा की जनता ने अगले पाँच साल भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को दे दिए हैं। (विघ्न) हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टर साहब, जमीन से जुड़े हूए लोग ऐसी बातें ही करते हें हम हवाई बातें नहीं करते हैं। (विघ्न) चेयरमैन सर, हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए हम लोगों की बातें करते हैं। इन लोगों को नहीं पता है क्योंकि अगर वे जनता के हितों की बात करते, जनता के दिलों को जीतते, लोगों का भला करते तो इनकी संख्या आज इतनी नहीं होती जितनी आज छन्नकी यहां पर आयी है। इससे पता लगता है कि इन्होंने इस प्रदेश में क्या–क्या काम किए हैं। चेयरमैन सर, किसान की बेहतरी के लिए इस सरकार ने बहुत काम किए हैं लेकिन अभी और भी करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। चेयरमैन सर, आज जितनी आमदनी प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की बड़ी है, मैं समझता हूँ वह पर्याप्त नहीं है

क्योंकि किसान के खर्चे भी उतने ही बड़े हैं। चेयरमैन सर, जो करनाल में सी.आईएस.आर. किसानों के लिए केन्द्र है उसमें उन्होंने एक ढाई एकड़ का मॉडल बनाया है। उस ढाई एकड़ के मॉडल से उनको 700 रुपये प्रतिदिन की आय हुई है। चेयरमैन सर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस मॉडल की प्रणाली को पूरे प्रदेश में किसानों के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। उससे पूरी तरह से प्रदेश के किसानों को शिक्षित करना चाहिए और उनको कहा जाना चाहिए कि इस तरह को प्रणाली को आप अपनाएं। अगर ऐसा होगा तो किसान की कायाकल्प ही बदल जाएगी इसलिए सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। चेयरमैन सर, मैं कुछ और ऐसी बात कहना चाहूँगा और सरकार का ध्यान भी दिलाना चाहूँगा। चेयरमैन सर, इस सरकार के द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत से प्रयास बिजली के कारखाने लगाने के लिए किए जा रहे हैं। चालीस साल से ज्यादा हरियाणा कौ बने हो गये हैं, पिछली सरकारों ने पानीपत थर्मल. प्लांट के सिवाए किसी और थर्मल जाट को लगाने की तरफ ध्यान नहीं दिया है लेकिन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार द्वारा चार बिजली के कारखाने लगाने का टारगेट है। एक यमुनानगर का बिजली का प्लांट तो चालू हो गया है, हिसार का बिजली का प्लांट इसी साल से चलने जा रहा है और झज्जर जिले में भी दो बिजली के कारखाने बनने जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है, लोगों को यह विश्वास है और वे अब पूरी तरह से समझते हैं कि इस सरकार ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए पूरे प्रयास किए

हैं। चेयरमैन सर, हमें उम्मीद है कि उनके ये प्रयास जल्दी ही पूरे होंगे और लोगों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में अगला सीजन पैडी का सीजन होगा। उस समय वहां पर सारे इलाके के लिए पूरी तरह से बिजली की जरूरत होगी इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि धान के लिए बिजली का और ज्यादा प्रबन्ध किया जाए ताकि वहां पर किसानों को कोई दिक्कत न आए। चेयरमैन सर, नहर के पानी के लिए सरकार का सबसे बड़ा प्रयास तो यह है कि डब्ल्यू. जे.सी. जो कि अंग्रेजों के टाईम का एक नहरी पानी का सिस्टम था, जो अभी तक उसी तरह से चल रहा था, लेकिन इस सरकार ने उसकी क्षमता को डेढ़ गुणा करके बहुत बड़ा कार्य किया है इससे पूरे उत्तरी हरियाणा को तो फायदा होगा ही, मैं समझता हूं कि दक्षिणी हरियाणा में भी जहां–जहां डब्ल्यू.जे.सी. का पानी लगेगा, उन सबको भी इसका लाभ होगा। यह बहुत बड़ा काम है। चेयरमैन सर, इसके अलावा दादूपुर नलवी और हांसी बुटाना लिंक नहर बनाने के काम सरकार के बहुत ही सराहनीय काम हैं! इनके साथ ही साथ मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि किसान अपनी जमीन जब अपने बच्चों के नाम करवाना चाहता है तो उसमें जो उसकी अपनी जप्ती जमीन है वह तो 15 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तब्दील कर– सकता है, अपने बच्चों के नाम कर सकता है परन्तु जो उसकी खरीदी हुई जायदाद है, उसके लिए उसको तीन परसैंट ड्यूटी देकर ही रजिस्ट्री करवानी पडती है अगर खत ऐसा नहीं कराता है तो परिवार में तरह–तरह के झगड़े

होते हैं। इसके लिए मैं सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उस स्टाम्प ड्यूटी को खत्म किया जाए ताकि उस जमीन को भी उसी तरीके से वारिस के नाम पर करवाया जा सके, यह मेरा सुझाव है। (घंटी) चेयरमैन सर, मैं समय का ध्यान रख रहा हूं। इसी प्रकार से जो किसान को–ऑपरेटिव बैंक में अपनी जमीन रहन पर रखता है पी.एल.डी.बी. में रखता है तो कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है लेकिन जब कोई कॉमर्शियल बैंक में रहन पर रखता है तो उसके लिए उसे स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। इस तरह का कानून ठीक नहीं है। अपनी जमीन भी किसान रहन पर रखे और उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी दे। मेरा अनुरोध है कि इस कानून मे बदलाव लाकर इस स्टाम्प ड्यूटी को खत्म किया जाए। चेयरमैन सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बजट में ऐसे बहुत से कार्य किए हैं गिन कार्यो से कई क्षेत्रो को बहुत लाभ पहुंचेगा। कई बहुत अच्छे अस्पताल रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद में बनाए गए हैं या उनका दर्जा बढ़ा है। इसके इलावा उनका दर्जा बढ़ाकर मल्टी स्पेशियेलिटी स्टेट ऑफ आर्ट लैवल के हॉस्पीटल बनाने के लिए कई सौ करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान किया गया है। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सरकार कौ बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अलावा भी हरियाणा का और भी बहुत सा ऐसा एरिया है जैसे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अम्बाला जहां इनकी जरूरत है। मेरे ख्याल में इन हॉस्पीटल्ज में वित्त मंत्री जी का और मांगे राम जी का जिला भी शामिल नहीं

होगा। मेरा अनुरोध है कि करनाल में भी इस प्रकार का कोई अस्पताल बनाकर वहां के लोगों कौ सुविधा प्रदान की जाए क्योंकि यह क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। चेयरमैन सर, आज ऐसा कोई भी हॉस्पीटल करनाल या कुरुक्षेत्र में नहीं है कि जिसमें किसी सीरियस मरीज का इलाज करवाया जा सके। आमतौर पर सीरियस मरीजों को लेकर हमें चण्डीगढ़ आना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस तरह को फैसिलिटी हमारे क्षेत्र में भी दी जाए। यह बात सही है कि सरकार समानता के आधार पर काम कर रही है चाहे पानी के बंटवारे की बात हो या विकास के कामों की बात हो। इसी तरह से मैं करना चाहूंगा कि हरियाणा में जो विकास है वह भी समानता के आधार पर हो रहा है परन्तु हरियाणा प्रदेश में 300 से ज्यादा गांव आदर्श गांव बनाए गए हैं। उनमें हर सुविधा दो गई है। यह जरूरी भी है क्योंकि आज देहात में जो ग्रामीण व्यक्ति है वह अपनी फेसीलिटीज के लिए शहर की तरफ भाग रहा है। अगर वे सभी फैसीलिटीज उसको गांव में ही मिलेंगी तो वह गांव में ही रहेगा। कई आदर्श गांव बनाये गये हैं। परन्तु मेरा एक सुझाव है कि जिस इलाके में या जिस ब्लॉक में एक भी गांव आदर्श गांव नहीं बनाया गया है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। उनका कोई न कोई एक गांव जो पिछड़ा हुआ है उस गांव को आदर्श गांव बनाना चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि सरकार जो. कुछ कर रही है वह सही है। सबको समान हिस्सा मिलना चाहिए। उनका भी इस बारे में अधिकार है। चेयरमैन साहब, माननीय

मुख्यमंत्री जी 3 सितम्बर, 2006 को नीलोखेड़ी गये थे और उन्होंने वहां पर बहुत सी घोषणाएं की थी जिनमें से बहुत सी तो पूरी हो गई हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनमें से एक जो मुख्य मांग थी कि नीलोखेड़ी में कोई कालेज नहीं हैं और वहां पर कालेज खोला जाए। वहां पर कालेज खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में हां भी भरी थी और कालेज खोलने के लिए वायदा किया था। मैं उनको वह वायदा याद दिलाना चाहता हूँ कि वे अपने उस वायदे को पूरा करें और नीलोखेड़ी में लड़की का या लड़कियों का कालेज खोला जाए क्योंकि वहां के लड़कों और लड़कियों को शिक्षा के लिए कुरुक्षेत्र या करनाल जाना पड़ता है उसके बीच में कोई भी कालेज नहीं हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कहा पर कालेज खोला जाए।

श्री सभापतिः राणा साहब, कंकल्यूड कीजिए।

श्री जय सिंह राणाः चेयरमैन साहब, मैं कंकल्यूड ही कर रहा हूँ। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने मांगें रखी हैं उनकीं पूरा किया जायेगा। दस हजार करोड़ रुपये का एक ऐतिहासिक बजट है इसलिए इन मांगों को पूरा किया जाए, इसमें कोई दिक्कत सरकार को नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इतनी फिराखदिली माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है। मैं इस हाउस का सदस्य वर्ष 1987 में बन कर आया था। चेयरमैन साहब, आप वर्ष 1991 में इस हाउस के सदस्य बनकर आये थे। इतने लम्बे अर्से में मैंने पण्डित भगवत

दयाल जी और राव बिरेन्द्र सिंह को छोड़कर सभी मुख्यमंत्रियों को यहां पर सदन के नेता के रूप में बैठे देखा है और उन्होंने जो वायदे इस हाउस में किए थे वे भी देखे हैं। जिस– प्रकार से हाउस चला करता? था वह भी देखा है। परन्तु मैं इस बात को दोबारा से कहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी सरकार को चला रहे हैं ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। चेयरमैन सर, यह सब संस्कारों का खेल है।

श्री सभापतिः मुख्यमंत्री जी अब भी कर रहे हैं।

श्री जय सिंह राणाः चेयरमैन सर, मैं यह कह रहा था कि ये एक साल तक नहीं बल्कि अगली टर्म में भी मुख्यमंत्री बनेंगे यह निश्चित हो चुका है। यह सब संस्कारों का खेल है जो उनको अच्छे संस्कार मिले हैं उनके पिता जी से, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया था मैं भी उनको नमन करता हूँ। इसके लिए मैं एक बात कहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यह उनके पिता के पुण्य कर्म थे, अच्छे कर्म थे जो उनके पिता जी ने किए थे। उन्हीं के अच्छे कर्मों के कारण ये मुख्यमंत्री बने हैं और एक सफल मुख्यमंत्री कहलाये हैं। चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।

11.00 बजे

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। सरकार द्वारा प्रस्तुत 5वें बजट पर दो–तीन रोज से यहां चर्चा हो रही है। बजट के ऊपर सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने जो कुछ कहा है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हरियाणा के निर्माण में अनेकों सरकारों के मुख्यमंत्रियों का योगदान रहा है उनमें चौधरी बंसीलाल जी का विशेष योगदान रहा है। बंसीलाल जी के बारे में यह कहा जाता था कि ये हरियाणा के निर्माता हैं। उन्होंने हरियाणा का समग्र विकास किया। हरियाणा की स्थिति उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थी और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या के इसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा का समग्र विकास उनकी रहनुमाई में एक अथक प्रयास था। आज उन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। बीच में बहुत सी सरकारें आई और उन्होंने हरियाणा को संवारने में अपना जितना दायित्व निभा सकती थी उतना प्रयास किया। आज तकरीबन 4 वर्ष इस सरकार के हो गए हैं। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की रहनुमाई में हरियाणा प्रदेश को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इस 4 साल के अर्से के विकास को, इस युग को और इस समय को निः संदेह प्रदेश का हर व्यक्ति महसूस करेगा कि हरियाणा के नव–निर्माण की नींव रखी गई है। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश को उत्कृष्टता की ओर ले गए हैं और ऐसा करके प्रदेश को देश में

सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने की तरफ जो कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उठाए हैं, इस देश के लिए शायद वह एक एग्जाम्पल है इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शितापूर्ण सोच को जाता है। हर क्षेत्र को, हर व्यक्ति को एक दृष्टि से, सामान भाव से बरतने का एक व्यवहार इस बात को और बल देता है। सभापति महोदय, अगर 4 साल के इस अर्से की बात करें तो माननीय सदस्यों ने इसका काफी जिक्र किया है। मैं उनका ज्यादा जिक्र तो नहीं करूँगा। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की कारगुजारियों का एक खाका और एक दर्पण है कि कहां हम खड़े हैं और क्या हमने किया है लेकिन बजट सरकार का वह दस्तावेज है, वह दर्पण है जो सरकार की नीति, सरकार की योजना तथा सरकार की नीयत को बताता है। अगर हम इस 4 साल के समय को देखें तो पुरानी सरकार के बजट का लक्ष्य 2100–2200 करोड़ तक निर्धारित था जो लगभग 2000 करोड़ से फालतू कभी नहीं गया लेकिन इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। आज हरियाणा का बजट मुख्यमंत्री जी की दूर दृष्टि, उनके विजन और वित्त मंत्री जी की काबलियत तथा दक्षता के बदौलत, यह रिकार्ड है मेरे ख्याल में, मेरी जानकारी के मुताबिक तो हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ जो 10 हजार करोड़ रुपये का बजट तकरीबन छ गुणा चार साल में बढ़ा हे। यह उनकी एक बेहतरीन सोच, एक विजन और काबलियत का एक नतीजा है कि उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इतना सुदृढ़ करने का प्रयास किया

है। उन्होंने सब संस्थानों को एक ठीक परिपेक्ष में संतुलित दृष्टि से दोहन करते हुए प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर ले जाने का एक खाका और दर्पण तैयार किया है। यह अपने आप में एक मिसाल है। चेयरमैन महोदय, मैं इस बजट में समग्र विकासपूर्ण, संतुलित और दूरदर्शितापूर्ण, पूर्ण शब्द अभी नहीं लगाना चाहता क्योंकि विकसित चीज वह होती है जो विकास की बुलंदियों तक पहुंच जाये और आगे विकास की गुँजाइश न रहे। लेकिन विकास की बुलंदियों तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशन किया है और आज उसका नतीजा है कि हम देश में कई क्षेत्रों में पहले नम्बर पर रफ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के कारण ही इन चार वर्ष मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने अनेक ऐसे एतिहासिक फैसले लिये हैं वे इतिहास में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। चाहे किसानों और गरीबों की ऋण माफी की बात है, चाहे 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफी की बात है। किसानों के ऊपर बिजली के बिल एक तलवार की तरह लटक रहे थे उन बकाया बिलों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक दिन में माफ कर दिया। चेयरमैन सर, इसके अतिरिक्त चाहे पैंशन भत्ते बढ़ाने की बात हो या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले भाईयों और एस०सी०, बी०सी० के भाईयों को फायदा देने की बात हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी सभी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। जो हमारे गरीब और हरिजन बच्चे हैं उनकी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने वजीफे की राशि में भी काफी बढ़ौत्तरी की है। इसके अतिरिक्त गरीब वर्गों को समाज

में उचित स्थान देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको रिहायशी प्लाट भी दिए हैं। इससे पहले 40 साल पहले गरीब वर्ग के भाईयों को रिहायश के लिए खाट मिले थे। हम सभी जानते हैं कि जीवन यापन करने के लिए रोटी–कपड़ा और मकान बुनियादी जरूरत है और यह हर आदमी का अधिकार भी है इन सभी बातों की तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। इन बातों के बारे में सोचते हुए और देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है जिसमें कुछ कैटेगरिज को शामिल किया गया है जिनको सरकार की तरफ से 100– 100 गज के प्लाट दिये जायेंगे। सरकार ने यह एक एतिहासिक कदम उठाया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। चेयरमैन सर, मैं बजट के बारे में कहना चाहूँगा कि वर्ष 2008–09 में बजट की प्राप्तियां और खर्चे के लिए विपक्ष के कुछ माननीय साथियों ने कल सदन में कुछ जिक्र किया था। मैं तो इनकी बात समझ नहीं पाया। इन्होंने कल कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं तो कर दी लेकिन उनके लिए पैसे का बजट में प्रावधान नहीं किया गया। वे कह रहे थे कि चुनाव सिर 'पर हैं इसलिए यै घोषणाएं कर दी गई। मैं माननीय विपक्ष के साथियों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वे स्वयं देख लें कि उनके समय में बजट दो हजार करोड़ रूपये तक पहुंचा था और आज हमारी सरकार के समय में कहा तक बजट पहुंच गया है। इनको इस तरफ भी देखना चाहिए कि हमारा बजट कभी 50 प्रतिशत, कभी इससे भी ज्यादा और कभी उससे भी ज्यादा निरंतर इकीज हो रहा है। इस तरह से

अगर सरकार का खजाना भरा हुआ है तो लोक हित के काम करना सरकार का पहला दायित्व है। प्राप्तियों का जिक्र करते हुए बताया गया हे कि वर्ष 2010 में तकरीबन 34 ,935 हजार करोड़ रूपये की प्राप्तियां हो जायेंगी। संसाधनों को जुटाना सरकार का काम है। चेयरमैन सर, जो बजट घाटा पिछली बार दर्शाया गया था उससे कम पर खत्म हुआ है। बजट घाटा बढ़ा नहीं है बल्कि उसको पूरा किया गया है। सरकार के खजाने की सेहत इतनी ज्यादा बेहतर है तो यदि सरकार जरूरतमंदों को, उस जनता को जिस जनता ने हम से अपेक्षा की है और ताकत दी है, उसके भले के काम करने के लिए 700–900 करोड़ रुपये का पैकेज देती है तो क्या गलत किया है। अगर 700–800 करोड़ रुपये के पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिये हैं तो फिर उनको कैसे नकारा जा सकता है और कैसे इसको इलैक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है क्योंकि इलैक्शन तो महज एक इत्तेफाक है, इलैक्शन तो आना ही था। सभापति महोदय, जिस तेजी के साथ हमारा बजट बढ़ना चाहिए था वह तो उसी तेजी के साथ बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा है और प्रोग्रेसिव सोच है। यह सब उसी का परिणाम है। सभापति महोदय, अब मैं कृषि के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने कृषि के बारे में बहुत जिक्र किया है। सभापति महोदय, अगर सरकार की सोच किसान के प्रति सही न हो तो उससे किसान के साथ–साथ पूरे राज्य का नुकसान होता है। सभापति महोदय, पांच साल पहले का हिसाब आप देखिए और उससे पहले की सरकारों द्वारा गेहूं और धान के साथ–साथ अन्य

फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राईस में 5–5, 7–7 और 10– 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाती रही है और इससे ज्यादा का कभी इजाफा नहीं हुआ। लेकिन पिछले चार वर्षों के दौरान सभी फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राईस में 70 प्रतिशत से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। यह अपने आप में एक रिकार्ड है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा करके जो किसानों के प्रति सद्भावना दिखाई उसकी हमारे विपक्ष के साथियों को भी तारीफ करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार के अच्छे कामों की तारीफ किस प्रकार से की जानी चाहिए यह हमारे विपक्ष के साथियों को श्री रामकुमार गौतम जी से सीखना चाहिए। सभापति महोदय, जब हरियाणा बना तो उस समय हमारी खाद्यान्न की पैदावार 26 लाख टन थी जबकि इस वर्ष नहरी पानी और ट् यूबवैल्ज के लिए बिजली की बेहतरीन उपलब्धता से खाद्यान्न की पैदावार निरंतर बड़ी है। इस साल बारिश नहीं हुई जो कि खेती की सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा साधन है वह पिछले साल तो अच्छी हुई थी लेकिन इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई है। हमारी सरकार ने इस साल 157 लाख टन के खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभापति महोदय, हमारा खाद्यान्न उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है यह हमारी सरकार द्वारा करवाई गई बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था के कारण सम्भव हो पाया है। सभापति महोदय, हमारी कृषि व्यवस्था ज्यादातर बारिश पर निर्भर है। अगर हमारे हरियाणा प्रदेश में सही–सही बारिश हो जाये तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन और भी बढ़ सकता है। फिर यह

हमारी सरकार के बेहतर प्रयासों के कारण सम्भव हुआ है कि बारिश की कमी के बावजूद भी हमारा खाद्यान्न उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। यह सब एक बेहतरीन बिजली और सिंचाई व्यवस्था का ही परिणाम है। इसके लिए हमारी सरकार निः संदेह बधाई की पात्र है। सभापति महोदय, वैसे तो केन्द्रीय पूल में पंजाब सबसे ज्यादा हिस्सा खाद्यान्न के रूप में जमा करवाता है लेकिन अगर क्षेत्रफल के अनुपात के हिसाब से देखा जाये तो हरियाणा प्रदेश का हिस्सा थोड़ा बहुत ज्यादा ही बैठेगा। सभापति महोदय, आज के लिए मेरा एक सवाल लगा हुआ था लेकिन प्रश्नकाल समाप्त हो जाने के कारण मेरे सवाल का जवाब अधूरा रह गया था। सभापति महोदय, यह हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच रही है कि जिस किसान से हम एक बार उसके पुरखों की जमीन ले लेते हैं उसे अच्छा मुआवजा दिया जाए। सभापति महोदय, हमारा किसान जमीन को मां के रूप में देखता है। किसान को उसकी जमीन का मुआवजा पुराने जमाने में दो, ढाई और तीन लाख तक का मुआवजा मिला करता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकमुश्त तौर पर यह फैसला किया और जो देश में सर्वाधिक मुआवजा था वह दिया, जिसमें अलग–अलग कैटेगरी बनाई और कैटेगरीवाईज 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख और 25 लाख ब्याज वगैरह मिलाकर हम किसान को देते हैं। उस समय यह देश में सर्वाधिक होने के साथ–साथ एक मिसाल भी था। सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे सवाल के बारे में बाद में मुझे बताया कि जो सैंट्रल एजेंसी है

वह 15 हजार सालाना का रॉयल्टी के रूप में देने पर विचार कर रही है।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): सभापति महोदय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह जमीन एक्वायर की है कोई एकी देने के बारे में विचारकर रहे हैं। यह बात अभी फाईनली डिसाईड नहीं हुई है। जब भी यह डिसाईड होगा माननीय सदस्य को उसकी जानकारी दे दी जायेगी यह अंडर कसीड़ेशन है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः सभापति महोदय, मुझे पता नहीं है कि ये पॉलिसी पहले थी कि किसान को जमीन के अनुपात की दृष्टि से कम है तो छोटा और अगर ज्यादा है तो बढ़ा भी दिया जाता था। रैजीडैशियल जोन में या इण्डस्ट्रियल जोन में वह पालिसी इस समय है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सभापति महोदय, अगर यह पॉलिसी अब नहीं है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसको लागू रखना चाहिए। सभापति महोदय, आज के बदलते परिवेश में पूरे देश में बड़ी–बड़ी कम्पनियों के आ जाने से और बेशुमार निवेश होने के कारण जमीन की कामतों में बेतहाशा तेजी आई हे। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश में तो चहुंमुखी विकास के द्वार ही खुल गये हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सब इसी की बदौलत है कि हम आज आर्थिक दृष्टि से इतने सुदृढ़ हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसान की जमीन की कीमत प्राईवेट

कम्पनीज ने एक–एक और सवा–सवा करोड़ रुपये प्रति एकड़ दी है। सभापति महोदय, जो पैरीफैरल एक्सप्रैस हाइवे है इसके लिए जो जमीन एक्वायर की गई है इसका मुआवजा बहुत थोड़ा है। अगर हम अपने पड़ौसी राज्य के द्वारा इस परपज के लिए एक्वायर की गई जमीन के लिए दी गई कीमत को देखें तो हमें भी इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, पड़ौसी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किसानों की दो–तीन कैटेगरीज बनाकर तकरीबन 35 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है और इसके साथ उनके द्वारा 7 परसैंट प्लॉट रैजीडैंशियल और कमर्शियल एरिया में दिया जाता है या अगर किसान 10 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा लेना चाहे तो 10 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा और खास 17 परसैंट पूरी डैवेल्पमैंट के साथ रैजीडैंशियल और कमर्शियल एरिया में प्लॉट उसको दिया जाता है। सभापति महोदय, इस योजना से किसान के एक एकड़ की कीमत कम से कम एक करोड़ और कहीं–कहीं एक करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाती है। सभापति महोदय, इसी प्रकार से सड्कों के विषय में बहुत चर्चा हुई है। किसी प्रदेश या देश के लिए सड्कों का जाल उस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा आधार है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जितना देश का यह तंत्र मजबूत होगा उतनी ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसमें कोई दोराय नहीं है। मौजूदा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ द्वारा इन 4 वर्षों में 2005 से 2000 तक तकरीबन 3600 करोड़ रुपये सड्कों पर खर्च

किए हैं। वर्ष 2009– 10 के लिए 1504 करोड़ रुपय का प्रावधान इस तंत्र को मजबूत करने के लिए किया गया है। सभापति महोदय, इसमें कोई दोराय नहीं कि काम भी हुआ है। सभी साथियों की शिकायत भी रही है और मांग भी रही है कि आज हम जो काम करें वह समयबद्ध तरीके से हो और क्यालिटीवाईज हिसाब से भी अच्छा काम हो तो डस पैसे का सदुपयोग होगा।

श्री सभापतिः चौधरी साहब, एड्रैस दी चेयर। फिर वे खड़े हो जायेंगे, एड्रैस दी चेयर।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः सभापति महोदय, मैं मूल जाता हूं। सभापति महोदय, उसके लिए जिला स्तर पर हर जिले में एक कमेटी बने जिसमें एक मिनिस्टर औंर उसके साथ जितने मैम्बर अधिकारी भी हों, जनप्रतिनिधि के रूप में एम०एल०ए० भी हों। एक विजिएलैंस कमेटी जो मानिटरिंग भी करे दोनों काम करे, बनानी चाहिए। वह कमेटी समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता की दृष्टि से उसको चौक करे और उनके ऊपर उनकी राय सुनिश्चित भी करे और उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाये।

श्री सभापतिः चौधरी साहब, आप कंकल्यूड कीजिए। नो रनिंग कमैंट्री।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः सभापति महोदय, मैं उद्योग के विषय में भी बात कहूँगा। इण्डस्ट्री और खेती ये अर्थव्यवस्था के दो बड़े आधार हैं। हमारी उद्योग की स्थिति आज यह है कि

हमारी औद्योगिक पॉलिसी ने भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा आधार दिया है। एक जमाने में तो हमारे प्रदेश में उद्योग एक ही अंक में हुआ करते थे लेकिन आज हमारे यहां तकरीबन 1350 मझले और बड़े उद्योग हैं और अस्सी हजार के करीब छोटे उद्योग हैं जो कि निरंतर प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। (विघ्न) चेयरमैन सर, इस बात के लिए तो मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि रोहतक और फरीदाबाद में आई०एम०टी० बनानें जा रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो कुण्डली मानेसर इस्टर्न और वैस्टने पैरिफेरल जो एक्सप्रैस हाईवे है यह प्रदेश को कमर्शियल और व्यवसायिक दृष्टि से एक बहुत ही मजबूत आधार प्रदान करता है इसके लिए मैडिसिटी और एजुसिटी सोनीपत, झज्जर और रोहतक मैं स्थापित कर रहे हैं। सोहना और दमदमा में साईबर सिटी जिसमें टूरिज्म बहुराष्ट्रीय सूचना केन्द्रों का विकास हम यहां पर कर रहे हैं। चेयरमैन सर, मेवात मे चमड़ा उद्योग के बारे में जैसे मेरी जानकारी है अगर वह सही है तो मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि पलवल में कन्टेनर या ट्रांसपोर्ट हब, यह तकरीबन चौथे दर्जे का विकास है। आपके माध्यम से सरकार से मेरी प्रार्थना है कि पलवल से लेकर बल्लभगढ़ तक जो ईस्टर्न साईड है इस पर ऐसे प्रोजैक्ट्स की शायद ही कोई योजना बनाई जा रही है। अब आई .एमटी. एक ऐसा प्रोजैक्ट है जिसमें मॉडर्न और बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर हम इण्डस्ट्रीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिससे

अच्छी इण्डस्ट्रीज स्टेट में अट्रैक्ट कर सकें (विघ्न) चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मेरी यह गुजारिश है कि उसको भी इसी तर्ज पर ऊंचे दर्जे की जो प्रौद्योगिकी है उसके आधार पर मान्यता दी जाए चाहे वह आर०एन०डी० है चाहे एजुसिटी है या मैडिसिटी है उस इलाके में भी इतना जरूर किया जाए (विघ्न)।

श्री सभापतिः अब आप कंकलूड करें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः चेयरमैन सर, आप मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री सभापतिः आप यह सब लिख कर दे दीजिए वह रिकार्ड पर आ जाएगा अब आप कंकलूड करें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः चेयरमैन सर, शहरी और ग्रामीण विकास के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। शहर और देहात हमारे देश में दो ही क्षेत्र हैं इनमें संतुलित और समुचित विकास को देखते हुए बजट में प्रोविजन भी अच्छा किया गया है। तकरीबन 1334 करोड़ रुपये शहरी विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए भी 989 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चेयरमैन सर, मैं समझता हूँ कि इस राशि में तकरीबन इस बार 65–66 परसैंट इजाफा है जो एक अच्छा इजाफा है। अनियमित कॉलोनीज के बारे में काफी जिक्र चला है इसलिए इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि लगी–झोपड़ी के बसाव और पुनर्स्थापना करने का मेरा सवाल था लेकिन समय समाप्त हो जाने के कारण वह सवाल बीच

में ही रह गया। इसके लिए में अर्ज करना चाहता हूँ अनएथोराईज्ड कॉलोनीज के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा भी की है। अनएथोराईज्ड कॉलोनीज क्यों बनती हें, क्यों बढ़ती हैं? उसका कारण है इण्डस्ट्रीज का बढ़ना। इण्डस्ट्रीज के बढ़ने के साथ हम यह नहीं सोचते कि मकानों की कितनी जरूरत पड़ेगी। आबादी के लिहाज से हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण है शहरों की तरफ लोगों का बढ़ता अट्रैक्शन। इसलिए भी लोग शहरों की तरफ भागते हैं। (विघ्न) चेयरमैन सर, अब मैं फरीदाबाद की बात कहना चाहता हूँ। निगम की हमारी स्थिति यह है कि फरीदाबाद में तकरीबन 51 ऐसी कॉलोनीज हैं जिनके बारे में कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे। इसमें हाई कोर्ट का स्टे है। चेयरमैन सर, हाई कोर्ट का स्टे इनके मुताबिक वर्ष 2007 में आया है। 2005 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और मार्च, 2006 में सर्वे किया गया। चेयरमैन सर, जब दिल्ली सरकार ने 1600 कालोनीज का कोर्ट की बाध्यता होने के बावजूद एक रास्ता निकाला है तो क्या उनसे सीखते हुए हरियाणा सरकार भी वैसा ही कोई रास्ता निकालेगी? फरीदाबाद के लिए यह बहुत ही भारी समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के लिए बहुत कुछ किया है। (विघ्न) यहां पर बहुत से पैसे दिए हैं और काम भी हो रहे हैं लेकिन अन–अथोराईज्ड कालोनीज और लगी–झोपड़ी दो हिस्से ऐसे हैं अगर उनका विकास नहीं होगा तो जो यह सरकार विकास कर रही है, वह विकास वहीं पर सीमित रह जाएगा। आज फरीदाबाद में रोड़ी और बजरी की कीमतें 50 प्रतिशत से 100

प्रतिशत तक बड़ी हैं। यह वहां पर पहाड़ की लीज खत्म होने की वजह से हुआ है। आने वाले समय में गर्मी का मौसम आएगा और तब तो इनकी कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अगर वहां पर लीज खत्म हो गई तो सरकार उस काम को अपने हाथ में ले ले। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्ज से वहां 250 क्रैशर्ज उठा दिए गए हैं और वहां पर फ्रैशर आज दम तोड़ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको किसी और जगह पर लगाया जाए। इसी तरह से जो आबकारी नीति बनाई गई है उस के अन्तर्गत जहां पर भी कन्या गुरूकुल हैं, वहां पर शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि क्या यह नीति कन्या गुरूकुल तक सीमित है या जहां गांवों में मैट्रिक और प्लस टू की कन्याओं के स्कूल हैं वहां पर भी इस नीति को शुरू करेंगे? इसी तरह से यहां पर जोहड़ों का सवाल आया था और मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बारे में आश्वासन भी दिया था। मैंने इस बारे में कुछ सवाल सदन में उठाए थे और उसके बारे में जो डिपार्टमैंट की तरफ से हिन्दी में जवाब आया था वह बहुत ही गल्त दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद कि जो भी जोहड़ गांव की आबादी के बीच में आ जाएगा उसको पक्का कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद भी जब वहां पर सर्वे किया गया तो उसकी गलत रिपोर्ट दे दी गई और जवाब में कहा गया है कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप उसकी जांच करवाएं।

श्री सभापतिः आप इस बारे में मंत्री जी को लिखकर दे दें। अब आप बैठिए। बलवन्त सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे।

श्री बलवन्त सिंह चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी महेन्द्र प्रताप सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि इन्होंने बोलते हुए कहा कि पड़ौसी राज्य ने 35 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया था। मैं चाहता हूँ कि ये इस बारे में क्लीयर करें। (विघ्न)

श्री सभापतिः बलवन्त सिंह जी, ये मंत्री नहीं हैं। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) डॉक्टर साहब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) राम कुमार गौतम जी आप बोलें। (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद):: सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। जहां तक बजट का सवाल है मैं समझता हूँ कि यह थोड़ा बहुत अच्छा है। इसमें कई डिपार्टमैंटस में इम्प्रूवमैंट की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हैं वह भी बहुत बढ़िया हैं। मैं कहता हूँ कि वे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। वैसे तो सभी लोग इस बारे में कह चुके हैं लेकिन विशेष तौर से उन्होंने जो हमारे बुजुर्गों को सम्मान दिया है, वह काबिलेतारीफ है। पहले कई सालों से ऐसा चल रहा था कि बुजुर्गों को पता ही नहीं होता था इसलिए वै तो कहते थे कि मैं तो अपना वोट ताऊ को ही दूंगा

क्योंकि उनकी पार्टी पेंशन वाली पार्टी है। चेयरमैन सर, ऐसी फीलिंग लोगों की थी। मुख्यमंत्री महोदय ने जो बुजुर्गों की पेंशन पहले 200 रुपये से 500 रुपये और फिर 500 रुपये से 700 रुपये की है वह काबिलेतारीफ है। (विघ्न)

डा० सुशील इंदौराः चेयरमैन सर,.....

श्री सभापतिः जो भी डॉक्टर इंदौरा जी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): चेयरमैन सर, इस सरकार ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिनके बारे में कोई शक नहीं है, वे काबिलेतारीफ हैं। हम अपोजीशन के लोग या कोई और लोग अगर गलत भावना से कितना ही क्रिटीसाईज करें, वह अलग बात है लेकिन ये असल में काबिलेतारीफ बातें हैं। विधवाओं के लिए 550 रुपये पेंशन करना, 70 साल की उस के बुजुर्गों के लिए 500 रुपये से 700 रुपये और 60 साल की उम्र के बुजुर्गों के लिए 500 रुपये में हर साल 50 रुपये की वृद्धि करना, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाना, ट्रैक्टर लोन के लिए सिर्फ एक एकड़ जमीन का रहन करना, ये सब काबिलेतारीफ घोषणाएं हैं। इनके बारे में सारे कांग्रेसी भाई भी बता चुके हैं। चेयरमैन सर, जितनी भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं वे बहुत अच्छी हैं। विधवाओं के लिए पेंशन बढ़ाना, बेसहारा बच्चों का 200 रुपये भत्ता करना, विकलांगों की पेंशन बढ़ाना, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करना, पंच,

सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, नगर निगम के मेयर, उप मेयर का वेतन बढ़ाना आदि, ये सब बातें काबिलेतारीफ हैं। उन्होंने अब किसी को नारा लगाने का मौका ही नहीं छोड़ा है। उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। नम्बरदारों का भी मानदेय बढ़ाना, आगनवाडी वर्कर्ज का भी मानदेय बढ़ाना, हर स्कूल स्टेडियम में कोच एवं सपोर्टिंग स्टाफ रखना, शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के लिए भी राहत देना जो सबसे ज्यादा गरीब इश्वायी गांव का चौकीदार होता है, उसके लिए जो उन्होंने 1500 रुपये किए हैं तो ये सारी बातें काबिलेतारीफ ही हैं। चेयरमैन सर, हम भले ही विरोधी पार्टी में हैं लेकिन जो सच्चाई है उसको हम नकार नहीं सकते। चेयरमैन सर, मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी में भी कई सड़कें हैं जो इस सरकार ने मुख्यमंत्री जी के हुक्म से बनायी हैं। हमारी बहुत इम्पोर्टेंन्ट सड़कें, जैसे वास से पेटवाड़, पेटवाड़ से वकलाना, पेटवाड़ से वडाला सड़क तो बनने वाली है तथा पेटवाड़ से माजरा, माजरा से माढा, ढाणी कुमार से सिसाई रोड आदि सड़कें बनायी गयी हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल जो बहुत वर्षों से नहीं बने थे, इस सरकार ने उनको बनवाया हे। जो हमारे यहां के पुराने लीडर हुआ करते थे जो राज के मालिक थे, उनके जमाने में नारनौंद तक में गर्ल्ज का प्लस 2 का स्कूल नहीं था, वास में भी गर्ल्ज का स्कूल नहीं था लेकिन वे भी मुख्यमंत्री जी ने बनवाये। इसी तरह से नारनौंद प्रोपर में सिवरेज का काम चल रहा है, सड़क की फोरलेनिंग हुई है, ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड का नया रैस्ट हाउस बन रहा है,

तहसील की नयी बिल्डिंग बन रही है, थाने की नयी बिल्डिंग बन रही है, नया बस स्टैंड बन रहा है, इस तरह से कई अच्छे काम इस सरकार ने किए हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से कुछ जो इम्पोर्टैंट इश्यूज हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनमें से कुछ इश्यूज मेरी कास्टीच्यूएंसी के हैं कुछ हरियाणा के हैं। मेरी कांस्टीच्यूएंसी की तो चेयरमैन सर, कुछ छोटी–छोटी सी मांगें हैं जिनकी वजह से हमारे इलाके के लोग बहुत परेशान हैं, गांव के लोग भी बहुत परेशान हैं। छोटी सी बात थी जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को बार–बार प्रार्थना की लेकिन उन्होंने अभी तक कबूल नहीं की है। मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा सा समय रह गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गौतम भाई तेरे नारनौंद में कालेज बनाऊंगा और अगले बजट में बना दूंगा। मैं यह चाहूँगा कि अभी आन दी फ्लोर ऑफ दि हाउस 'आकर मुख्यमंत्री जी यह कहें कि नारनौंद का कालेज मंजूर कर दिया है। मेरी सबसे बड़ी मांग यह है। दूसरी मेरी मांग नारनौंद के चुटंग इलाके के बारे में है। वह हरियाणा का सबसे पुराना इलाका है वहां सब–डिवीजन हम चाहते थे। सारे इलाके की यह डिमांड है ताकि लोगों को अपने कामों के लिए इधर–उधर न भागना पड़े। मेरे हल्के की कुछ सड़कें बहुत इम्पोर्टैंट हैं। सड़क जो मुझे कन्वे करवाई थी उसके बारे में मेरे पास श्री के०के० खण्डेलवाल का लैटर आया था कि सीसर से वाया बडाला पेटवाड़ तक सड़क मंजूर कर दी है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक सिर्फ बडाला से पेटवाड़ तक सड़क मंजूर की

है। एक हमारे हांसी से जींद के स्टेट हाइवे की वाइडनिग बहुत ही जरूरी है। यह छोटी सी सड़क है और कई बार कहने के बावजूद भी नहीं बनी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सड़क राजली ब्रिज से खानपुर और डाटा गुराना तक है। एक मेरे हल्के में जो स्कूल है उसमें 18 कमरे बने हुए हैं। मेरे इलाके में सीसर गांव के भाइयों की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रखवाओ तो मैंने कहा कि मैं तो काग्रेसी नहीं हूँ तो उन्होंने कहा कि दीपेन्द्र हुड्डा जी को बुला दो। मेरे हल्के के लोग वहां गर्ल्स स्कूल को प्राइमरी से हाई स्कूल में अपग्रेड करवाना चाहते हैं, मेरी गुजारिश है कि यह जरूर बनवाइए। कुछ बातें प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में एक कमीशन आया था। पहले कमीशन आया था और बाद में जब चौटाला जी की सरकार आई तो उन्होंने उसे डले मारे और डिपो के डिपो जलवा दिये थे। चौधरी भजन लाल 1991 में मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की लेकिन जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और चुनाव आ गया तो उन्होंने 1995 में दो कैटेगरी बी०सी कए और बी०सी–बी के नाम से बना कर लागू किया। दस परसैंट रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के भाइयों को क्लास–।, 2, 3 और 4 में मिलता था। मैं यह मामला कई बार हाउस में उठा चुका हूँ। चौधरी भजन लाल ने उस समय पाप किया और उन बी.सी.ए. के बेचारे गरीब लोगों का गला काट दिया। बी०सी० –बी के लोग बहुत सम्पन्न हैं उसमें हमारे गुर्जर भाई महेन्द्र प्रताप जी, यादव भाई जैसे कैप्टन अजय सिंह यादव

जी और जो मेव भाई थे उनको भी उसमें इकट्ठा कर दिया। उसके बाद रिजल्ट यह हुआ कि 27 परसैंट जब छोटी नौकरियों में कर सकते थे जैसे क्लास– 3 और क्लास–4 में हुआ है तो क्लास–1 और क्लास– 2 में करने में क्या प्रौब्लम थी। जब आरक्षण सारे देश में लागू हो रहा था तो यहां भी क्लास– 1 तथा क्लास– 2 में भी 27 परसैंट आरक्षण लागू करना चाहिए था। उनको भी जो जीने का अधिकार है, वह तो उन्हें मिलना चाहिए। इन बी०सी–ए के भाइयों से कोई एम०एल०ए० नहीं था, एम०पी० नहीं था, अब जाकर राम प्रकाश जी राज्य सभा के मैंबर बने हैं, कम से कम दस परसैंट में क्लास बी के लोगों को शामिल तो न करते, यह मेरी मांग आपके मार्फत है। (विघ्न)

Mr. Chairperson : Hon'ble Ministers, No running commentary; No interruption please. Let him speak.

श्री राम कुमार गौतमः सभापति महोदय, पिछली सरकार के वक्त में तो एस०सीज० और बी कीज० की महिलाओं के लिए बजट ही नहीं था और इनके समय में तो एस०सीज०, एस०टीज० और बी०सीज० के भाइयों की ये शक्ल देखकर भी राजी नहीं थे। दस हजार का तो ये उस समय गरीब लोगों की नौकरियों में बैकलॉग ही छोड़ गए।

श्री रामफल चिड़ानाः चेयरमैन सर, अब भी 30 हजार से ज्यादा बैकलॉग बाकी है।

श्री सभापतिः आप नोट कर लें बाद में बता देना। अभी आप बैठ जायें।

श्री राम कुमार गौतमः इसमें एस०सीज० और बी०सीज० का बजट 1232 करोड़ रुपये खान का और 161 करोड़ रुपये नॉन प्लान का बजट, उसके मुकाबले में तो बहुत है। लेकिन फिर भी इन एस०सी० भाइयों के और बी०सी० भाइयों के हालात इतने खराब हैं। गांवों में जो छोटे दस्तकार हैं जैसे कोई लोहे की खराद पर काम करते हैं, किसी ने फर्नीचर का काम किया हुआ है, जो किसान के छोटे औजार बनाते हैं या उनकी रिपेयर का काम करते हैं जिन्होंने पांच हार्स पावर की बिजली की जिन्होंने मोटर लगा रखी हैं उनके बिल को भी किसान के ट्यूबवैल की बिजली के बिल के साथ जोड़ दिया जाए। आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है। (घण्टी) हालांकि मैं फाइनैंस मिनिस्टर की तारीफ करूंगा जो इन्होंने शराब के ठेकों में रिजर्वेशन कर दी है। मैं तो कहता हूँ कि सभी ठेकों में कर दी जाए ताकि ये लोग सम्पन्न हो जाएं इनको बसने का बराबर का अधिकार मिल जाए। इसके अलावा जो फालतू जमीन पड़ी है उसमें से गरीब आदमियों को 100– 100 गज के प्लाट देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया हे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके अलावा जो किसानों की जमीन का मुआवजा बढ़ाया है और किसान की फसलों के रेट बढ़ाये हैं। यह भी एक सराहनीय कदम है। ये गरीब लोग किसका खाट खरीदेंगे? जितनी सरप्लस सरकार

की जमीन पड़ी है या दूसरी सरप्लस जमीन पड़ी है, वह सब इन एस०सी० भाइयों को दे दी जाए ये मेरा सुझाव है। जब तक हमारे कमजोर तबके के भाइयों को बराबर का मौका नहीं मिलेगा हरियाणा प्रदेश और देश मजबूत नहीं होगा। जो पहले इम्पलाईज पिछली सरकार ने निकाल दिए थे जैसे कैनफेड, एम०आई०टी०सी० और इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के थे उन इम्पलाईज को वापिस लेकर मुख्यमंत्री जी ने दरियादिली दिखाकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है। (घण्टी) चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा समय और लूंगा। उनमें से कुछ इम्पलाईज छूट गये जिनमें से बहुत से तो अब रहे नहीं। कान्कास्ट के 225 इम्पलाईज थे जिनमें से 70–75 तो मर ऋ गये हैं या चले गये हैं अब तो 150 ही रह गये हैं। इन इम्पलाईज को भी अगर सरकार रि–इम्पलाई कर दे तो सरकार की बहुत दरियादिली होगी। सरकार का ये लोग बड़ा अहसान मानेंगे। पहले तो इन्होंने पिछली सरकार के गीत गाये। ये वर्ष 1998 में नौकरी से हटाये गये थे। लेकिन उस सरकार ने कुछ नहीं किया। उस सरकार ने कुछ नहीं दिया। इसी प्रकार से 1600 सिपाहियों ने पिछली सरकार की और कांग्रेस की रैली में भी हिस्सा लिया लेकिन उनको भी वापिस नौकरी में नहीं लिया गया। मेरा अनुरोध है कि उनको नौकरी में वापिस ले लिया जाए तो उनके घरों में भी चूल्हे जल जायेंगे और उनके घरों में रौनक हो जायेगी, उनको भी दोबारा से रोजगार देना चाहिए। हालांकि यह मामला कई बार पहले भी उठाया गया है लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी भी बाप की जायदाद है उसके बच्चों के नाम

ट्रांसफर करने लिए उसमें यह एनसैस्टरल प्रोपर्टी, या सैल्फ एक्यायर्ड प्रोपर्टी, ये नहीं होना चाहिए इसकी तरफ सरकार ध्यान दे। मैंने अपने भाई की जमीन की रजिस्ट्री करवाई। उस समय भाई–भाई की जमीन, बापू की खरीदी हुई जमीन, इसमें भी फर्क है, यह बहुत इम्पोटैट बात है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए साधारण तरीके से जिस एनसैस्टरल जमीन की कोलैक्टिव डिक्री करते थे। उसी तरह से ऐसी जमीन की भी रजिस्ट्री की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं उनके स्टैण्डर्ड में भी सुधार करना चाहिए। उसके लिए बजट काफी बढ़ाना चाहिए क्योंकि वे बच्चे आई०आई०एम० और आई०आई०टी० के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाते। कई लोग 100–100 गज की कोठरी ले रहे हैं और उसमें स्कूल खोल रखे हैं उनमें हजारों की संख्या में बच्चे चले जाते हैं। वहां बच्चों को बिठाने की भी जगह नहीं है। जबकि जो किले में स्कूल खुले हुए हैं वहां बच्चे जाते नहीं इसलिए इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सभापति महोदय, हैल्थ का बजट हालांकि काफी बढ़ाया गया है लेकिन आज हैल्थ की पोजीशन बहुत खराव है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में ज्यादा से ज्यादा 4– 5 अस्पताल हैं और उनकी हालत बहुत खतरनाक है। वहां न कोई डॉक्टर्ज हैं और न ही कोई और दूसरी सुविधायें हैं। अभी पीछे एजीटेशन करके बांस जो हमारे यहां का सबसे बड़ा गांव है वहां डॉक्टर लगवाए थे। सभापति महोदय, मेरा मानना है कि हर गांव में अस्पताल खुलने

चाहिएं। सभापति महोदय, वैसे तो अब काफी फर्क है फिर भी हालत बहुत खराब हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हैल्थ का बजट भी बढ़ाया जाए और इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टरों की रिकूटमैंट भी ज्यादा होनी चाहिए। सभापति महोदय, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को भी चुस्त दुरूस्त करने की जरूरत है। एक आर्डर किसी का भी कहीं जाता है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए क्योंकि उसका पता ही नहीं होता कि कहां गया। कई बार कोई पी०ए० उस आर्डर को बेचकर चाट पकोडी खा लेता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो शासन है वह पहले वाले शासनों में से सबसे ज्यादा काबिले तारीफ है इसमें कोई शक नहीं है। सभापति महोदय, आज हरियाणा में करप्शन इतना है जिसका कोई ठिकाना नहीं है इसको कंट्रोल करना आज समय की मांग है। जब तक हम एग्जम्पलरी पनिशमैंट नहीं देंगे तब तक ये जितने पुराने पालाटिशयंज हैं इनका कुछ नहीं हो सकता जो आज की लड़ाई लड़ रहे हैं, चला जाता नहीं, सौदा कुछ नहीं लेकिन इसके बावजूद करप्शन करके करोड़ों अरबों रुपये की हर शहर में इन्होंने जायदाद बना ली अगर इनको शुरू में ही गोला लाठी दे देते तो सौदा कुछ बचता ही नहीं। हर .आदमी डरता कि ये जो भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की हरियाणा की सरकार है यह कोई पपई का खेल नहीं है यहां जो करप्शन करेगा उससे हिसाब लिया जाएगा। कई अफसर ऐसे हैं जो जात पात का नारा भी दे देते हैं।

सभापति महोदय, जब तक करप्शन करने वाले ऑफिसर्ज को सजा नहीं मिलेगी तब तक करप्शन दूर नहीं होगा और तब तक सुधार होने की गुंजाइश नहीं होगी। आज सड़क बनती है और बनते बनते ही टूट जाती है। एच.आर०डी०एफ० का आधे से ज्यादा पैसा वेस्ट जा रहा है। इसकी इकवायरी करवाई जाए। इस तरह की बनी हुई सड्कों का सैम्पल करवाया जाए क्योंकि इस करप्शन ने बेड़ा गर्क कर दिया है। करप्शन को इस समय कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, हमारी पार्टी का और इनैलो का जो गठजोड़ हो रहा है यह चांद मोहम्मद और फिजा वाला हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, एक बात देखिए यह समझौता हमारा पहले भी हुआ था। हमारी पार्टी के जो बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनकी इच्छा थी उन्होंने समझौता कर लिया। मैं तो समझता हूं कि आजमाए ने अजमावे और अपनी ऐसी तैसी कराओ लेकिन समझौता कर लिया गलती कर ली लेकिन गलती करने के बाद ढाक के वही तीन पात हैं इनमें बदलाव नहीं हो सकता। समझौता हमारे साथ किया हैं और समझौता करने के बाद हमारे सारे कडीडेट्स को इन्होंने गण्डासा मारा। मैं भी उनमें शामिल हूँ। उस समय सारे मार दिए थे। उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने सारे हरियाणा को इस तरह लूटा जैसे तैमूरलंग राज ने महम को लूटा था। वे तैमूरलंग की तरह पूरे प्रदेश को लूटकर चले गये। उस समय उन्होंने हमारी पार्टी के एक नेता को भी नहीं बख्शा जिसको इन्होंने जलील न किया हो जिनकी बेइज्जती न की हो। आज भी

जिन लोगों ने इनके साथ समझौता किया है उनको भी उस समय जलील किया था, बेइज्जत किया था। मैं अपने नेताओं के खिलाफ बोलूं यह अच्छा नहीं लगता लेकिन इनको समझौता नहीं करना चाहिए था। चेयरमैन सर, समझौता होने से क्या बनेगा, कोई इनको पर्ची डालने वाला नहीं मिलेगा (हंसी)। जिस तरह से बिना टिकट का लैटर बैल लौट आता है उसी तरह से ये भी बैल ही आयेंगे। आडवानी जी हमारे नेता हैं और मेरे पितातुल्य हैं। लेकिन उम्र ऐसी आ जाती है वे क्या करें। (हंसी) चेयरमैन सर, कई बार आदमी से गलती हो जाती है और कहते हैं कि काटडे का आड़ पकड़कर घर बड़ गया था। वे समझते हैं कि किसी भी तरह से बात बन जाये और शासन मिल जाये लेकिन हमारे लिए किसी शासन से पहले हमारा देश है जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद प्रदेश मायने रखता है और उसके बाद हमारी प्रदेश की जनता मायने रखती है जिसके द्वारा हम यहां चुनकर आते हैं, पार्टी बाद में आती है। इन बातों की तरफ गौर करना चाहिए था लेकिन लोग तो शासन के पीछे हैं। इस देश में कोई कायदा कानून नहीं है। इनको तो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की तीन पीढ़ियों की फोटो अपने घर लगा लेनी चाहिए क्योंकि चार साल निकल गये मुख्यमंत्री ही रोजाना कहते हैं कि सी०बी०आई० जांच करेगी लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। हमें तो पता नहीं सी०बी० आई० कहां पर है? यदि मुख्यमंत्री जी एकदम से एक्शन लेते तो आज इनकी पार्टी ही नहीं दिखती। इनकी पार्टी नहीं है यह तो एक गिरोह है। इस तरह का गिरोह पैसु के समय भी था। उस

समय उस गिरोह को आर०एस० राव ने छांग कर रख दिया था। इनको भी छल कर रखना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री जी नेक और शरीफ हैं। अगर ये इनके खिलाफ कार्यवाही करते तो हमारे प्रदेश से करप्शन हमेशा के लिए बंद हो जाती। (विघ्न)

श्री सभापतिः गौतम जी, आप बजट पर बोलें और जल्दी ही वाईंड अप करें। (विघ्न) No interruption please.

श्री राम कुमार गौतमः चेयरमैन सर, मेरे इन भाइयों की हालत तो इस प्रकार की है कि जैसे कोई आदमी कुएं में फंस जाये तो रात होने पर वह यही सोचता है कि आज की रात तो किसी तरह कुएं में कट जाये। यही हालत इन भाइयों की हो रखी है।

श्री सभापतिः गौतम जी, आप बजट पर बोलें और जल्दी ही वाईंड अप करें। श्री राम कुमार गौतमः चेयरमैन सर, मैं प्लास्टिक के बैग्ज के बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार ने इन पर बैन लगा रखा है लेकिन ये फिर भी खुले आम बिक रहे हैं। इनको खाने से पशु बीमार हो जाते हैं और इनसे नालियां तथा सीवरेज आदि भी रुक जाते हैं इसलिए सरकार को सख्त एक्शन लेकर इन प्लास्टिक बैग्ज को बंद करना चाहिए। सभापति महोदय, इसके अलावा ये जो सी०एफ०एल० की मरकरी ट्यूब्स हैं इनकी डिस्पोजल का इंतजाम भै। सरकार को करना चाहिए क्योंकि ये इनसानी जिन्दगी के लिए बहुत घातक हैं। सभापति महोदय, मैंने

अपने नारनौंद में एक रिटेनिंग वील बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से रिकवैस्ट की थी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी और जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनवा दिया गया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, हमने जिस पुल पर इस रिटेनिंग वील को बनाने की मांग की थी वह पुल ज्यों का त्यों छोटा ही रह गया है। इसलिए जिस परपज के लिए हमने रिटेनिंग वील बनवाई थी वह पूरा नहीं हुआ।

Mr. Chairperson : Gautam Sahib, please conclude.

श्री राम कुमार गौतमः सभापति महोदय जो 100– 100 गज के खाट सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दिये जा रहे हैं यह भी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया कदम है। इस बारे में मैं यह बताना चाहूँगा कि कई जगह कुछ पंचायतें धरने पर बैठी हैं कि हम इस परपज के लिए एक गज भी जमीन नहीं देंगे। इसलिए मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि इसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाये क्योंकि जब तक सख्त कानून नहीं बनाया जायेगा तब तक गरीब लोगों को उनके प्लाट का कब्जा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से 1971 में जो प्लाट गरीब परिवारों को दिये गये थे उनमें से कई गरीब व्यक्तियों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर 100–100 गज के प्लॉट देने के लिए सरकार को जमीन एक्वायर करनी पड़े तो सरकार को जमीन एक्वायर करके गरीबों को प्लाट आबंटित करने चाहिएं।

श्री रामफल चिड़ाना: सभापति महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। सभापति महोदय, मैं बैकलॉग के बारे में बताना चाहता हूँ जो माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछली चौटाला सरकार द्वारा 50 हजार से ऊपर का बैकलाग पैंडिग था उस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज कांग्रेस की सरकार में 50 हजार से भी ज्यादा का बैकलाग पैंडिंग है। सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार को बैकलॉग को कम करने के उपाय करने चाहिएं थे। कांग्रेस सरकार द्वारा बैकलाग को बढ़ाया तो गया लेकिन कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये। यह बात भी माननीय सदस्य को कहनी चाहिए थी।

श्री नरेश मलिक: सभापति महोदय, मेरे साथी गौतम जी ने कई तरह की बातें की। मैं हरियाणा में भाजपा का नेता होने के नाते यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये भाजपा की कोई बातें न होकर माननीय साथी गौतम जी के निजी विचार थे। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह गौतम जी की इंडीविजुअल सोच है और भाजपा की इस तरह की कोई विचारधारा नहीं है।

श्री सभापति: गौतम साहब, आपका कोई प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है क्या? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम: चेयरमैन सर, पुराने समय में..... ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः गौतम साहव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मलिक साहब कहते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं क्या इस बारे में आपने कोई पत्र विधान सभा स्पीकर को लिखा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतमः सभापति महोदय, हमारे मलिक भाई ऐसे खानदान से हैं जिन को पुराने जमाने में मलिक बादशाह कहते थे। पुराने समय में ऐसा बताते हैं कि एक मलिक भाई की भैंस चोरी हो गई। एक–दो किलोमीटर दूर जाने के बाद उसने चोर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चोर ने कहा कि मलिक राजा साहब, आप इतनी दूर क्यों आये मैं तो वहीं पर छोड़ देता। इस बात पर मलिक साहब ने कहा कि जा ले जा तू भे के याद राखैगा। सर, मलिक साहब हमारे छोटे भाई हें, हमारे नेता हैं और हमारे प्यारे दोस्त हैं। जब मेरे लिए चिट्ठी लिख कर दे रखी थी कि आप सदन में भाजपा के नेता हैं तब भी ये कहते थे कि तेरे से पहले मैं बोलूंगा तो मैं भी कह देता था कि कोई बात नहीं मैं बाद में बोल लूंगा। लीडर तो सभापति महोदय, हम दो ही हैं बाकी सौदा तो म्हारा ठीकै ठीक है। लेकिन सर, जब गठबन्धन हुआ तो कई लोग बुलाये, कईयों के पास हम भी गये। यह छोटा भाई है यह भी गया उसमें इन्होंने भी कहा कि समझौता ना करो ये डाकू हैं। मैंने मलिक साहब से पूछा कि आप भी विरोध कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि भाई ईमानदारी से कहता हूं कि मैं तो आपसे भी आगे जाऊंगा, मैं तो विधान सभा से ही इस्तीफा दे

दूंगा। मैंने भाई को याद दिलाया कि क्या कह रहे हो तो इन्होंने कहा कि मेरी कोई मजबूरी है वह निकल लेने दो फिर मैं इनको देख लूंगा। (हंसी मजाक)

श्री भीमसैन मेहता (इन्द्री): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में पेश किया है मैं भी उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, यह ऐसा बजट है जिसकी हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सराहना हो रही है। इस बजट में हर क्षेत्र के विकास के कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है चाहे वह कृषि के क्षेत्र की बात हो, हैल्थ की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या चाहे नई सड्कों की बात हो, इसमें हर तरह से हर प्रकार के विकास का प्रावधान किया गया है। वैसे तो इन 4 सालों के अरसे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भी विकास के काम किये हैं इतने पहले कभी नहीं हुए और कई ऐतिहासिक फैसले लिये हैं आज जिनकी चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश और देश में की जा रही है। इसी तरह से जैसे 100– 100 गज के प्लाट देने की बात थी, इस बारे में हमारे विपक्ष के साथी गांवों में जाकर लोगों को कह रहे थे कि ये केवल घोषणाएं मात्र हैं और कुछ नहीं होगा। लेकिन सभापति महोदयय आज खुशी की बात है कि लोगों का सपना हकीकत में बदल गया है और उनको 100– 100 गज के खाट दिये जा रहे हैं। यह सब काम माननीय मुख्यमंत्री जी

की वजह से ही हो रहा है और वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी वहीं पर सरकार ने पानी की टंकी और कनैक्शन देकर अनुसूचित जाति के भाईयों के लिए पीने के पानी का प्रावधान करवा दिया है। इसी प्रकार से किसानों के लिए भी बहुत सी घोषणाएं की हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसकी चर्चा मेरे से पहले कई माननीय साथियों ने भी की है चाहे वह उनकी फसलों के भावों की बात हो, चाहे उनकी जमीन जो एक्वायर करने की बात हो। सभापति महोदय, पहले ऐसा कभी भी और किसी स्टेट में नहीं हुआ कि किसान की फसल बोने से पहले फसल के भाव तय कर दिये जायें लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना बोने से पहले ही उसके रेट तय करवाये, और रेट भी देश में सबसे ज्यादा दिये। इसी प्रकार से जमीनों के फ्लोर रेट तय किये गए हैं। पहले जो जमीन 2–3 रुपयों में बिकती थी आज उसी जमीन के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं। सभापित महोदय इस बारे में बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं मैं उनको दोहराना नही चाहता। आपने मुझे थोड़ा ही समय दिया है इसलिए मैं 2–3 बात अपने हल्के की रखना चाहूँगा। हमारे हलके में जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है वह यह है कि हमारे इन्द्री को सब–डिवीजन बनाने की घोषणा की है इसके लिए पूरे हलकावासियो की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं और उनको धन्यवाद देते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे तक की जो सड़क है उसकी हालत बहुत

खस्ता है। कुछ दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी से मिला भी था और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी ही इसको बनायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस सड़क की हालत को देखते हुए इसको जल्दी ठीक करवाया जाये। इसी तरह से हमारे हास्पीटलों की भी हालत खराब है और वहाँ पर कई चीजों की कमी है। जैसे हॉस्पीटलों में डॉक्टरों की कमी है और यंत्रों की भी कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पीटल्ज की हालत को सुधारा जाये। सारी की सारी घोषणाएं जो हुई हैं वह पूर्ण रूप से सराहनीय हैं। चेयरमैन सर, मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सराहनीय बजट पेश किया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया।

12.00 बजे

श्री रामकिशन फौजी (बवानी खेड़ा): चेयरमैन सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। (इस समय माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर सर, आज से चार साल पहले माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने इस विधान सभा के पटल पर चार बजट प्रस्तुत किये हें। चारों बजटों में हरियाणा प्रदेश के लोगों में बड़ी

खुशियां आई, लोग खुशहाल हुए, गरीबी दूर हुई। बजट से किसान का भला हुआ, मजदूर का भला हुआ और हर समाज और जाति का ध्यान रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब चार साल पहले कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनी वह सरकार जब लोगों ने बनाई थी तब लोग खुश नहीं थे। वह लोगों ने खुश होकर नहीं बनाई थी क्योंकि जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार रही उन छः सालों के दौरान प्रदेश में ज्यादतियां, जुल्म, लूट, खसूट इतनी चरम सीमा पर थी कि उनसे लोग बड़े तंग थे। जब लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई तो लोगों ने आस रखी कि यह सरकार काम करेगी। यह सरकार बनने से पहले लोग जो काम सोच भी नहीं सकते थे वे काम चौधरी भूपेन्द्र सिंह की सरकार ने करके दिखाए। चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी ने ऐसे–ऐसे फैसले लिये कि कोई सोच भी नहीं सकता था। चाहे बिजली के 1600 करोड़ रुपये के बिल माफ करने की बात हो, चाहे छोटे दुकानदार की कर्ज मुआफी की बात हो, चाहे ब्याज मुआफी की बात हो या 100– 100 गज के प्लॉटस देने की बात हो, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ बताया। चौधरी भूपेन्द्र सिंह की सरकार ने इतनी कामयाब घोषणाएं कीं कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी इन्सान यह नहीं कह सकता कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह की सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किये हैं उनके बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जनता मुख्यमंत्री जी को

उनके द्वारा किये गये कामों का मैडल देगी और फिर से इनकी सरकार बनाएगी ताकि हरियाणा प्रदेश और भी खुशहाल हो सके। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और सरकार ने जो काम किये हैं उनको लोग एक मैडल देंगे जैसे कि हमारे खिलाड़ी देश और 'विदेशों से 'आज खेलों में मैडल लेकर आते हैं। स्पीकर सर, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है और न कोई कार्यक्रम। इनके पास एक ही रटी–रटाई बात है कि जो घोषणाएं हैं उसे बारे में हमें शंका है कि वे पूरी की जाएंगी या नहीं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है लेकिन इतना जरूर कहना है कि इस सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी करके दिखाई हैं। स्पीकर सर, अब ऐसी–ऐसी घोषणाएं होंगी कि ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। (विघ्न) आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का काम देखें। हमारे कुछ पुराने साथी यहां पर बैठे हुए हैं और वे इनका काम देखकर वापिस आएंगे। (विघ्न) इस सरकार ने अच्छी घोषणाएं की हैं और अच्छा बजट पेश किया है। इस सरकार ने हांसी बुटाना नहर का फैसला किया है। उसकी वजह से जहां पर किसान पानी की एक–एक बूंद के लिए तरस रहा था, इस सरकार ने उसकी आखिरी छोर तक पानी पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा एरिया रेतीला है और राजस्थान के साथ लगता एरिया है। आज वहां पर दो हफ्ते पानी चलता है। भूपेन्द्र सिंह जी ने अब जो घोषणाएं की हैं वे इन्होंने पूरी करके दिखाई हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि इनका नाम हरियाणा के इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखना

चाहिए। स्पीकर सर, हमारे हरियाणा में ऐसी भी सरकारें आई थीं जिन्होंने हरियाणा को खोखला कर दिया था। आज इस सरकार के अच्छे कामों से, लोगों के लिए अच्छी घोषणाओं की वजह से हमारा हरियाणा फिर से खुशहाल हो गया है, यह इस सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है। स्पीकर सर, इसी के साथ मैं सदन में यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने यह जो 100– 100 गज के प्लाट दिए हैं, इन प्लाटों को वे लोग 100 गज के नहीं मानते हैं बल्कि ये प्लाट उनके लिए 1000 गज के हैं। इससे बहुत लोग खुश हैं। इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग किन्हीं कारणों से पहले ये खाट नहीं ले सके थे उनको दोबारा से फार्म भरने का मौका दिया जाए ताकि उन गरीब लोगों का फायदा हो जाए। स्पीकर सर, आज गांवों में कंक्रीट की गलियां बन गई हैं जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने घर के आगे की गली कंक्रीट बनवा ली थी लेकिन इस सरकार ने हर गांव में बनवाई है। (विघ्न) मेरा इस बारे में निवेदन है कि ये जो कंक्रीट की गलियां बनवाई गई हैं तो वहां पर नालियों का कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये जो गलियां कंक्रीट की बनाई गई हैं वहां पर नालियों का भी प्रोवीजन किया जाए। इसके साथ ही हमारी बयानी खेड़ा की नगरपालिका बैकवर्ड नगरपालिका है। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं। हमारे सुरजेवाला जी ने यहां पर बोलते हुए कहा था कि इन्होंने 25 नगरपालिकाओं को लिया है तो मैं आपके माध्यम से

निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी नगरपालिका को भी उन 25 नगरपालिकाओं में शामिल किया जाए। स्पीकर सर, आज गन्ने के बहुत बढ़िया भाव दिए गए हैं। आज किसानों को हर किस्म के बीजों पर सब्सिडी दी जाती है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस तरह से गेहूं सरसों और दूसरे बीजों पर सब्सिडी दी जाती है उसी तरह से गन्ने के बीज पर भी सबसिडी दी जानी चाहिए ताकि गरीब किसान भी उनकी बोआई कर सकें तथा गन्ने की पैदावार और ज्यादा हो सके। स्पीकर सर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी कि जो एस०सी० पशु रखता है तो उसके उस पशु का बीमा किया जाएगा। लेकिन मुझे पता चला है कि उस बीमा योजना को बंद कर दिया गया है। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उस बीमा योजना को दोबारा से शुरू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हमारे बहुत से लोन माफ किए हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते थे वह काम भी उन्होंने किया है। वे हमारी सोच से भी आगे की सोच रखते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि वे पता नहीं किस समय कौन सी घोषणा कर दें। आज किसान बहुत खुश है इसलिए अब तो हम मुख्यमंत्री जी से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मेरा दूसरा निवेदन है कि जो लैंड मोर्डगेज बैंक हैं उनकी सहायता से एस०सीज० के लोग जमीन खरीदते थे क्योंकि उनको लैंड परचेज के लिए लोन मिलता था। पहले उनको आधे एकड़ के लिए या एक एकड़ जमीन

खरीदने के लिए लोन मिलता था। लेकिन अब मेरी नालेज में आया है कि पिछले दिनों से वह लोन देना बंद कर दिया गया है। अब एस०सीज० के लोग इस लैंड मोर्डगेज बैंक से लोन नहीं ले सकते। मेरा निवेदन है कि इसको दोबारा चालू किया जाए ताकि गरीब आदमी इस बैंक से लोन लेकर अपनी जमीन ले सकें। इसके अलावा जो वाटर वर्क्स हैं वे पिछली बार जब फ्लड आयी थी उसकी वजह से खराब हो गये थे। मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक ऐसी ड्रेन बनाकर दी कि अब एक बूंद पानी भी नहीं रुक सकता। अब उसकी वजह से किसान को आगे जाकर भी पानी मिल जाता है जिसके कारण किसान आज बहुत खुश है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे दस गांव जैसे पून्हड, भैणी, सिवाणा आदि खत्म हो जाते। स्पीकर साहब, ओम प्रकाश चौटाला का जड़ राज था तो मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में मैं कह रहा हूँ कि उनके 6 साल के राज में कहीं पर भी एक दाना फसल का नहीं होता था क्योंकि वहां पर पानी न निकलने की वजह से बटेरा ही होता था। मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहने पर वहां पर एक ड्रेन निकाल दी। वहां पर 5–6 गांव जैसे अलखपूरा, भैणी ठाकरान और पून्हड आदि के वाटर वर्क्स फ्लड आने की वजह से खत्म हो गए थे जिसकी वजह से उनमें पानी नहीं रुकता था। अगर उनमें पानी रुकता भी था तो नीचे का जो फ्लड का खराब पानी आता है, वही रुकता था। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय से मिला था और उनसे कहा था कि जल्दी से जल्दी इन वाटर वर्क्स को बनाया जाए। अगर ये बन जाएंगे तो इनसे लोगों को बहुत बड़ी

सुविधा मिलेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत सी घोषणाएं की। हम इनके बारे में रात को भी बैठकर याद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें सच्चाई है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि गरीब लोगों की बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री जी ने 5 हजार रुपये से 15 हजार रुपये देने का ऐलान किया था लेकिन एक गरीब आदमी जो किसी भी जाति या समाज से हो सकता है, अगर उस गरीब की बेटी की शादी होती है तो वह तभी शुद्ध मानी जाती है जब कोई सोने का गहना डाल दिया जाए। लेकिन गरीब आदमी सोने का गहना नहीं डाल सकता इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी सरकार की तरफ से गरीब की बेटी की शादी में सोने का हार भी डालने का प्रबंध करवा दें ताकि गरीब की बेटी की शादी शुद्ध हो जाए और वह मौज करे। अगर ऐसा हो जाएगा तो उनका भला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और मैं ज्यादा न कहकर आपका और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

चौ० अर्जन सिंह (छछरौली): स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए टाईम दिया। वैसे तो इस बजट पर बोलने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि सारी बातें तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही पूरी कर दी हैं। हम सिर्फ इनका धन्यवाद और सराहना ही कर सकते हैं। जो भी सुझाव कोई लेकर आता है उससे पहले ही ये उस बारे में एनाउसमैंट

कर देते हैं इसलिए मैं तो सरकार का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने इन भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि मांगो उसी से जो दे खुशी से, उससे क्या मांगना जो दु:खी हो औरों की खुशी से। सर, ये तो लोगों को सुखी देख ही नहीं सकते। मैं इनका एक काम बताना चाहता हूं। पहले मुख्यमंत्री तो गड्डी में अपने नाम के पत्थर लिखवाकर रखा करते थे। लोग यदि कुछ मांगते थे तो उनको वे ये पत्थर दे देते थे क्योंकि उनके पास लिखे हुए पत्थर होते थे। काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। इलैक्शन के टाईम में इनके पास गड्डियां बहुत होती थीं। वे उस समय दो गड्डियां अपने नाम के पत्थरों की भरकर रखा करते थे। अभी बुढ़ापा पेंशन के बारे में मेरे पड़ोसी भाई जिक्र कर रहे थे लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे पहले ही जो उनकी उम्मीद थी वह भी और जो इनकी उम्मीद से ज्यादा थी, उनकी भी साथ के साथ घोषणा कर दी। ये कहा करते थे कि हमने 100 रुपये से 200 रुपये पैंशन कर दी। ठीक है, 100 रुपये से 200 रुपये पेंशन इन्होंने करी है और फिर 200 रुपये भी करी थी लेकिन वह दी अगली सरकार ने थी। स्पीकर साहब, ये उन 200 रुपये का भी क्या किया करते थे। जब बुढ़ापा पेंशन गांव में बंटती थी तो पीछे पीछे यह मैसेज चला जाता था कि इस गांव में बुढ़ापा पेंशन जा ली है इसलिए मेरा प्रोग्राम वहां पर रखवा दो। सर, ताखडी में से नहीं, उठा शेर का पट्ठा, साथ के साथ सारा पैसा उठा लेता था। इनकी तो ताखडी टंगी रही,

खे के पास पेंशन तो गई ही नहीं। (विघ्न) पेंशन तो मिल ही नहीं पाती थी कि उनसे उल्टी ले लेते थे गैल की गैल ही ले लेते थे ऐसी पेंशन देने का क्या फायदा। आज के मुख्यमंत्री जी को देखें। किसी भी गांव में जाते हैं तो कोई माला नहीं, कोई थैली नहीं लेते बल्कि हर गांव में कुछ न कुछ देकर ही आते हैं। (विघ्न) इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। साथ ही मैं आज विपक्ष के साथियों का डबल धन्यवाद करता हूँ कि वे आज चुप रहे हैं, आज ज्यादा बीच में बोले नहीं हैं। इसके लिए इनका भी डबल धन्यवाद करता हूँ। मेरा यह भी निवेदन है कि इनसे कभी कोई उम्मीद न की जाए। (विश्व) मैंने तो चौधरी बलवंत सिंह सढौरा को भी कहा है कि इनकी सरकार के समय में यदि इनकी कोई सड़क बनी हो या कोई सब–डिवीजन खुला हो तो ये बताएं। कोई भी कार्य करते हुए मुख्यमंत्री जी यह भी नहीं देखते कि पक्ष का हल्का है या विपक्ष का हल्का है। मुख्यमंत्री जी इनके हल्के को सब–डिवीजन बना दिया। बलवंत सिंह जी तो ऊपर–ऊपर से नाराज होते हैं। अन्तरआत्मा से ये खुश हैं। इनको तो मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। स्पीकर सर, इनका बटन कहीं और लग रहा है और बिजली कहीं और जलती है। (हंसी)

श्री बलवंत सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि मेरे हल्के की सड़कें हमारी सरकार के समय में नहीं बनी थी और ये कह रहे हैं कि इस सरकार के कार्यकाल में इनके हल्के की सड़कें बन गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके हल्के में जाने

में दस किलोमीटर का रास्ता आप यदि पीने घंटे से कम समय में तय करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि इनके हल्के की सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। हमें ये क्यों बीच में शामिल करते हैं। अपनी जो मांग है वह मांग लें।

चौ० अर्जन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं तो मांग के ले रहा हूँ इनको तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है फिर भी ये उल्टी बातें करते हैं। इनको तो बिना मांगे ही सब कुछ दे रखा है इनसे ज्यादा अहसानमंद तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह जो बुढ़ापा पैंशन के रूप में बुढों को वृद्धों को सम्मान दिया गया है, मेरी रिक्वैस्ट है कि बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और विधवाओं के लिए बहुत कुछ दिया जाए।

श्री अध्यक्षः आपका समय समाप्त हो गया है। आप बैठ जाए।

चौ० अर्जन सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनीता यादव (साल्हावास): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। बजट से पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे भत्ते दिए और अन्य कल्याणकारी घोषणाएं की हैं उसके लिए मैं उनको हार्दिक

बधाई देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सबसे पहला टौपिक सिंचाई का रखना चाहती हूँ। मुझ से पूर्व बोलते हुए कई वक्ताओं ने यह कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वह किया। मैं इससे डिफर यह बात कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा भी नहीं, वह भी किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हम वहां बैठते थे और सरकार का एक साल का समय रह जाता था तब जाने क्या–क्या यहां हुआ करता था। हम इनको कहा करते थे कि भाई थोड़ा बहुत काम कर लो तो प्रदेश में दोबारा कुछ चुनकर आ जाओगे लेकिन ये नहीं माने और उसका परिणाम यह हुआ कि ये दो डिजिट में भी नहीं आ सके। इनके केवल दो ही काबिल और पढ़े–लिखे विधायक दोबारा चुनकर आये हैं। दूसरे भाइयों को तो मौका नहीं मिला। ये कुछ अच्छा करते कुछ तो फर्क होता।

श्री अध्यक्षः यह प्रजातंत्र है इसमें कभी इधर बैठते हैं तो कभी उधर भी बैठना पड़ता है। लोगों ने इनकी रजाई सी भर दी तभी तो उधर बैठे हैं। आप बजट पर बोलिये।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि हांसी– बुटाना नहर बनायेंगे तो यह बात इन भाइयों के बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने यह कहा कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला से गोद बलावा तक पानी का समान बंटवारा करने के लिए कहा था कि अगर एक रोटी है तो उसके चार टुकड़े करके सभी में समान बंटवारा किया जायेगा। लेकिन इन भाइयों को वह बात गंवारा नहीं हुई। अध्यक्ष

महोदय, इतनी महान हस्ती चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा आज हमारे बीच में. नहीं हैं जिनकी भाखड़ा नहर बनाने में इन्वोल्वमैंट रही। उसी भाखड़ा मेन लाईन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी–बुटाना लिंक नहर, दादुपुर नलवी और घग्गर नदी की योजना बनाई है जोकि इनको गंवारा नहीं हुई। इसके बारे में मैं एक शेयर कहना चाहती हूँ।

जब तक चमकेंगे आकाश में चाँद और तारे,

जब तक चमकेंगे आकाश में चाँद और तारे,

अमर रहेंगे चौधरी रणवीर सिंह जी

जनता और किसानों के चारे।

लोग याद करते हैं आज दुनिया के सारे,

आज हरियाणा प्रदेश है मायूस निना तुम्हारे।

भाखड़ा बांध जहां पर उनकी अस्थियां विसर्जित की गई हैं उसके बारे में यह बात मैंने कही है कि वे इस तरह का बाँध यहां पर बनाकर चले गये जो एक मिसाल है। जब–जब प्रदेश में या देश में किसी तरह का भार आता है तो कोई न कोई शक्ति उसमें जन्म जरूर लेती है। पिछली सरकार ने पांच साल का जो भार प्रदेश की जनता को दिया उसका कहीं न कहीं तो अन्त होना ही था। उस रूप में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एक संस्कारी मुख्यमंत्री यहां पर आए और उन्होंने अपने पिताजी की बात को

आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की जनता की सुध ली। इन्होंने इतनी सारी सहूलियतें प्रदेश को जनता को दी कि अब 80 से 85 प्रतिशत किसान अब गांव में रहते हैं। सभी लागों ने शहर की बात की लेकिन क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ इसलिए गांव की ही बात करना चाहती हूँ। किसानों के हितों को देखते हुए आज हमारी सरकार 'किसान–मजदूर वर्ष' के रूप में इस वर्ष को मना रही है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, अनिता जी, आप अपनी बातें लिखकर भिजवा देना। अब सदन के नेता बोलेंगे।

नियम 64 के अधीन वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा में कई सदस्यों द्वारा अवैध कालोनीज को नियमित करने का मुद्दा उठाया गया है। इस बारे में स्थानीय निकाय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण इस समय राज्य में नगर पालिका की सीमाओं में इन अवैध कालोनीज को नियमित नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, अवैध कालोनीज को रैगुलर करने की एक गम्भीर समस्या है। हरियाणा सरकार इस समस्या के समाधान के लिए जागरुक है। इस बारे में हमने गम्भीरता से विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि आगामी तीन महीनों में उपरोक्त सभी अवैध कालोनीज का विशेष तौर पर सर्वे किया जायेगा उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो इस बारे में

कानून में उचित संशोधन लाकर सभी अवैध कालोनीज को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

वर्ष 2009–2010 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Maj. Nirpender Singh Sangwan (Dadri) : Sir, I congratulate the worthy Chief Minister and the Government, especially the Finance Minister for bringing out such a growth oriented budget inspite of world wide and nation wide recession. Growth for the year 2008-09 placed on record is 17.9% GSDP the growth rate of 8%. This is an excellent performance and the per capita income being second only to Goa. Excise and taxation department needs special congratulations and has mentioned for the highest tax collection and professionalism. In the special economic impetus package, six districts hospitals that are being upgraded. I would request the Finance Minister and the Chief Minister to enhance Ks. 100 crore which are given in the budget because the equipments also should be state of art. The sewerage and water supply needs major upgradation and 100% coverage for good reliable drinking water and sewerage facilities has been given 500 crore. But I would request that these projects should be put on the drawing board and they should start working on them right now and not wait for Rs. 500 crore.

The impetus of village ponds cannot be over emphasized. Rs. 100 crore that have been given are I think insufficient. More money should be given for the village ponds upgradation. For water courses renovation, Rs. 100 crore which the Finance Minister has very kindly given, it needs

more money because water is a precious. Demonstration and teaching for drip irrigation and subsidy should be taken care of. I would be failing in my duty, if I do not mention the Ex-servicemen and war widows and serving soldiers of the State. Our State has the highest number of Ex-servicemen after Punjab and also serving soldiers. War widows are also at the maximum. I would request that though the war widows get there pension but there is no reason no way that we rehabilitate them. There should be special seats in the JBT that all these ladies who want admission should not be denied admission because of a special quota. For war widows rehabilitation, we should work out a special package and for their wards. Because the Army men or rather the people in the defence gave the best years of their life to the nation. They cannot look after their families because they do not have enough places to put up, so, they should be given this reservation and a special college for wards of serving and retired soldiers i.e. engineering college or a technical college should be setup so that their wards can take up.

श्री अध्यक्षः मेजर साहब, अब आप बैठें। एफ०एम० साहब, ने भी रिप्लाई देना

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिन्ट का समय और दे दें। मैं वाटर कोर्सिज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः आपने कह तो दिया कि वाटर कोर्सिज के लिए और पैसा दो। जो आप कहना चाहते हैं वह लिखकर भिजवा देना।

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ कि मेरी पार्टी को और विशेषकर मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया गया है जोकि एक ऐतिहासिक क्षण है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। बजट कोई आम लेखा जोखा नहीं होता। बजट में लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारी आमदनी अच्छी हो तथा खर्चों को इस तरीके से सुचारू रूप से किया जाए कि आज की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ताकि भविष्य को सुंदर और स्वर्णिम बनाया जा सके। बीरेन्द्र सिंह जी मेरे राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी है। वैसे आदमी बहुत बढ़िया हैं और दीनबन्धु सर छोटूराम के नाती हैं। लेकिन जो बजट पेश किया गया है उसमें हिचकिचाहट दिखती है। मुझे लगता है कि हिचकिचाहट में यह बजट बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हिचकिचाहट में बनाया गया बजट हरियाणा प्रदेश को क्या दे सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी चार बार पार्लियामैंट में रहे हैं और पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में एक प्रैक्टिस है जिसकी उनको अनुपालना करनी चाहिए थी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बजट पेश होने के एक घंटे पहले बहुत सी घोषणाएं कर दी

जायें। बजट पेश होने वाला था और उन्होंने सदन में बहुत सी घोषणाएं कर दी।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, आप रैपीटीशन कर रहे हैं। यह बात आपकी पार्टी के दूसरे सदस्य भी बोल चुक हैं। आप कोई नई बात कहना चाहते हैं तो कहें।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि Beware of the men who does not written your below. He neither forgives you nor allows you to forgive yourself. माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, यह किसकी कोटेशन है?

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, यह जार्ज बरनार्ड शाह की कोटेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि दीनबंधु सर छोटूराम के नाती इतने कमजोर और विवश नहीं हैं कि वे अपनी बात को कहीं न कहीं मौके पर संभाल न पाये।

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, आप क्यों पानी में आग लगाना चाहते हैं?

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, हमारा तो काम यही है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बजट से बहुत निराशा

हुई है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल एक दो बातें ही कहूँगा। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे वित्त मंत्री जी ने माना है कि इस मंदी के दौर में हमें रोजगार सृजन करने की जरूरत है। सरकार ने 25880 करोड़ रुपये राजस्व खर्चा दिखाया है जिसमें हमारा फिसकल डैफिसिट भी है। जबकि हमारे टोटल सोर्सिज से जो आमदनी है वह तकरीबन इससे कम बैठती है, ज्यादा नहीं है। अगर माननीय वित्त मंत्री जी की माने तो पिछली बार वैट आने से एक बार 5500 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट हुआ था लेकिन जो बजट सरप्लस में है वह घाटे में चला जाये यह अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की निशानी नहीं है।

श्री खैराती लाल शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि जब वित्त मंत्री जी ने पहली बार 248 करोड़ रुपये का घाटा दूसरे बजट में दिखाया था उस समय इन्दौरा जी ने जो शब्द कहे थे वे मैं सदन को बताना चाहूँगा। इन्होंने उस समय कहा था कि हम इस प्रदेश को तबाह कर देंगे। उसके बाद जब अगले साल 1280 करोड़ रुपये का प्लस बजट आया तब भी इन्होंने यह कहा था कि जो प्लस बजट होता है वह ठीक नहीं है, यह सरकार के निकम्मेपन की निशानी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, पहले ये डिसाईड कर लें कि ये कहना क्या चाहते हैं?

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, जब वित्त मंत्री जी बजट खस में लेकर आये थे, सरप्लस बजट हुआ था उसके दो कारण थे। एक तो हमें वेट से काफी आमदनी हुई थी और दूसरा

कारण यह था कि उस समय प्रोपर्टी में बहुत ज्यादा इन्हांसमैंट हुई थी। लेकिन आज हमारे रिसोर्सिज जो हैं चाहे आटोमोबाईल से हैं, मैनीफैक्चरिंग इण्डस्ट्रीज से हैं, वेट से हैं, प्रोपर्टी से हैं या दूसरे हैं उनसे ज्यादा रिसोर्सिज मिलने की उम्मीद नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर क्रीटीसाईज नही करना चाहता। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर हमारा बजट उत्पादकता बढ़ाने के लिए डैफीसिट में जाता है तो कोई बात नहीं है। एक सरप्लस स्टेट यदि उत्पादकता बढ़ाना चाहती है तो हमें करना चाहिये। क्योंकि यह लोगों के भले के लिए है। इसके अतिरिक्त यदि रोजगार के साधन सृजन करने के लिए .और असहाय लोगों की मदद करने के लिए बजट घाटे में जाता है तो भी हमें लोगों की भलाई के लिये ये कदम उठाने चाहिएं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो हमारी पड़ोसी स्टेट है वहां जैसी हमारी हालत नहीं है। हमारी हालत उनसे बहुत बेहतर है। आज हमारी आर्थिक बहुत मजबूत है। अगर उस आर्थिक स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन मुख्यमंत्री जी इस समय सदन में बैठे नहीं हैं। लेकिन बहुत अच्छा होता यदि वे इस 700 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में पहले ही करते।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, यह भी रैपीटीशन है। इस बारे में आपके सारे मैंबर बोले हैं कि बजट में पैसे का प्रावधान है कि नहीं है। इंदौरा जी, पैसे का प्रावधान है या नहीं है इसके बारे

में न आप जानते हैं और न ही मैं जानता हूँ। इसका जवाब वित्त मंत्री जी देंगे। प्लीज आप रैपीटीशन न करें।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ ऑर्डर है। स्पीकर सर, डॉ० इन्दौरा पार्लियामैटेरियन रहे हैं। माननीय सदस्य की कुछ बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। स्पीकर सर, जो स्टेट का बजट घाटे का है वह हमेशा ही प्रो–पीपल होता है और प्रो–डिवैल्पमैंट होता है। स्टेट कभी रुपये बचाती नहीं है स्टेट रुपये खर्च करती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि वे कैसे वित्तीय प्रबंधन करेंगे जिससे यह घाटा पूरा हो जायेगा। माननीय सदस्य बिना वजह बजट को क्रीटीसाईज कर रहे हैं इसका यह मतलब है कि इनको बजट की पूरी समझ नहीं है।

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी की सुविधा, सड़कें और बिजली ये सभी मदें बुनियादी सुविधाओं में आती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक घोषणा का जिक्र करना चाहूँगा। स्पीकर सर, इसी सदन में एक साल पहले स्वास्थ्य से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश में जो डॉक्टर्ज हैं उनको पंजाब से ज्यादा सैलरी देंगे और इसके साथ ही उनको 25 परसेंट एन०पी०ए० दिया जायेगा। स्पीकर सर, ये सदन की घोषणायें हैं जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है इसलिए मुझे डर है कि कहीं आज जो घोषणाएं हुई हैं इन

घोषणाओं का भी जो स्वास्थ्य के लिए घोषणाओं की इम्पलीमैंटेशन ज्यादा जरूरी है वह हर हाल में हानी ही चाहिए। स्पीकर सर, अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्वर दिनोंदिन गिरता जा रहा है उसके लिए सुधारात्मक कदम सरकार द्वारा उठाये जाने चाहिएं। स्पीकर सर, पूरे भारत देश की तरह हमारा हरियाणा प्रदेश भी गांवों में बसता है। हमारे प्रदेश में 6800 से ज्यादा गांव हें। हमारे गांव के स्कूलों में न टीचर हैं और न ही अन्य प्रकार की आवश्यक सुविधायें हैं। स्पीकर सर, अगर बच्चा शुरू से ही साईंस की क्लास में नहीं पड़ेगा तो सरकार द्वारा आई०एम०टी० और आई०आई०टी० खोलने का क्या औचित्य रह जायेगा। स्पीकर सर, सरकार गरीब आदमी की आर्थिक मदद करने के बजाय अगर उनके शिक्षा के स्तर में सुधार कर दे तो यह उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्षः ऑनरेबल मैम्बर्ज जैसा कि मैंने आपको आश्वासन दिया था कि कुछ नाम मेरे पास हैं वे बजट पर पांच–पांच मिनट बोलेंगे। लेकिन तीन मैम्बर तकरीबन डेढ़ घंटा बोल चुके हैं और फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने भी अपना जवाब देना है। कुछ नाम मेरे पास रह गये हैं जो गवर्नर एड्रैस पर बोल लिये जिनकी दोबारा बोलने के लिए रिक्वैस्ट आई हुई है। मैं

उनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि वे या तो डिमाण्डज पर बोल लें या 20—02—2009 को जब एप्रोप्रियेशन बिल आयेंगे तो उन पर बोल लें।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): स्पीकर सर, यहां पर कुछ मैम्बर्ज ने यह चर्चा की है कि नहरी पानी की चोरी के कारण अधिकतर टेल्ज पर पानी नहीं पहुंचता। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इस ओर सजगता से ध्यान दिया है कि पानी की चोरी को किस प्रकार से रोका जा सके। इसके लिए हमने बाकायदा अपने विभाग के एस०ईज०, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्ज और एस०डी०ओज० को आदेश दे दिये हैं कि वे क्रमशः 50, 75 और 100 किलोमीटर तक के एरिया की पैट्रोलिग करेंगे। दो एस०पीज० जिनका हैडक्वार्टर होगा भिवानी और अम्बाला में और डी०एस०पीज० होंगे भिवानी, अम्बाला, रोहतक और रिवाड़ी में। इसके अलावा हम 9 पुलिस स्टेशन एस्टेबलिश कर रहे हैं जो कि रोहतक, जीन्द, भिवानी, फरीदाबाद, रिवाड़ी, हिसार, पानीपत और पंचकूला में होंगे। इनका मेन उद्देश्य यही होगा कि जो पॉवर और इरीगेशन थैफ्ट हो रही हैं उनकी रोकथाम की जाये। ये बाकायदा स्पैशल सैल्ज हम इसी परपज के लिए बना रहे हें। इस प्रकार से सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से सजग है। अध्यक्ष महोदय, इरीगेशन और पॉवर थैफ्ट की रोकथाम के लिए पहली बार हमारी सरकार ने पहल की है इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके लिए जो

स्पैशल सैल्फ हमारी सरकार स्थापित करने जा रही है उनमें 512 अधिकारी होंगे, दो एस०पी० होंगे, 4 डी०एस०पी० होंगे और विभिन्न 8 पुलिस स्टेशंज होंगें जिनमें 128 अधिकारी होंगे। अध्यक्ष महोदय, सभी 21 डिस्ट्रिक्ट में एक–एक रेडिंग टीम का गठन किया जायेगा जिनमें टोटल अमला 379 होगा। स्पीकर सर, यह मैं विशेषकर उन माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने पानी की चोरी की बात की थी। स्पीकर सर, इसके अलावा माननीय सदस्य डॉ० सीता राम ने यह कहा कि उन्हें भाखड़ा का पानी बहुत कम मिलता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004–05 में फरवरी के महीने में इन्हें जो ऐवरेज पानी मिला वह 5215 क्यूसिक पानी मिला था, 2005–06 में 9980 क्यूसिक मिला और 2008–09 में, फरवरी, 2009 तक हमें 10357 क्यूसिक पानी मिला है। अध्यक्ष महोदय, कहां तो 5215 क्यूसिक पानी इनके टाईम में मिलता था और कहाँ अब 10357 क्यूसिक पानी मिलता है। यह हरियाणा में अब तक का रिकॉर्ड रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों ने दूसरी बात कही है कि हमने बी०एम०एल० हांसी–बुटाना लिंक नहर के लिए भारत सरकार से परमिशन क्यों नही ली। अध्यक्ष महोदय, यह एक आरडयूएस प्रोसीजर होता है, इसमें कई महकमे शामिल होते हैं जिनके पास जाकर हमें परमिशन लेनी होती है। नाबार्ड के लोन के बारे में 3–3 साल लग जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह देखते हुए कि हमें पानी का समान बंटवारा करना चाहिए, बी०एम०एल० हांसी–बुटाना लिंक कैनाल और दादुपुर नलवी दो

मेजर प्रोजैक्ट्स बनाये। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमें उसके बाद क्लियरेंस मिल गई। वह क्लियरेंस हमें सितम्बर, 2007 में मिली। 2006 में हमने काम शुरू कर दिया था। हमें हाईड्रोलोजी और फ्लड डिपार्टमैंट से क्लियरेंस मिल गई। इन्होंने एक पैटिशन हाई कोर्ट में डाली कि फ्लड आ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वहाँ से बाकायदा सी०डब्ल्यू०सी० ने रिपोर्ट दी और हमसे जवाब मांगे। हमने सारे जवाब दिये कि हम इनकी फ्लड की सिच्यूएशन को दूर करेंगे और हमने सैन्ट्रल वाटर कमिशन को इस बारे में कनविन्स किया। उसके अलावा इरीगेशन और प्लानिंग डिपार्टमैंट ने हमारा प्रोजैक्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद सैन्ट्रल ग्राऊंड वाटर कमिशन ने हमारा प्रोजैक्ट क्लियर कर दिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी हमारा यह प्रोजैक्ट क्लियर कर दिया। इनवायरनमैंट मिनिस्ट्री में भी कुछ लोगों ने इस काम को रोकने की कोशिश की लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को दुष्ट लोग कहूँगा जिन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। हरियाणा सरकार पानी का संमान बंटवारा करना चाहती थी लेकिन ये दुष्ट लोग उसमें अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मंशा' नहीं है कि पानी का समान बंटवारा हो। उसके अलावा हमें फोरैस्ट क्लियरेंस भी मिल चुकी है और उसके अलावा सैन्ट्रल वाटर कमिशन ने हमारी बात सुनकर यह कहा कि यह जो प्रोजैक्ट है it has been found to be cleared from all inter-State angles. उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान और पंजाब के जितने भी कन्सर्न हैं वे सब हरियाणा राज्य ने दूर कर

दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे ये साथी हैं ये खुद तो पीछे रहते हैं और पंजाब को आगे करके इन्होंने एक पैटीशन डाल दी। जब सी०डब्ल्यू०सी० ने कहा कि आप बी०बी०एम०बी० से पंक्चर करने के लिए परमिशन लें तो इन दी मीन व्हाईल कुछ साथी है हमारे वे पीछे रह कर रोड़ा अटकाते थे। बल्कि इनके एक पूर्व इरीगेशन मिनिस्टर स्वयं हाई कोर्ट में जा कर बैठा करते थे और उस वक्त हाई कोर्ट की उन लोगों के खिलाफ स्ट्रीक्चर हैं। मैं आपको ये चार लाईन पढ़ कर सुनाऊंगा। ये उन लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट के स्ट्रीक्चर्ज हैं इसमें लिखा है– "Before parting, we, however, feel that it is important to unmask the petitioners, who have done the cloak of public interest to raise such issues, which have only laid bare the fangs which do not belong to the innocent face of a farmer but to someone else." उन्होंने कहा कि ये फार्मर के काम नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझ कर यह केस डलवाया है। इसमें आगे लिखा है – "the petitions, especially C.W.P. No. 19676 of 2005 are a result of an ingenious mind with a purpose other than a public purpose." यह इन्होंने जानबूझ कर किया है। इनका कोई मकसद नहीं है। It was an issue without a public purpose. It is further mentioned —"when viewed from the prism of the tests laid down by the Apex Court for public interest litigation, we find the essential colors missing from the spectrum." अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मकसद यह है कि जो हमारी सरकार की जो मंशा थी कि पानी का समान बंटवारा होना चाहिए वह पूरी

नहीं होती। अगर हम नाबार्ड के चक्कर में फंस जाते तो यह काम नहीं हो सकता था। अब हमें सब क्लियरेंस मिल चुकी हैं। आज हमारी तारीख थी लेकिन आज भी पंजाब सरकार ने एडजोर्नमैंट मांग लिया। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सारी रिपोर्ट हैं वै हरियाणा के हक में हैं और पंजाब सरकार केवल इसे हिले करना चाहती है। फैसला हमारे हक में ही होगा। हमने चाहे एस०वाई०एल० का मामला हो चाहे बी०एम०एल० हांसी–बुटाना लिंक नहर की बात हो, हमने बैस्ट लायर्ज इस काम पर लगा रखे हैं। इस मामले में सरकार का व्यू बिल्कुल क्लियर है। नहर में पानी भी चलेगा और इनकी मंशा भी पूरी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, इनके एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि यह नहर बनेगी तो गृहयुद्ध हो जायेगा। इससे क्लीयर होता है कि इन लोगों की मंशा क्या है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members now Ch. Birender Singh, Finance Minister, will give reply on the Budget Estimates for the year 2009-2010.

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मैम्बर्ज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले तीन दिन में जो बजट ऐस्टिमेटस 2009–10 के प्रस्तुत किये गये हैं उनकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की। लगभग तीन दर्जन सदस्यों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया और बहुत से बहुमूल्य सुझाव सदन के पटल पर माननीय सदस्यों ने दिये। स्पीकर सर, बजट में हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि दुनियां भर में आर्थिक मंदी का दौर हे और आर्थिक मंदी के दौर में हरियाणा देश का पहला राज्य है

जिसने अपना पूरा बजट पेश किया। उसके साथ ही साथ जो आर्थिक मंदी से निपटने और आर्थिक मंदी पर काबू पाने के लिए राज्य जो कोशिश कर सकता है अपने स्तर पर हमने वह सब प्रयास किये हैं। स्पीकर सर, नुक्ताचीनी कहिये या क्रिटिसिज्म माननीय सदस्यों ने खासतौर से विरोधी पक्ष के सदस्यों ने तीन तरह के सुझाव रखे हैं। उनका यह कहना है कि जो बजट पिछले तीन चार साल से सरप्लस में हैं उसके बाद एकदम यह घाटे का बजट क्यों बना। दूसरा उन्होंने कहा कि घाटे को पूरा करने के लिए हमने बाजार से पैसा उधार उठाया है और मार्किट बॉरोइंग की। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि जब आपका बजट घाटे का है और आप मार्किट से पैसा उठा रहे हैं तो फिर आपकी एनुअल प्लान योजना उस पर आप दस हजार करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं। ये तीन मुद्दे खासतौर से माननीय डॉ० सीता राम जी, जिन्होंने बजट की डिबेट को इनऑगुरेट किया उन्होंने 'और दूसरे सदस्यों ने रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों चीजों का जब तक हमारे पास जवाब नहीं होगा तो हम यह समझते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। हमने जो बजट रखा है वह इतना बड़ा घाटा बर्दाश्त करने का बजट नहीं होना चाहिए था लेकिन हमने जो भी प्रावधान बजट में किये हैं वे बिलकूल सोच समझ कर किये हैं। मैं कुछ उदाहरण देकर आपको यह बात कहना चाहता हूँ कि दुनियां में जो सबसे बड़ी मंदी है उसका सबसे बड़ा असर आज अगर किसी देश पर पड़ा है तो वह अमेरीका पर पड़ा है। अमेरिका ने भी 800 बिलियन से ज्यादा का स्टिमुलस पैकेज अपने देश को

उसकी आर्थिक मंदी से उभारने के लिए देकर आर्थिक ग्रोथ को लाईन पर लाने के लिए कोशिश की है। स्पीकर सर, मैं यह भी समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि आर्थिक मंदी से निपटने के कौन–कौन से तरीके हो सकते हैं। इसके बारे में जो सबसे बड़ा एक आर्थिक मंदी का दौर आया था वह 1930 में आया था। उस समय यूरोप के देश आर्थिक मंदी से हिट हुए थे और दूसरे वे देश जो अंडर डिवैल्पड कंट्रीज थे पराधीन थे जिनमें आजादी नहीं थी वे तो हिट होने ही होने थे। उनकी हालत तो उस समय और भी चिन्ताजनक थी। लेकिन जो देश इससे प्रभावित हुए हैं उनमें खासतौर पर इंग्लैंड और अमेरिका हैं। स्पीकर सर, उस समय एक बहुत बड़े एक्नोमिस्ट प्रो० केन्ज थे, उनका कहना था कि आर्थिक मंदी के दो कारण होते हैं। एक तो कारखानों से ज्यादा सामान बनना बंद हो जाए या कम हो जाए और दूसरे खेती में एकदम गिरावट आ जाए या अकाल पड़ जाए। स्पीकर सर, इसके अलावा जो गरीब लोगों की रोजी रोटी है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज हैं, निर्माण के कार्य हैं, सड़क बनानी है, कारखाने लगाने हैं और बड़ी बिल्डिंग्ज बनानी हैं, इन कार्यों में स्थिरता आ जाए, ये कार्य अगर घट जाएं तो भी मंदी की मार गरीब आदमी पर पड़ती है। स्पीकर सर, केन्ज यह कहता है कि सप्लाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सप्लाई की तो आज भी यह स्थिति हे कि हमारे कारखाने बंद नहीं है। पहले अगर विदेशों से किसी कारखाने को 5000 गारमैंट का आर्डर एक दिन में पूरे करने को मिलता था तो आज वही बीयर यह कहता है

कि मुझे 5000 की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे देश में रिसैशन है इसलिए मुझे 2000 गारमैटस की जरूरत है। इस वजह से कारखाने में जितने भी काम करने वाले लोग हैं या तो उनकी संख्या में कटौती होगी या मालिक उनकी छुट्टी करेंगे या उनका वेतन कम कर देंगे। स्पीकर सर, इसका प्रभाव आदमी की परचेजिग कपैस्टी पर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, केन्ज कहता है कि ऐसी आर्थिक मंदी में ज्यादा पैसा पम्प इन करेंगे, ज्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्यादा इकास्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे और इसमें ज्यादा पैसा हम लगाएंगे तो ही हम इस मंदी से उभर सकते हैं, लड़ सकते हैं। स्पीकर सर, जो चर्चा उनके द्वारा की गई है मैं वह कोट कर रहा हूँ:–

Kanes advocated the use of deficit financing as an instrument of economic policy to uplift the economy out of the depth of economics, depression and also to raise the level of output and employment. As such private investment become sleek on account of around pessimism in the economy. Professor Kanes looked upon public investment during the depression. Public spending would result in an increase in output from the employment and income. Deficit financing or rather deficit spending as used by Professor Kanes is the only way to come out of the depression and to raise the level of output and employment."

This is the fundamental of the economics. If you are to fight out then the way out is you will have to pump in more resources. You may create resources even if there is a deficit.

सर, मैं यहां पर एडमिट करता हूँ कि आज जो हालात हैं इसकी वजह से नैक्स्ट ईयर का जो बजट होगा, जिसके बारे में प्रणब मुखर्जी ने भी अपने बजट भाषण में भी कहा है, उसमें उन्होंने यही इशारा किया है कि जो अगला साल है वह दुनिया के लिए भी और अपने देश के लिए भी बड़ा चौलेंजिंग है। उसमें भी इक्नौमिक क्राइसिज रहेंगे, परसिस्ट करेंगे और इस तरह की परिस्थिति बनती है तो आज हमारा अगर 3400 करोड़ रुपए का डैफिसिट है तो वह अगले साल के बजट में बढ़कर 9000 करोड़ होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इनके क्रिटिसिज्म को ठीक मानू तो इनको यह भी मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक जो यह कहता है कि "I am an International Monetary Fund," उसके पास भी 6 से 8 महीने के फंडज बाकी हैं जिसके पास पैसों की अम्बार होती थी, आज उस बारे में जो अखबार लिखते हैं मैं उसको यहां पर कोट करता हूँ:—

"Now, turmoil hits IMF.

Today, the IMF resources are enough to face the situation but because we are facing a global cirsis, the needs may be much bigger than the previously. We have to intervene in Asia, Africa and Central Europe, Latin America, may be elsewhere. I cannot promise that in six to eight months from now we will have enough resources."

वे यह कहते हैं कि हम प्रोमिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भी रिर्सोसिज डिविन्डल हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो

हमारी इकोनोमी है उसको हमें जांचना पड़ेगा। हरियाणा में जो माननीय सदस्य हैं, जो यह महान सदन है इसकी जिम्मेवारी हरियाणा के हाई करोड़ लोगों के प्रति है। यह जिम्मेवारी निभाने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए अगर हम बजट को गलत रास्ते पर लेकर जाते हें तो हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। स्पीकर साहब, अगर डिवैल्पमैंटल ऐक्टिविटीज को हम कम कर देते या बंद कर देते तो हमारा बजट भी सरप्लस होता और हम घर पर आराम से बैठते। अखबारों में भी लिखा जाता कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसका बजट सरप्लस है। लेकिन जो प्रोग्रैस थी, जो उन्नति थी, जो विकास था उसको अगर हम बलिदान पर लगा देते तब तो हम यह मान सकते हैं कि हमने गलत किया। लेकिन यह बात सोच समझकर कि जो राज्य 2008–09 का 6400 करोड़ रुपये का ऐनुअल खान 7130 करोड़ रुपये पर लेकर जाता है वह राज्य ऐसी परिस्थितियों में जहाँ आर्थिक समस्याएं हमारे को घेरे हुए हैं, हमने यह फैसला लिया कि हम विकास की रफ्तार को कम नहीं होने देंगे बल्कि उसको और तेजी देंगे इसलिए हमने अपनी ऐनुअल खान दस हजार करोड़ रुपये की रखी। स्पीकर साहब, दस हजार करोड़ रुपये की जो हमारी ऐनुअल प्लान है अगर उसके आकड़े आप देखें तो जब हमारी सरकार ने टेक ओवर किया था। उस समय दो हजार करोड़ की ऐनुअल प्लान थी, हम इसको दो हजार करोड़ रुपये से दस हजार करोड़ रुपये पर लेकर पहुंचे हैं। यह ठीक है कि पिछले तीन साल अच्छे निकले इसलिए आप भी कह सकते हैं कि आपने अपने प्लेअल प्लान को बढ़ा

लिया होगा लेकिन आज तो रिसैशन है इसलिए इस रिसैशन में हमने दस हजार करोड़ रुपये का ऐनुअल प्लान करने का फैसला लिया। इस दस हजार करोड़ रुपये में केन्द्र सरकार से हमें और भी ऐडीशनल सहायता मिलनी है इसलिए अगर उसको भी इसमें ऐड कर दें तो हमारी प्लेअल प्लान 11100 कुछ करोड़ रुपये से ऊपर की होगी। स्पीकर सर, इनके वक्त के मैं क्राईसिज की बात नहीं करता लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पिछली सरकार का और हमारी इस सरकार का जो चार साल का टेन्योर है, उसमें कितना भारी अंतर है। 2000 से लेकर 2006 तक ये बहुत ढीगे मारते थे कि हमने देश में सबसे पहले वैट इंट्रोडयूस किया और हमें उससे पैसा भी बहुत मिला। स्पीकर सर, इनके पांच साल में वैट की और सैल्ज टैक्स की कलैक्शन 17454 करोड़ रुपये की थी जबकि अब हमारी 29964 करोड़ रुपये की कलैक्शन है। चार साल के अंदर ऐक्साइज की कलैक्शन इनकी साढ़े चार करोड़ रुपये की थी जबकि हमारी ऐक्साइज की कलैक्शन 5263 करोड़ रुपये है। इसी तरह से लाईसेंस फीस जिसके बारे में इन्दौरा साहब ने भी बात की। सर, एक समय था जब आपको यह मिल गयी लेकिन जो डिवैल्पर्ज थे, बिल्डर्ज थे, उनको हमने मौका दिया और उनको कहा कि कालोनिज बनाने के लिए हमारे से अच्छी जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती। इस वजह से इनके पांच साल के समय में धरती के सौदे तो होते रहे गुड़गांव में या कहीं और लेकिन

टोटल लाईसेंस फीस 5 साल में 610 करोड़ रुपये की ही मिली थी।

13.00 बजे

श्री बलवंत सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कलैक्टर रेट भी तो 5 गुना बढ़ा दिये, उससे भी तो इकीज हुई है। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर हमने 5 गुना कलैक्टर रेट बढ़ाए हैं तो इनके समय के 610 करोड़ रुपये के मुकाबले में 12 गुना ज्यादा पैसा अर्थात् 7182 करोड़ रुपये रेवेन्यू आया

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ ऑर्डर है। अभी फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने विकास की बात कही है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो हर सैक्टर में चाहे वह सिंचाई का क्षेत्र है, चाहे रूरल डिवैल्पमैंट का है there is a decrease in the allocation. फिर विकास कहां से हो गया? Property enhancement was started after our Government. प्रोपर्टी में बूम इनकी सरकार आते ही शुरू हुई थी। प्रोपर्टी इन्हांसमैंट शुरू हो गई और उससे जो पैसा आया उसको यूज करना चाहिए था। उसका मिसयूज हुआ and that is wrong.

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर इन्दौरा इन्हांसमैंट की बात कर रहे हैं, वह भी मैं बता रहा हूँ। इनके समय में पांच साल में 2871 करोड़ रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प डयूटी

के माध्यम से आया। हमारे चार साल के समय में जबकि हमने स्टाम्प डयूटी रिडयूस भी की उसके वावजूद भी (विघ्न)

श्री बलवन्त सिंहः कलैक्टर रेट 6 परसैंट से बढ़कर 30 परसैंट हो गया और जमीन का रेट जो 1 लाख रुपये प्रति एक्क था वह बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया, उससे भी तो फर्क पड़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री एस० एस० सुरजेवालाः किसान की जमीनों की कीमत बड़े, क्या आप यह नहीं चाहते?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्य ही बता रहा हूँ। इनके पांच साल के समय में स्टाम्प डयूटी से 2871 करोड़ रुपये और हमारे चार साल के समय में 7000 करोड़ रुपये की क्लैक्शन आयी और इस पर भी ये प्वायंट ऑफ आर्डर ले कर आ रहे हैं कि हमारी ऐलोकेशन कम है। सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट जिसमें वूमैन इम्पावरमैंट डिपार्टमैंट और चाइल्ड वैल्फेयर डिपार्टमैंट भी शामिल है उसमें इनके पांच साल के समय में 2540 करोड़ रुपये की ऐलोकेशन थी जबकि हमारे समय में 5571 करोड़ रुपये की ऐलोकेशन है जो कि डबल से भी ज्यादा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, रूरल डिवैल्पमैंट के बारे में कहना चाहूँगा कि जो किसानों का रहनुमा होने का दावा करने वाली इनकी सरकार साढ़े पांच साल तक रही उस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इनके पांच साल के समय में मात्र 760 करोड़ रुपये की ऐलोकेशन हुई थी

और हमने चार साल में 3182 करोड़ रुपये की ऐलोकेशन रखी है जो कि इकास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। ऐजूकेशन जिसमें मैं आज भी मानता हूं कि बहुत कुछ काम करना बाकी है। हम ये मानकर चलते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से हम अपने बच्चों को इतना लायक बनाना चाहते हैं और वड़े–बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के स्कूलों में पढ़ने वाले वच्चों के बराबर में खड़ा करना चाहते हैं तो हमें क्वालिटी आफ ऐजूकेशन में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। मैं बताना चाहूँगा कि इनके समय में ऐजूकेशन के लिए 5 साल में 7715 करोड़ रुपये की एलोकेशन हुई थी और हमने चार साल की अवधि में 16697 करोड़ रुपये की ऐलोकेशन की है। अभी पीछे हमारे विपक्ष के साथी हैल्थ के बारे में बहस कर रहे थे। इन्होंने हैल्थ के लिए 1794 करोड़ रुपये की राशि 6 साल में रखी थी और हमने 3398 करोड़ रुपये की राशि रखी है। ऐग्रीकल्चर सैक्टर में इनके समय में 1720 करोड़ रुपये लगे और हमारे समय में 3714 करोड़ रुपये लगे। हरियाणा में एक ही ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको इन्होंने पूरे पांच साल में 370 करोड़ रुपये दिये और हालत ये थी कि when I took over as Finance Minister, the then Vice-Chancellor met me. He said, we are to pay 80 crores rupees to the employees of the University. They had taken away the Provident Fund amount from the accounts of the employees which is a criminal offence. But still I assured the Vice-Chancellor of that University that whatever help you want, we will give and we

want to clear the amount. आज उस यूनिवर्सिटी को हमने 370 करोड़ रुपये की बजाए 655 करोड़ रुपये दिए हैं।

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, माननीय बीरेन्द्र सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पावर सैक्टर है उसमें वर्ष 2007–2008 में 14.3% की इन्क्रीज हुई है....

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, जब पावर सैक्टर की बात हो तब बोल लेना अब आप बैठ जाइये।

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, सरकार का जो इरीगेशन सैक्टर में इंक्रीज था that was 6.25%. Now, it is 5%, in power sector it was 14.34% and now it is 11.9% और आप रूरल डिवलैपमैंट में भी देख लें।

श्री खैराती लाल शर्माः स्पीकर सर, यह हर बजट भाषण में सदन को मिसगाईड करते है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, they stand democratically electrocuted. सर, फाईनैंस मिनिस्टर की बात सुनकर ये इतने स्तब्ध हैं कि इनको होश ही नहीं रहा। They have been democratically completely electrocuted.

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, वो तो उनका बजट मैनेजमैंट है। परसैंटेज में कब इक्रीज आ जाये कब डिक्रीज हो जाये यह कह नहीं सकते। Percentage can be decreased or increased

according to the necessity as and when it arises. वह तो अपने हिसाब से उसमें कटौती होती रहती है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः इसके साथ–साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हर सरकार में होनी चाहिए वह यह है कि हम कैपिटल एक्सपैंडीचर जिससे कि हम एसैट्स क्रिएट करते हैं जैसे बिल्डिंग, हाउसिज, सड़कें आदि इस कैपिटल ऐक्सपैंडीचर में जो पिछली सरकार के समय वर्ष 2004–2006 में जब ये छोड्कर गये तब इसमें 1140 करोड़ रुपये प्रावधान था और हम इस साल उसमें 5455 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। मैं एक और बात कहूँगा। ऐसी स्थिति में जब जो आर्थिक मैल्ट डाऊन या स्लो डाऊन हैं उसमें हम एऐफेक्टिड हैं। उसके लिए हम पहले ही तैयार थे। छठे वेतन आयोग की रिकमैंडेंशन को केन्द्र सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को देने के लिए हमने पहले ही प्रावधान किया था। इम्पॉवरमैंट कमेटी जो वित्त मंत्रालय की है उसकी हर महीने मीटिंग होती हैं। इस बात के लिए मैं सरकार और सदन की सराहना करूंगा कि सारे देश के अन्दर सिर्फ दो ही राज्य थे तमिलनाडू और हरियाणा जिन्होंने अपने कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एक साल पहले सोच लिया था कि इसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाए। इन सारे हालातों में यह चीज जरूरी है कि जो हमारी आर्थिक ग्रोथ है वह नेशनल ग्रोथ से लगभग–लगभग आगे रही है। पिछले साल हमारी

ग्रोथ 98 प्रतिशत थी जबकि आज भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री प्रणब मुकर्जी ने कहा है कि भारत सरकार की ग्रोथ रेट 71 प्रतिशत होगी। इस साल हमारा ग्रोथ रेट आलरेडी छ परसैंट है। पिछले साल मैंने कहा था कि चिदम्बरम ने अपने भाषण में कहा था कि यदि हम आने वाले 5 सालों में छ और छ परसैंट के बीच में ग्रोथ रेट बनाकर रखें तो 10–12 सालों में हम इस देश से गरीबी को जड़ से खत्म कर सकेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर हम ग्रोथ रेट 11, साढ़े 10,10 और 9 परसैंट पर कायम रख सकें तो 6 साल के अंदर–अंदर हरियाणा से बी०पी०एल० और गरीब नाम का शब्द खत्म हो सकता है। ये शब्द हमने उस समय कहे थे। मैं फिर यही कहूँगा कि इस ग्रोथ को, इस बढ़ोतरी को कायम रखने के लिए हमें आज सोचना पड़ेगा, यह नहीं कि फिगर्ज में घाटा कहां है फायदा कहां है। प्रो० अमृत्या सैन जो कि बहुत बड़े नोबल पुरस्कार विनर हैं जिन्होंने इक्नोमी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने इस बारे में कहा है कि – Alongwith old slogan of growth with equity, we also need a new commitment towards down turn with security. If the economy is going down then we must ensure security for our people, security for our handicaps, security for our old people and security for women. He also asserts the fact that occasional down turns are common, possibly inescapable in market economies. Employment generation schemes have to be expended and social securities have to be strengthened to protect vulnerable section of our society. Smt. Sonia Gandhi, Chairperson of United Progressive Alliance has also said that equitable

economic growth has to be sustainable. It cannot be said that at one point of time you are growing at the rate of eleven point something or ten point something and the next year there is dip of 6 per cent. So, Smt. Sonia Gandhi has made it clear that to be equitable economic growth has to be sustainable. To be sustainable economic growth has interned to be all inclusive and all inclusive is no longer the greatest good of the greatest number. It is actually `Sarvodya' or the rise for all. This should be a concept of growing economy on which Smt. Sonia Gandhi has also commented upon. Speaker Sir, now how to make the economies sustainable? There, I would like to compare what Mr. Pranab Mukherjee has said in the Parliament that for the first four years of the United Progressive Alliance Government, our policies ensured a dream run for the economy with gross domestic product recording an increase of 7.5% to 9.5% from fiscal year 2004-05 to 2007-08. For the first time Indian economy was showed sustained growth which I was talking while quoting Smt. Sonia Gandhi. Growth of 9% for three consecutive years with per capita income growing at the rate of 7.4% per annum. This represented fastest ever improvement in living standards over a four years of period. During this period the fiscal deficit in the Government of India came down from 4.5% to 2.7% in 2007-08 and 3.6% to 1.1% in 2008-09. स्पीकर सर, मैंने इसलिए यह बात कही कि how we have become so well? How we have supported this direction that the economy should be sustainable? स्पीकर सर, मैं यह भी कोट करना चाहूँगा कि जिस समय 2004–05 में विपक्ष के भाईयों की सरकार थी उस समय स्टेट जी०डी०पी० ग्रोथ रेट छह प्रतिशत था and when we took

over the State, our growth rate went up from 8.6% to 9.4%. Speaker Sir, in the next year 2006-07 it went up from 9.4% to 14.2% and again in 2007-08. it was 9.3%. Now Sir, when the country's Finance Minister is quoting 7.1% growth rate in 2009-10, we are expecting 9.7% of the growth rate in the next year. (इस समय मेजें थपथपाई गई।) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि कई चीजों में हमने नये क्रीतिमान स्थापित किए हैं। हमारा जो टैक्स कलैक्शन है उसमें we are number one in the entire country. Per capita tax collection of Haryana is at the top in the country. टैक्स कलैक्शन में हमारे से दो राज्य ऊपर हैं। एक दिल्ली है जो देश की राजधानी हैं और जिसकी ज्योग्राफी भी हमारे से अलग है। दिल्ली में देश के बड़े–बड़े धनाड्य लोग रहते हैं। वहां की टैक्स कलेक्शन 5350 रुपये पर कैपिटा है। गोवा भी टैक्स कलैक्शन में हमारे से आगे है जिसकी population 13 लाख है। गोवा की पर कैपिटा टैक्श कलैक्शन 6500 रुपये है। इन दोनों राज्यों को छोड् कर बहुत से छोटे और बड़े राज्य हैं जिनमें महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्य भी हैं जहां पर बड़ी–वड़ी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं। हमारा टैक्स कलेक्शन उन सब से अधिक है। हमारा पर कैपिटा टैक्स क्तैक्यान 3415 रुपये है which is highest in the country as far as bigger State are concerned. अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी ने बजट अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि बजट डैफीसिट बहुत ज्यादा है उसकी प्राप्तियां कहां से हो पायेंगी। मैं इन्दौरा जी और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार

का बजट आया है इसमें central assistance to the States in the Union budget has been enhanced by 11%. इसमें 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा उन्होंने रखा है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं दोबारा कहना चाहूँगा जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमने जो बजट बनाया है वह इसलिए नहीं बनाया कि इसको घाटे का बनाना है, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अगर हम डिवैल्पमैंट की एक्टीवियईज नहीं करते तो सरकस बजट होता। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा स्टेट ऐसा स्टेट है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास 3 हजार करोड़ रुपये अपने सुरक्षित जमा करवा रखे हैं जिस पैसे को हम किसी भी समय ले सक्ते हैं and you will not believe it that we are not entitled to reflect Rs. 3000 crore in our budget, if we would have been entitled for that then our budget is more. So this is in one sector. इसके अतिरिक्त मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो फिसकल डैफीसिट का टोटल अमाउंट है उसका हम 3 प्रतिशत मार्केट से उधार पर उठा सकते हैं जिसकी सीमा साढ़े चार हजार करोड़ रुपये तक की है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगले साल भी हम अपने किसी काम को बंद नहीं होने देंगे। अगले साल के लिए जो पैसा अलोकेट किया है वह इतना किया है कि कई महकमों को तो हमें कहना पड़ता है कि आप पैसा खर्च करो वरना पैसा बिना खर्च रह जायेगा। स्पीकर सर, हमारा अनुमान है कि अगले साल हमारा 35 हजार करोड़ रुपये का खर्चा होगा, हमें अनुमान है

कि अगले साल के दौरान हमें 82 हजार करोड़ रुपये के करीब रेवेन्यू रिसीट्स मिलेंगी और तीन हजार करोड़ रुपये का घाटा है।

श्री नरेश मलिकः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि तीन हजार करोड़ रुपये आज भी हमारे पास सुरक्षित है। स्पीकर सर, हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पिछले तीनों सालों के दौरान भी बहुत अच्छा और हैल्दी बजट पेश किया है और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस दौरान हमारे प्रदेश की रेवेन्यू रिसीट्स काफी बड़ी हैं। अगर आलमोस्ट देखा जाये तो आज हमारी रेवेन्यू रिसीट्स डबल से ज्यादा हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से एक बात जानना चाहता.हूँ कि वर्ष 2001 से 2005 तक जो रिपेमैंट आफ लोन्ज स्टेट के थे वे 16878 करोड़ रुपये के थे और वर्ष 2006 से 2010 तक केवल 8203 करोड़ रुपये थे। अध्यक्ष महोदय, उस समय 2354 करोड़ रुपये व्याज देना पड़ता था और आज हमें 3001 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। इस प्रकार से आज हमारा 700 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में ज्यादा जा रहा हे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय और सरकार से यह कहना चाहूँगा कि वे अगर तीन साल पहले इस बारे में थोड़ा सा और चौकन्ने हो जाते तो मेरे विचार से आज यह स्थिति नहीं आती कि हमारा बजट आज लौस में जाता यानि 700 करोड़ रुपये हमें महज व्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है

और जो रिपेमैंट आफ लोन है वह पिल्ली सरकार की तुलना में सिर्फ 5० परसैंट किया गया है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो बात कही हे मैं इस पर भी आना चाहता था और माननीय साथियों को इस बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। स्पीकर सर, किसी राज्य का जो फिसकल मैनेजमैंट है उसमें जो स्टेट का जी०डी०पी० है उसका 28 परसैंट तक लोन लेने का हमें अख्तियार है या उधार चढ़ाने का अख्तियार है। देसी भाषा में यह कहा जाये कि मान लीजिए अगले साल हम एक्सपैक्ट करते हैं कि हमारी स्टेट का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो लाख करोड़ से ज्यादा होगा। दो लाख करोड़ का मतलब यह है कि अगर 28 परसैंट हमें अलाऊ करें तो 56 हजार करोड़ रुपये की उधार हम ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की खुशी होगी कि हमारा वह 28 परसैंट की बजाये सिर्फ 197 परसैंट है। इस प्रकार से अभी भी हमारे पास 1० परसैंट का कुशन है। स्पीकर सर, जो पैरामीटरज ब्लारब्बी०एम० में निश्चित किये गये थे उन पैरामीटरज को हमने निभाया है और वे पैरामीटरज हमें 'आज के दिन अलाऊ करते हैं और मैं यह कह सक्ता हूँ कि we are the best economy as far as other States in the country are concerned. स्पीकर सर, हमने अपने सार्थक प्रयासों से दूसरे राज्यों को कर दिखाया है कि हमारा अर्थतंत्र मजबूत है। Speaker Sir, when I was attending the meeting of Empowered Committee and the Chairman of the Empowered Committee asked me what is your total collection

from taxes. Speaker Sir, when I told him that from VAT itself our collection is more than eight thousand crore rupees. The entire House was stunned to know this. Orrisa Finance Minister told me that his total tax collection was eight thousand crore whereas our tax collection from one head i.e. VAT was more than eight thousand crore rupees. So we are the best economy as far as the figures are concerned. स्पीकर सर, दूसरी एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूँगा कि यह जो विपक्ष के साथी पूछ रहे हैं कि हमें ब्याज कितना देना पड़ता है। स्पीकर सर, जब हमने एफ०आर०बी०एम० एक्ट पास करवाया तो उसमें कंडीशन थी कि अगर आप एफ०आर०बी०एम० की कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो जो लोन 11, 12 और 14 परसैंट पर सरकार दे रही थी जो इनके शासन काल का लिया हुआ था वह हम आपको 10 परसेंट से नीचे लाकर देश। स्पीकर सर, उससे हम 300 करोड़ रुपये प्रत्येक साल का बचाते थे और वह भी सिर्फ हमारी एफिसिएन्ट फिसकल डैफिसिट मैनेजमैंट की वजह से है।

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर है।

Shri Birender Singh : He has no point Sir, Let me explain.

श्री अध्यक्षः हाँ जी, सढौरा साहब क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं एक तरफ तो इन्होंने आन दि फ्लोर आफ दा हाउस कहा है कि हम एमपावर्ड कमेटी की मीटिंग में गये थे और जव हमने कहा कि वैट से हमें 9 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है तो हमारी बल्ले–बल्ले हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि आप बड़ी वाह–वाह करते थे कि हमारे को वैट से कलैक्शन होती है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन सी बात हम सच्ची समझें वैट बछिया था या बढ़िया नहीं था।

श्री अध्यक्षः सढौरा साहब, ऐसा है, हर चीज के दो पहलू होते हैं अच्छा भी और बुरा भी। उसको इम्पलीमैंट करने का तरीका ठीक हो तो वह ठीक है।

Shri Birender Singh : I have a specific reply for this. We never criticized VAT. Our criticism was only to this extent that VAT should not be levied in any State in isolation. We never wanted that Haryana should impose VAT and rest of the States should not imposed VAT. My party's policy was always clear on this issue. We are for VAT. We support VAT but we will not say that this should be levied and imposed in isolation. That was the stand of the party. अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ये विपक्ष के हमारे साथी कह रहे हैं कि इतना डैफिसिट हो गया, यह हो गया, वह हो गया और इसका इन्तजाम कैसे करेंगे। इनके राज में इनके चहेतों को छोड़ कर

नौकरियों पर टोटल बैन था और मैं अब जब फाईल देखता हू। कि चौटाला जी के राज में सरकार ने राईट साईजिग कमेटी बनाई थी और हर महकमे की नौकरियों को काट कर रख दिया था। उस राईट साईजिंग का कारण यह था कि इनके टाईम में जो इकानोमी थी उसको ये ठीक मैनेज नहीं कर सक्ते थे और इनको किसी ने सिखा दिया होगा कि अगर आप नौकरियाँ ना लगाओ तो आपका काम ठीक चल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में अगर आप लोगों से नौकरी के अधिकार को ही छीन लेंगे तो उससे असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं but I would congratulate the Chief Minister.

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, 25 हजार तो इन्होंने निकाले हैं वे हमारे ही लगाये हुये तो थे। इसीलिए तो आपने उनको हटा दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिल्ली सरकार ने आऊट सोर्सिंग की एक पॉलिसी बना दी थी और आऊट सोर्सिंग में क्या होता है? चाहे चपड़ासी हो, चौकीदार हो, स्वीपर हो जो भी 8वीं पास या 10वीं पास और अनपढ़ गरीबों के लिए सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध हो सकती थी, उन नौकरियों पर ताला लगा दिया गया था और यह फैसला हुआ था कि ये सब आऊट सोर्सिंग से, ठेकेदार के माध्यम से नौकरियाँ लगाई जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार को जो 6 परसैंट मिलता

है वह तो लेते ही थे साथ ही वह 50 आदमी लगा कर 50 आदमियों का काम लेते थे और 50 का वेतन लेते थे और उन लोगों से जिनका छ घंटे ड्यूटी करने का अधिकार है उनसे 12 घंटे से 16 घंटे तक काम लिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, हमने अब इस प्रथा को खत्म कर दिया है। चाहे भारत सरकार में भी यह प्रथा हो लेकिन हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने यह काम किया है। आज हमने यह फैसला लिया है कि कोई भी क्लास–4 का इम्पलाई हम आऊट सोर्सिग से नहीं भरेंगे। हम उसके लिए सीधी भर्ती करेंगे, उसको सरकारी नौकरी देंगे और उसको पूरा पैसा देंगे। हमने एक कमेटी का गठन किया है। राज्य स्तर पर अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है जितनी भी नौकरियां होगीं चाहे 4 हजार हों या 6 हजार ही, उन सबको उस कमेटी के माध्यम से भरा जाएगा। उनकी सलैक्शन उस कमेटी के माध्यम से ही की जायेगी और इनके राज में ऐसी प्रथा थी कि जो गरीब आदमी है जिसको प्रोटैक्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी को इग्नोर किया। एक एच०सी०एस० आफिसर तो सरकारी लग जाए, एक एस०डी०ओ० या एक जे०ई० तो सरकारी लग जाए लेकिन जो उसका बेलदार लगे उसे काट्रैक्टर लगाए और उसका शोषण करे इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। हमने इस प्रथा को खत्म किया है। (विघ्न)

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्वांयट ऑफ ऑर्डर है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह

पूछना चाहूँगा कि पब्लिक हैल्थ में जो चार हजार टयूबवैल ऑपरेटर्ज रखे हैं क्या वे सीधी भर्ती से रखे हैं या ठैकेदारी प्रथा के तहत रखे हैं। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, वे सीधी भर्ती से रखे गये हैं इसमें कोई ठेकेदारी नहीं है। (विघ्न) स्पीकर सर, हरियाणा में एम्पलॉईज की जो टोटल स्ट्रैंग्थ है जिसमें कारपोरेशन्ज, बोर्ड्ज और दूसरी जो फैडरेशंज भी हैं उनमें जो सरकारी कर्मचारी हैं they are around three lacs fifty thousand, may be some more than three lacs fifty thousand. सर, हमने सारी नौकरियाँ खोली और नौकरियों पर जो बैन लगा हुआ था उसको हटाया। स्पीकर सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि अब तक हमने 18 हजार नई नौकरियाँ सर्विस सिलैक्शन कमीशन के माध्यम से दी हैं। आठ हजार नौकरियाँ पुलिस डिपार्टमैंट में दी हैं। सात हजार नौकरियां हम ऑलरेडी एडवर्टाईज कर चुके हैं। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट में साढ़े तीन हजार कर्मचारी हमने लगाए हैं। गांवों में जो 11 हजार सफाई कर्मचारी लगने हैं उनमें से नौ हजार सफाई कर्मचारी लग चुके हैं और इन–पोजीशन हे। एम०आई०टी०सी० के कर्मचारी जिन पर इनका छुरा चला था इनकी तलवार चली थी उनको इनकी सरकार ने नौकरियों से निकाल कर रख दिया था उन चार हजार आदमियों को हमने दोबारा नौकरियों में लिया है। इसके अलावा एक हजार और ऐसी असामिया हैं जो गवर्नमैंट नौकरियों में खासतौर से हैल्थ डिपार्टमैंट में लगाने हैं। इसके इलावा 720 कैनाल गार्डज भी हमने लगाए हैं। इस तरह से 43,500 नौजवानों

को हम अब तक एम्पलॉयमैंट दे चुके हैं (इस समय मेजें थपथपाई गई) और इसके अलावा सात हजार पोस्ट्स हमने ऐडवर्टाइज की हैं पुलिस की और पांच हजार पांच सौ के इन्टरव्यू हो चुके हैं और उनके रिजल्टस कभी भी निकल सकते हैं। स्पीकर सर, पन्द्रह हजार टीचर्ज की वैकेंसी हम और ऐडवर्टाइज करने जा रहे हैं। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके और कारनामे दिखाए हैं। पन्द्रह हजार टीचर्ज की वैकेंसीज हम ऐडवर्टाइज करने जा रहे हैं और जहां पर खाली स्थान हैं वहां हम उनको लगाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक हजार अंग्रेजी के टीका हम ऐलिमैंट्री ऐजूकेशन के लिए लगाएंगे। इससे जुड़े हुए सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ क्योंकि इन लोगों को इस जात की बड़ी उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश होने से पहले घोषणाएं क्यों की? (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, मैं एक जानकारी चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः इन्दौरा साहब, आप यह बताएं कि जो एनाउसमैंट हुई वह अच्छा हुआ या बुरा हुआ (विघन)

डा० सूशील इन्दौराः स्पीकर सर, यह रेयर इंस्टांस हैं। पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग जो समझते हैं वह दुआ। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, आज के दिन जो पाईपलाईन में हैं और जो हम निकाल रहे हें लगभग 75,100 लोगों को हमारी सरकार नौकरी देगी। जिस सरकार के एम्पलाईज की संख्या लगभग साढ़े तीन लाख है और इस बात को हम समझते थे कि इसका भार बज? पर पड़ेगा लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। हमने यह कहा कि हम अपने नौजवानों को, जो पढाई करते हैं, उनके माँ–बाप पैसा लगाकर उनको अच्छी पढ़ाई करवाते हैं उनको अगर हम रोजगार नहीं दे सकते तो यह ठीक नहीं है। स्पीकर सर, मैं यह भी कहूंगा कि हजारों बच्चे ऐसे हें जो नौकरी में लगे हैं।

डा० सीता रामः स्पीकर सर, छठे पे कमीशन के मामले में मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। सैंट्रल गवर्नमैंट ने जो पे कमीशन दिया है उसका जिक्र इन्होंने किया था। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि क्या वे इन टीटो सिक्सथ पे कमीशन मूलरूप में सभी कर्मचारियों के लिए लागू करेंगे? (विघ्न एवं शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस प्वायंट पर जब आऊंगा तो मैं इनको बताऊंगा। (विघ्न) आप बैठ जाएं मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। सर, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 1992 से 1995 तक सरकार द्वारा तीन सालों में 10 हजार नौकरियां दी गई, 1996 से 1998 तक 11 हजार नौकरियां दी गई और इनके पांच साल के राज में 1999 से 2004 तक 15,765 नौकरियां दी थी। स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब है कि पिछले 12 साल में जो

टोटल नौकरियां दी थी वे लगभग 36,765 दी गई। जबकि हमारे केवल चार सालों के राज में 43,500 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हें और हमारा टोटल अगर सभी विभागों का देखे तो यह टारगेट 75,100 का है। इन्दौरा जी, आप इस बात को सुनने के उत्सुक हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बजट से पहले क्यों घोषणाएं की। आज ऐसी बातें करके अखबारों में सुर्खियां बटोरने की बात कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय, इनको एक गलतफहमी हो जाती हे कि इनसे ज्यादा इंटैलिजैंट कोई नहीं है। कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी को इस वात का इल्म है and he understands that he is not the depository of all the wisdom. इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने साथियों से ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी सलाह करते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, आपकी सलाह भी मानते हैं। इन्होंने 100 से 150 कहा था और आपने उसको 200 करने को कहा था। इन्होंने उसको भी मान लिया था। आप जो वस्तु स्थिति है उसको तो मानें।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, आपको तो पता ही होगा दो साल पहले मैं बजट पद रहा था तो बहिन करतार देवी जी ने यहां मेरे पीछे से बैठे–बैठे यह कहा था कि सोशल वैलफेयर के लिए जो स्प करोड़ रुपए का बजट रखा है, वह कम है, आप इसमें 20 करोड़ और बढ़ा दो। मैंने मुख्यमंत्री जी रो कहा कि बहिन करतार देवी जी की बात ठीक है। स्पीकर सर, तो मेरे ये सामने

बैठने वाले साथी कहने लगे कि 60 करोड़ रुपए की बजाए 120 करोड़ रुपए कर दो, 60 करोड़ ही बढ़ा दो। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहां पर ऐसी घोषणा करने की हैसियत रखते हैं, पैसे का प्रावधान कर सकते हैं। इन्दौरा जो, आप इस बात को तो मानेंगे कि हमने इन चार सालों में कोई नया टैक्स नही लगाया है। हमने तो टैक्सों में रिडक्यान की है।

डॉ० सुशील इन्दौरा: आपने एन्ट्री टैक्स लगाया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप अपनी सीट पर बैठें मैं इसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। Sir, again, they have been caught on a wrong foot. Speaker Sir, they had introduced the LADT when they were in power. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी, जब आप बजट पर बोल रहे थे तो आपकी सारी बातें फाईनांस मंत्री जी नोट कर रहे थे और अब आपका जवाब दे रहे हैं। (विघ्न) आपको अगर कुछ पूछना है तो I allow you after the speech of the Finance Minister. मैंने सभी को बोलने का मौका दिया था और अब बार–बार प्वायंट आफ ऑर्डर, प्यायंट आफ ऑर्डर करके बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी आप अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न) ऑनरेबल मिनिस्टर बजट पर रिप्लाई दे रहे हैं। क्या आप अपनी बातों की रिप्लाई को सुनना नहीं चाहते हैं? (विघ्न)

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, they were also asking for point of orders when I was speaking.

Mr. Speaker : No question, No point of order. Please take your seat.

Shri Birender Singh : Indora ji, I remind you that LADT Bill was brought by your Government on the floor of the House. When it was struck down by the Hon'ble High Court and the appeal was pending in the Supreme Court, we thought that it would be better to introduce a new legislation and that was called Entry Tax. So, that is not our creation. We just improved upon what you did in your regime. सर, मैंने जैसे बताया कि इनके समय में जिसको डवैल्पमैंट कहते थे वह खत्म हो चुकी थी और जो सरकार में बैठे लोग थे उनके वैस्टेड इंट्रस्ट थे and they wanted Haryana to be their fiefdom, उसको वे अपनी जागीर समझने लग गए थे और यही कारण था कि हरियाणा के लोगों ने उनको रिजैक्ट कर दिया। हरियाणा के लोगों ने यह मान लिया कि अब वे पहले वाली गलती नहीं करेंगे। स्पीकर साहब, जन आक्रोश यात्रा निकालकर इन्होंने पोलिटिकली गलती की है क्योंकि जो उस समय के कान टूटे हुए आदमी थे वे चार साल बाद फिर नजर आ गए हैं। (हंसी) सर, मैं सही कह रहा हूँ। इन्होंने दो बड़ी गलियों की हें। मैं यह चाहता हूं कि ये फले फूले क्योंकि अगर इनकी राजनीति में कोई जगइ होगी तभी तो हमारे को भी लोग तोलकर देखेंगे कि हम अच्छे हैं या नहीं। इन्होंने जो जनआक्रोश यात्रा निकाली है उससे इन्होंने अपने पुराने दिनों की याद दिला दी।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, कान टूटने का क्या मामला है? (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, एक और बात जो सबसे जरूरी है, जिसका जिक्र मैं अब करना चाहूँ।।। हमने इस बजट में 1500 करोड़ रुपये का स्टीमूलस इकोनोमी पैकेज दिया है और उसका कारण यह है कि अगर वह स्टीमूलस पैकेज हम नहीं देते तो हमारी जो ग्रोथ है उसमे ठहराव आ जाता यानी वह स्लोडाउन हो जाती जोकि आल ओवर –वर्ल्ड हो रही है। सर, हमने करत करोड़ रुपये जो बजट का हिस्सा नहीं है वो भी हम दे रहे हें हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा जाव जैनरेट हों, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के साधन मिलें और हमारा जो फिजीकल इंफास्ट्रक्चर हे उसको भी हम इससे मजबूत कर सकें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने खालों को पक्का करने का योजनाबद्ध तरीके से फैसला किया था। दो साल में हम हरियाणा में जितने भी वाटर चौनल्ज हैं, उनको पक्का करेंगे। इसके लिए हमने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के साथ–साथ हमने यह भी कहा है कि जो नरेगा में हमें पैसा मिलेगा तो उस पैसे को हम इसमें जोड़कर जो लेबर कम्पोनैंट ज्यादा है, उसको हम नरेगा से प्र कर सकते हैं। इससे हरियाणा के किसान को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तो फायदा मिलेगा ही लेकिन साथ ही गरीब आदमियों को भी हम नरेगा के माध्यम से पैसा

देंगे। इसके साथ ही साथ हरियाणा में महिलाओं के लिए सोनीपत के खानपुर में एक मैडीकल कॉलेज स्थापित करने का भी हमने निर्णय किया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान इसी फाईनैंशियल ईयर में हमने किया है। सर, उस कॉलेज के लिए जो 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है वह स्टीमूलस पैकेज का है which is not the part of the budget of Health Department and there is also a provision available in the Health Department Budget for the same cause. इसी तरीके से हमने जो कंस्ट्रक्शयन की ऐक्टिविटीज हैं, उनको बढ़ाने का काम भी किया है। यह सही बात है कि आज के दिन जो स्लो डाउन है उसका सबसे बड़ा प्रभाव हरियाणा में कहीं पड़ा है तो वह कंस्ट्रक्शन ऐक्टीविटीज पर पड़ा है। इसलिए हम अपनी उन्हीं ऐक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही अपने प्रदेश के इंडस्ट्रियल वर्कर्ज को काम देना चाहते हैं इसलिए हमने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए नए क्वार्टर बनाने का प्रावधान किया है जिससे कैस्ट्रक्यान ऐक्टिविटीज को हम बढ़ा सकें। इसके साथ ही साथ पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग जो महकमा है उसके लिए भी 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। ये सारे प्रोजैक्ट्स अगले दो साल तक चलेंगे। 1500 करोड़ रुपये का जो बचा हुआ अमाउंट है उसका प्रावधान हम अगले साल करेंगे। जैसा मैंने बताया कि आज के दिन अगर हम डिवैल्पमैंट ऐक्टिविटीज के लिए ज्यादा पैसा नहीं जुटा सकेंगे तो टोटल जो स्कीम हैं वह बैकफायर भी कर सकती हैं। अमेरिका में इसके लिए 900 बिलियन

डालर से ज्यादा पैकेज ऐनाउस हुआ है। उसके बावजूद भी उनकी इकोनोमी अब तक लाइन पर नहीं आ पा रही है उसके लिए और पैसे की जरूरत है। हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यह माना है कि हरियाणा के लोगों को कहीं जॉब्स की जरूरत पड़ेगी तो वह देना तभी संभव है जब हमारे विभिन्न महकमों में उनको हम काम दे सकें और उनसे काम ले सकें। अध्यक्ष महोदय, केवल यही बात नहीं, जीव अपोर्चुनिटीज कै लिए हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारे यहा जो पढ़े–लिखे नौजवान हैं उनको हम बेरोजगारी भला देंगे। इससे पहले जो सरकार थी इसने वोट लेने के लिए सितम्बर, 2004 में ऐलान किया था कि मैट्रिक वाले को 100 रुपये और ग्रेजुएट को 200 रुपये बेरोजगारी भला दिया जाएगा। हमने सभी बातों का ध्यान रखा है। आजकल 100 रुपये में आता क्या है, यह तो उनके साथ एक मजाक था। हमने एक फैसला किया और दो दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसमें सबसे बड़ा कंपोनैंट ये है कि जिस बच्चे को 200 रुपये मिलना था अब उसको 1500 रुपये प्रति महीने मिलेगा। अगर इनकी सरकार आ जाती तो उन बच्चों को 200 रुपये प्रति माह ही मिलता। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि बेरोजगारी भले का मतलब यह नहीं है कि आप उस बेरोजगार बच्चे पर कोई अहसान कर रहे हैं। बेरोजगारी भले का मतलब मैं यह मानकार चलता हूं कि जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक वह अपने माता–पिता पर आश्रित नहीं होना चाहिए। उसके पास कोई भी ऐक्टिविटी करने के लिए इतने साधन जरूर हों कि कहीं परीक्षा

देने जाने के लिए टिकट लेने के पैसे उसके पास हों और उसे अपनी मां से, बड़े भाई से या पिता से पैसे न मांगने पड़ें। 1500 रुपये इसके लिए अच्छी अमाउंट है और लड़कियों के लिए हमने डयोढा पैसा दिया है। (विघ्न)

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर सर, ठीक है, लेकिन यह बात चुनाव सिर पर है तब याद आई हे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इनकी यह बात बिल्कुल गलत है। हमने जब हमारी सरकार आई थी तब भी इसको बढाकार 300 रुपये और 500 रुपये किया था।

श्री अध्यक्षः अनाउसमैंट तब होती है जब कलैक्शज हों, कलैक्शज ही नहीं होगी तो अनाउसमैंट क्या होगी। (विघ्न) इन्दौरा साहब, आप अपने पीछे के बजट देखो क्या इन्क्रीज होती थी। कहां जाता था पैसा? उस समय जब ऑक्शन होती थी तब ठेके अपने चहेतों को दिए जाते थे।

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, इस साल से पिछले साल के आकड़े देखो।

Mr. Speaker : Please Dr. Indora, don't interrupt the proceedings, (Interruptions)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, आज से लगभग तीन साल पहले जो बेरोजगारी भत्ता 100 रुपये दिया जाता था वह इस

सरकार ने 300 रुपये किया है that is on record. जो 200 रुपये थे उसको 500 रुपये किया है। आप पता तो करो। एक मार्च 2008 को वर्तमान सरकार ने तीन साल पूरे किए थे और लगभग चार साल होने वाले हैं। उस समय हमने यह कदम उठाया था। इसके साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इनेलो के नेता हमारी सरकार को क्रिटीसाईज करते हें कि इस सरकार ने बच्चों को विदेश भेजने का वायदा किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। स्पीकर सर, इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हमने एक प्लेसमैंट ओवरसीज ब्यूरो नाम की सोसायटी कायम की है। ऑन रिकॉर्ड मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि उस सोसायटी के माध्यम से हमने दो साल में 150 से ज्यादा बच्चे विदेश भेजे हैं। आप इस बारे में पंजाब से पता कर लें जिन्होंने 13 सालों में केवल 300 बच्चों से ज्यादा नहीं भेजे हैं, जिनमें ज्यादातर नर्सिज हैं। इसके अलावा 100–125 बच्चे जो हायर ऐजूकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको भेज चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैवल एजेन्ट्स का इसमें बड़ा भारी नेटवर्क रहा है, उसको इतनी जल्दी तोड़ना आसान नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा के बच्चे आज से 20 साल पहले बड़े इन्ट्रोवर्ल्ज थे वे विदेश में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन आज उनके मन में यह लालसा है और इच्छा हे कि मैं भी बाहर जाकर कुछ पैसा कमाऊ ओर अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। उस उत्साह को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है और हमें विस्वास है कि यह जो प्लेसमैंट सोसायटी है, वह बच्चों को रोजगार देने में कारगर

साबित होगी और जो कबूतरबाजी के सौदे हैं उनको ख्य करेगी। यह जो हमारा फैसला था उसमें हम कामयाब हुए हैं। स्पीकर सर, दूसरी बात जो मैं रखना चाहता हूँ वह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी घोषणाएं की थी जैसे ओल्ड ऐज पैंशन की, डिसएब्लिटी एलाउंस की और विडोज के लिए पैसा देने की बात थी। कुछ साथियों ने यह कहा कि विडोज की पैंशन में उतनी इन्क्रीज नहीं की जितनी ओल्ड ऐज की पैंशन में की है। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात आ गई है। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। सीकर सर, हमारी और क्या जिम्मेवारी है यह भी हमें देखना होगा। बहुत से ऐसे केसिज हैं, ओल्ड ऐज पैंशन वाले जेसे कुछ लोग आज भी 60 साल के नहीं हुए हैं और वो 4–5 और 6 सारन से पैंशन ले रहै हैं। क्योंकि आपने उनके। आदत खराब कर दी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब गांव का सरपंच और पंचायत यह कहने में सक्षम नहीं है कि इस आदमी को गलत दिया गया है या सही दिया गया है, कौन इस बात को डिटैक्ट करेगा और कौन उसकी पूछताछ करेगा? मैं यह मानता हूँ कि सही बैनीफिसरीज को यह पैंशन का पैसा मिलना चाहिए। जो ऐसे आदमी इसे डिजर्व नहीं करते, जिनके घर भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, उनका यह हक नहीं बनता कि वे गरीब का पैसा रखें। इसलिए हमने निर्णय लेते वक्त जब जो ओल्ड ऐज पैंशन बुजुर्गो की 500 रुपये से 700 रुपये की है तब यही बात उसके पीछे थी कि जो बुजुर्ग 10 साल से पैंशन ले रहा हे और उसका सारा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा कि फलां आदमी

दस साल से पैंशन ले रहा है तो वह 200 रुपये की अतिरिक्त पैंशन का हकदार होगा। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आपको हरियाणा में नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। जिस किस्म की राजनीति विपक्ष के लोग करते हैं वैसा नहीं चलेगा। वैसे तो आज विपक्ष के सदस्य बहुत क्षीण हो गये वरना तो ये अभी तक क्या हमारे को जीने देते? चौटाला साहब सदन में नहीं आये मैं यह समझता था कि साल भर शर्म होती है बहुत बुरी हार की। विदेश चले जायेंगे। उसके बाद कुछ जमेगा फिर आकर के बोलेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं रामकुमार गौतम जी की मलाई के लिए बोल रहा हूँ। मेरा अपना यह मानना था कि एक साल में, दो साल में इनमें कुछ हौसला होगा, ये मैदान में आएंगे और यहाँ लोगों की बात करेंगे लेकिन इनको लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम को माफ करो। इस सरकार से हमें जो उम्मीद भी नहीं थी उससे भी बहुत ज्यादा हमें मिल गया है। अब लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं। आपने गलती से सियासत की और उस सियासत को आपको भुगतना पड़ेगा। आज अगर आपके नेता में साहस हो तो उनको यहां आना चाहिए और यहाँ अच्छे सुझाव देने चाहिएं। आपने तो कह दिया कि यह घाटे का बजट है।

श्री अध्यक्षः उनको सदन से जरूरी शायद कोई काम रहा होगा।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, राजनीति में राजनीति करने का ही काम होता है। लोगों ने उनसे वह काम छुटवा दिया है। इनको और कोई काम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for half an hour ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : Alright, the time of the sitting of the House is extended for half an hour.

वर्ष 2009–2010 के लिए गजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत से सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं जिनके बारे में मेरे कुछ मंत्री साथियों ने उनके विभाग से सम्बन्धित जवाब भी दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने ऐसी बातें भी की हें जो उनके चुनावी क्षेत्र से सम्बन्धित थी। मैं नहीं समझता कि मैं उनका जवाब दूँ क्योंकि वे बातें विभाग के मंत्रियों से सम्बन्धित हैं, उनके नोटिस में आ गया है और उन पर उचित कार्यवाही हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला जी ने यह कहा कि जो हिसार में वैटरनरी कॉलेज है, वह बहुत पुराना है और रैपुटिड कॉलेज है, उसको यूनिवर्सिटी में कंवर्ट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप इस वात को मानेंगे कि जितना इकास्ट्रक्चर, जितना ढांचा हमने शिक्षा के लिए और

खासकर उच्च शिक्षा के लिए इन 4 सालों में बनाया है, इतिहास में किसी राज्य ने भी शायद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया होगा। हमने 4–4 नई यूनिवर्सिटीज दी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सुरजेवाला जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले साल के बजट में वैटरनरी यूनिवर्सिटीज के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। ज्यों ही प्रशासन से होकर यूनिवर्सिटी का बिल कैबिनेट के पास आएगा हम इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कंवर्ट कर देंगे क्योंकि सैद्धांतिक रूप से सरकार और मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए माना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूँ कि हरियाणा के गरीब को उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसकी मदद हमें करनी है। उसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि हमारा जो पशु पालन का काम है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा और हो सकता है कि इनका भी दृष्टिकोण यही हो इसलिए ये वैटनरी यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। अगर गांव में 200 किसान हैं तो उसमें से 20 प्रतिशत किसान ही ऐसे हैं जो अपनी फसल मंडी में ले आने की हैसियत रखते हें और 80 प्रतिशत किसानों की इतनी हैसियत नहीं है कि वे अपनी फसल को मंडी में लाकर बेच सकें क्योंकि उनको अपनी कंजम्पशन के लिए ही कम पड़ता है। जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है उसका भी मुख्य व्यवसाय पशु पालन ही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं देखा है कि गांवों में एक गरीब आदमी भैंस की एक कटडी ले लेता है और उसको दो–तीन साल पालकर उसको 25–30 हजार रुपये में बेच देता हे। उससे उसकी आमदनी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त जो लोग दूध बेचने का

काम करते हैं उनके लिए भी सरकार विचार कर रही हे कि उनको हाई ब्रीड की भैंस दी जा सकें। क्योंकि हाई ब्रीड की भैंस ज्यादा दूध देगी और उसको भी उतना ही चारा खिलाना पड़ता है जितना कि नार्मल भैंस को खिलाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कल सदन में चर्चा हुई थी कि गांवों में डंगरों को पानी पिलाने के लिए स्वच्छ तालाब नहीं बचे हैं। हम भी इससे सहमत हैं। अगर गांव में तालाबों में पशु गंदा पानी पीते हैं तो पशुओं को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जब हम गांवों में अफसोस करने के लिए जाते हैं तो पता चलता हे कि यदि एक गांव में चार मौतें हुई हैं तो उनमें एक मौत कैंसर के कारण हुई होती हैं। यदि पशु ऐसा पानी पीयेंगे तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही होगा। इस समस्य को दूर करने के लिए हमने स्टेबलाईज प्रोविजन किया है। गांवों में तालाबों को स्वच्छ पानी देने के लिए एक नई टैक्नोलोजी आई हे। हमने 50 करोड़ रुपये उसके तहत रखे हैं। उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हरियाणा डेयरी फैडरेशन को सब्सिडी देने के लिए नहीं उनके लोसिज या इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए नहीं बल्कि दूध बेचने वाले जो लोग हैं उनको दूध की कीमत अच्छी मिले। उसके लिए हमने इन पैसों का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ अगर उनका दूध आज के दिन 15 या 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा है उसको जब तक हम क्वांटम जम्प नहीं देंगे यानि उसका रेट डेढा या दोगुना नहीं करेंगे तब तक उनकी आर्थिक स्थिति में कोई

लम्बा चौड़ा सुधार होने वाला नही है। यदि 50 करोड़ रुपये के अलावा और भी पैसा देना पड़ेगा तो वह भी हम देंगे क्योंकि हमने हरियाणा में दूध बेचने वाले गरीब लोग जो गांवों में रहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए यह प्रोग्राम बनाया है। यह प्रोग्राम यहीं तक सीमित नहीं हे बल्कि अगर आज दूध की कीमत मार्केट में 16 रुपये प्रति किलो है तो हमारी फैडरेशन 26 रुपये प्रति किलो दूध खरीदेगी। इस तरह से फैडरेशन मार्केट फोर्सिज को डोमीनेट करेगी और वही दूध जो दूधिया है उसकी मी यह हैसियत नहीं बचेगी कि वह 16 रुपये प्रति किलो दूध खरीदे। उसको भी 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दूध खरीदना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की परिस्थिति प्रदेश में बनेगी तो दूध का व्यवसाय करने वाले गरीब परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने यह प्रोग्राम शुरू किया है।

14.00 बजे

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वैटरनरी यूनिवर्सिटी कब तक खोल दी जायेगी?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बजट में प्रावधान है। सुरजेवाला जी तो बहुत लम्बे समय तक मंत्री रहे हैं, ये तो सारी बातों को समझते हैं कि किस किस तरीके से कैबिनेट

में परपोजल आती हैं लेकिन हमारा तो प्रयास है कि जल्दी ही वैटरनरी यूनिवर्सिटी खोली जाये। जब हमारी सरकार प्रदेश में चार यूनिवर्सिटीज खोल चुकी है तो हमें पांचवी यूनिवर्सिटी खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं विधायक होता तो मैं मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करता कि वैटरनरी यूनिवर्सिटी हिसार की बजाय जींद में खोलनी चाहिए क्योंकि मुर्रा का जो अपीक सैंटर है वह जींद में ही है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से साथियों ने पावर के बारे में भी सदन में चर्चा की है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने या तो बजट पढ़ लिया होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो वे पढ़ लें कि नैशनल पावर लोड फैक्टर में 8 प्रतिशत की इकीज है और हमारे प्रदेश की उसमें 14 प्रतिशत इकीज है। इससे हम जान सकते हैं कि हमने पावर सैक्टर में बहुत काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दावे से कहता हूँ ये इस बात को समझ लें कि 2011 तक हरियाणा में सरप्लस बिजली होगी। हरियाणा के विकास की जो हमने कल्पना की थी वह उस सीमा तक नहीं पहुंची उसमें सबसे बड़ी बाधा बिजली की कमी ही रही है। चाहे वह इण्डस्ट्रियल सैक्टर में हो और चाहे वह एग्रीकल्वर सैक्टर में हो। स्पीकर सर, मैं तो यहां तक कहता हूँ मैंने पिल्ले साल भी यह बात कही थी कि हम 2800 करोड़ रुपये रूरल एग्रीकल्चर सब्सिडी के नाम से पावर यूटीलिटीज को देते हैं। स्पीकर सर, में आज भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये सब्सिडी किसान को मिलनी चाहिये। मैंने इस बात का महकमे से पता भी किया है they are on the job कि ये

जो सब्सिडी है यह किसान को मिलनी चाहिए यह पावर यूटीलिटीज की नहीं मिलनी चाहिए। स्पीकर सर, ज्यादातर ऐसा किया जाता है कि अगर कहीं बिजली की चोरी होती हो तो उसे भी किसान के नाम डाल दिया जाता है और कहीं अगर कोई दूसरे लॉसिज होते हैं तो उन्हें भी किसान के नाम ही डाल दिया जाता है। स्पीकर सर, हम इस दिशा में प्रयासरत हैं कि एक समय आये जब किसान को डायरेक्ट पावर सब्सिडी दें ताकि किसान अपने आप अपना बिल भरें। स्पीकर सर, अगर वह इस तरह से करेगा तो पावर सब्सिडी रिडयूस होगी। स्पीकर सर, मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इस साल कुछ ऐसे रिजल्ट आये हैं जिससे कि पावर सैक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में और यह जो प्लांट लोड फैक्टर है वह भी हमारा 70 परसैंट के करीब है इन सबमें हमारी एफीशिएंशी बड़ी है। स्पीकर सर, जो हमारा प्लांट लोड फैक्टर है जो कि 70 परसैंट है यह नेशनल एवरेज से भी अच्छा है। स्पीकर सर, कई जगह तो 98 परसैंट तक प्लांट फैक्टर रहा है जो बैस्ट एफिशिएंट प्रोजैक्ट्स में हो सक्ता है। स्पीकर सर, मंत्री जी कह रहे हैं कि now, it has reached' upto 78 point स्पीकर सर, यह हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमैंट है। स्पीकर सर, एक बात मैं इम्पलाईज के बारे में भी कहना चाहूँगा कि हमने सिक्सथ पे कमीशन जो कि हरियाणा के इम्पलाईज की मांग थी कि वह सैंट्रल पैटर्न पर लागू हो उसे हमने लागू किया और 01 जनवरी, 2009 से सिक्सथ पे कमीशन के अनुसार भुगतान भी शुरू किया जा चुका है। स्पीकर सर, इस बारे में मैं कुछ

आकड़े देना चाहता हूँ। स्पीकर सर, वर्ष 2008–09 में जो पेमैंट आफ एरियर्स का एडीशनल बर्डन हमारे ऊपर पड़ा है जिसका इस वर्ष हम 40 परसैंट देंगे और अगले साल 60 परसैंट देंगे। इससे हमारे स्टेट एक्सचौकर पर 1740 करोड़ रुपये का एडीशनल बर्डन पड़ा है क्योंकि यह एरियर मिलना है जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2008 तक का। स्पीकर सर, जो पेमैंट हमने जनवरी–फरवरी, 2009 के वेतन के रूप में की है वह 230 करोड़ रुपये अधिक की है। स्पीकर सर, इस प्रकार से 40 परसैंट एरियर के रूप में 1740 करोड़ रुपये, जनवरी–फरवरी, 2009 के वेतन के रूप में 250 करोड़ रुपये की पेमैंट दी है और जो अलाउंसिज रिवाईज हुए हैं। वे मी दिए हैं। स्पीकर सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने पहली बार उन इम्पलाईज को दो बच्चों तक 10 महीनों तक के लिए 500 रुपया प्रति बच्चा दिया है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। यह हरियाणा में हमारी सरकार द्वारा पहली बार किया गया है। स्पीकर सर, इस प्रकार से वर्ष 2008–09 में 2106 करोड़ रुपये का एक्सट्रा बर्डन हमारी स्टेट के एक्सचेकर पर पड़ा है। इसी प्रकार से वर्ष 2009– 10 में 60 परसैंट एरियर की पेमैंट करने पर 2610 करोड़ रुपये का स्टेट एक्सचेकर पर एडीशनल बर्डन आयेगा। इसके अलावा जो वर्ष 2009– 10 का सैलरी कम्पोनेंट है उस पर 1491 करोड़ रुपए और जो रिवाईज्ड अलाउंस 696 करोड़ रुपये के हैं उनका भी बर्डन आएगा। स्पीकर सर, इस प्रकार 4797 करोड़ रुपये प्लस 2105 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 6800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा, एक स्टेट का जिसकी रेवेन्यू

कलैक्शन 23–24 हजार करोड़ रुपये हो उसमें से अस्प करोड़ रुपये अगर हमें इम्पलाईज के एरियर्स के हमें देने पड़े इससे एक बार तो स्टेट का बजट डगमगायेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान में देखा है, वहां पर जो पिछली सरकार थी उसने एक साल का एरियर दिया ही नहीं। महारानी ने मना कर दिया कि हम आपको 2006 से नहों दे सकते मैं तो 2007 से ही दे सकती हूँ। कर्मचारियों ने डैमोन्सट्रेशन भी किया लेकिन वह नहीं मानी। अध्यक्ष महोदय, आपको खुशी होगी और मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सारे देश में पहला राज्य है जिसने उठ के उठ महीने का पूरा एरियर दिया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) यही नहीं मैं तो यह भी कहता हूँ कि बहुत से इम्पलाईज हमसे मिलते भी हैं कि जी हमारा कुछ नहीं हुआ ग्रेड पहले से भी कम हो गया लेकिन मैं एक बात का कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार के सारे कर्मचारियों की अगर कोई शिकायत है, अगर उनकी कोई उचित ग्रिवैंसिज हैं तो उसको एनोमली केटी पूरा करेगी और एनोमली कमेटी से भी अगर कोई बात छुपी रह जायेगी तो मैं यह आश्वासन देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम उनको पूरा इंसाफ देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इन हालात में आगे आने वाले साल में जो हमारा अनुमान है, जो हमारे आँकडे हैं, उसके मुताबिक हमने हर महकमे को पहले से ज्यादा बढ़ा कर पैसे दिये हें। कई साथियों ने सवाल उठाया कि पहले इस मद में 4 रुपये 17 पैसे का प्रावधान था अब की यार 4 रुपये 13 पैसे रह

गया। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बजट की जो वोल्यूम है उसको देखिये। आज से 4 साल पहले हमारा बजट कुल 16 हजार करोड़ रुपये ही था आज वह 35 हजार करोड़ रुपये पहुंचा है तो जो वोल्यूम है वह बोलता है कि स्टेट प्रगति के रास्ते पर है, विकास के रास्ते पर जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें भी चिन्ता है, आपको भी चिन्ता होनी चाहिए और वह क्षेत्र है हमारी चिकित्सा का। जहाँ तक चिकित्सा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में हमें आमूल–चूल परिवर्तन की जरूरत है। गाँवों में हमने बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाये। कहीं पी०एच०सी०, कहीं सी०एच०सी०, कहीं डिलीवरी हट्स बनाये, कहीं पर सब–सैन्टर बनाये लेकिन इन सबसे काम नहीं चलता। चाहे डाक्टर हों, या दूसरा पैरा मैडीकल स्टाफ हो, सबकी कोशिश यही रहती है कि नजदीक के शहर में जाकर रहें। हमने यह भी फैसला किया कि जो रैफल सिस्टम है वह बहुत ज्यादा मजबूत हो।

डॉ० सुशील इन्दौराः डॉक्टरों की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर रखी है उनका क्या रहा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस मामले में उनकी मुख्यमंत्री जी से कल ही मीटिंग हुई है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): ऐनोमली कमेटी उन पर विचार कर रही है और उनका बाद में फैसला हो जायेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि हैल्थ के मामले में हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। जहाँ सोशल सट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, सोशल इम्पावरमैंट की जरूरत है वहीं हमने अपने फिजिकल इनफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया है। सोशल इकास्ट्रक्चर में मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा और हैल्थ ये दो ऐसी मदें हैं जिनमें हमें बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सी चीजों को नये सिरे से तय करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1 हजार अंग्रेजी के टीचर लगायेंगे। 500 टीचर लगाने की तो इन्होंने भी घोषणा 6 साल पहले की थी लेकिन ये एक भी टीचर नहीं लगा पाये।

डा० सुशील कुमार इन्दौराः आपका क्या पता आप भी लगा पाओगे या नहीं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः हम तो जरूर लगायेंगे।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, ऐसा है कि भर्ती तो ये करना चाहते थे लेकिन ये कहते थे कि जब तक जीऊगा तब तक मुख्यमंत्री रहूँगा लेकिन ये मुख्यमंत्री रहे नहीं और इसी वजह से ये भर्ती नहीं कर पाये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, जैसे मैंने कहा कि बहुत से साथियों ने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो उनके चुनाव क्षेत्रों तक सीमित थे। स्पीकर सर, जहाँ तक बिल्डिंग्ज एण्ड रोड्ज की

बात हे, मैंने कहा है और आज भी on the floor of the House मैं यह कहता हूँ कि बजट में चाहे कैसे भी प्रावधान हों कैपिटल असैट्स क्रिऐट करने के लिए कैपिटल ऐक्सपैंडीचर के हैड में जो भी महकमा हमारे से पैसा मांगेगा हम उसको इन्कार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हरियाणा में जो फिजिकल इकास्ट्रक्चर है, वह ढांचा जिसकी जरूरत है, वह बने और उससे ही अच्छे स्कूल्ज बनें, अच्छे होस्पीटल्ज बनें और अच्छी सड़कें बनें। ये सारी की सारी चीजें तभी सम्भव हैं जब बिल्डिंग और रोड्ज की जो मद हैं उसमें कोई कमी न हो। स्पीकर सर, हमारे विपक्ष के साथी यह तो कह देते हैं कि इसमें यह कमी रखी और उसमें वह कमी रखी। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इस साल हमने 798 परसैंट की इकीज बजट ऐस्टिमेट्स में बी०एण्ड आर० के लिए की है जो अपने आप में एक रिकार्ड है। चौधरी शमशेर सिंह जी ने अपने सुझाव देते हुए एक बात कही थी, मैं भी उसका पक्षधर हूँ। स्पीकर सर, मैं यह मानता हूँ कि अगर मेरे से कोई नाराज होता है तो हो लेकिन मैं यह मानता हूँ कि गुडगांव का विकास हरियाणा का विकास नहीं है और जिस बात की श्रीमती सोनिया गांधी ने चर्चा की Inclusive growth is possible only when we have only economy corridors in Haryana and that too was suggested by Shri Shamsher Singh. If an entrepreneur is in a position to come in Gurgaon with in 30 minutes, if he has land in Mahendergarh and he is capable to go there in 70 minutes, he will prefer that revenue and that is the way we can have inclusive growth. दिल्ली के चारों तरफ वसे लोगों की कास्ट पर हम नहीं चाहते कि

हरियाणा का जो हिंटरलैंड है उसकी मौलिकग्रोथ हो। स्पीकर सर, मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ क्योंकि I have my own views on this. मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि जब हरियाणा प्रदेश बना तब आपके एग्रीकल्चर सैक्टर का 56 परसैंट स्टेट जी०डी०पी० का हिस्सा था अब वह हिस्सा डाउन होकर 19 परसैंट आ गया है। टरसरी सैक्टर, जिसको सर्विस सैक्टर बोलते हैं वह अब 51 परसैंट पर पहुंच गया। 51 परसैंट पर जो पहुंचा है that is sign of growth. स्पीकर सर, मैं यह नहीं कहता कि उससे हमारी तरक्की नहीं हुई। जय टरसरी सैक्टर और इण्डस्ट्रियल सैक्टर का स्टेट जी०डी०पी० से शेयर बढ़ता हे तो that is indicator for growth लेकिन वह तभी है जब कृषि पर आधारित जो हाथ हैं उनको और रोजगार मिले। डिस्पर्सल ग्रोथ, इकलूसिव ग्रोथ का भी यही मतलब है। इक्नोमिक कोरीडोर की जो हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात की तसल्ली है कि जो हम के०एम०पी० एक्सप्रैस हाईवे बना रहे हैं उसमें 136 किलोमीटर लम्बी जो स्टेट ऐक्सप्रैस हाईवे होगा वह देश का नहीं दुनियां का कमर्शियल एक्टिविटीज का एक हब हो सकता है। हरियाणा के बारे में उससे बड़ी और कोई बात कोई सोच नहीं सकता है। हम यह बात मान कर चलते हैं कि के०एम०पी० हमारे लिए तरक्की का एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। यह बात भी जरूरी है कि फास्टर कनैक्टिविटी हो और फास्टर कनैक्टिविटी तभी सम्भव है जब हम हरियाणा के सुदूर हिस्से को भी दिल्ली के उस हिस्से से जोड़ सकें जहां कमर्शियल एक्टिविटीज हैं। स्पीकर सर, एक मैं इरिगेशन के बारे

में भी कहूँगा। मैं यह समझता हूँ कि हमने इरिगेशन में बहुत से नए प्रोजैक्ट्स लिए हैं। जो हरियाणा के लिए आगे आने वाले समय में बहुत ही लाभकारी हैं इसलिए हमने इनका चनि साईज भी बढ़ाया हैं लेकिन एक एरिया आफ कन्सर्न हे वह है किसाऊ डैम, लखवारा डैम और रेणुका डैम। मुझे उम्मीद है कि रेणुका डैम की बात हमारे हक में ही जाएगी। पहले इस्का पानी सिर्फ दिल्ली में पीने के लिए जाता था और अब शायद इससे हरियाणा को भी लाभ होगा। स्पीकर सर, यहाँ पर बोलते हुए बहुत से साथियों ने चौधरी रणबीर सिंह जी को श्रद्धांजलि दी थी। में उनके बारे में एक बात सदन में कहना चाहता हूँ जिसका आपको पता नहीं होगा कि आज से 50 साल पहले रेणुका डैम के मामले को चौधरी रणवीर सिंह जी ने कसीव किया था। सर, मैं इस वारे में कहना चाहूँगा कि वह कमी भी हरियाणा की प्रायरिटी नहीं रही है, यह बड़ा ही अनफारचुनेट है। हमने कई बार यहां पर देखा है कि जिस एस०वाई०एल० की बात ये करते हैं उसको हमेशा इन्होंने राजनीतिक मुद्दा वनाया है। ये उस बारे में कभी सीरियस नहीं थे। आज चाहे रेणुका, किसाऊ और लखवारा डैम की बात हो, इम? लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमारे एक्ट को एब्रोगेट करने के लिए विधान सभा में बादल, अमरिन्दर सिंह और बी०जेपी० आपस में हाथ मिलाकर इक्ट्ठा होकर आधे घंटे में गवर्नर से साईन करवा लाए थे। यह इसलिए किया गया ताकि हमें पानी न मिले। (विघ्न) यह सोचने की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहूँगा कि उस समय पंजाब में किस की सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपको उस समय चौलेंज करना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान) आपने कोई चौलेंज नहीं किया।

श्री बलवन्त सिंहः हमने चौलेंज किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई चौलेंज नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त हम भी सदन में थे। हम प्रधानमंत्री से इस बारे में मिले थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी मिले थे और उन्होंने इसे चौलेंज करने का फैसला किया था और सुप्रीमकोर्ट ने भी यह फैसला हमारे हक में किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब बैठें। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंहः .....

डॉ० सुशील इन्दौराः .....

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): स्पीकर सर, वित्त मंत्री जी ने जो एस०वाई०एल० पर चर्चा की है कि पंजाब असैम्बली में एक रैज्यूलेशन पास हुआ था। हरियाणा में इनकी इनेलो की

सरकार थी और हम अपोजीशन में थे। उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया था। आप इसको राजनीति क्यों बना रहे हो, उन्होंने नहीं बनाई, हम क्यों बनाए। हमने यह कहा था कि हमें सदन के 90 के 90 मैम्बर्ज को चाहे वे किसी भी पार्टी के हों सभी को इस्तीफा देना चाहिए और केन्द्र की सरकार को इसका विरोध जताना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। (शोर एवं व्यवधान) आप लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया था। (शोर एवं व्यवधान) आप राजनीति क्यों करना चाहते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ही यह बात सदन में आई थी। (शोर एवं व्यवधान) ही हमने कहा था और हमने दिया था। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) जो आदमी यह कहता है कि हम हरियाणा में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे और खून खराबा हो जाएगा। आप उनके घर में जाकर रहते हो। उसकी कोठी में आप बसेरा करते हो। (शोर एवं व्यवधान) उसकी कोठी में रोटियां चुगा करते हो। (शोर एवं व्यवधान) वे आपकी रैलियों में जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) वे आपकी रैलियों में जाकर दहाड़ते हैं। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर साहव, आप पहले यह कहो कि आप बादल साहब की कोठी में नहीं रुकेंगे, बादल साहब की कोठी में नहीं ठहरेंगे। कोई और ठहरने की जगह नहीं है क्या? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर साहब,.....

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

डा० सीता रामः स्पीकर साहब,.....

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने.....।

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, ... (शोर एवं व्यवधान),

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस समय तीनों सरकारें इनकी थीं। पंजाब में बादल जी की सरकार थी, हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार थी और ऊपर केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तीनों सरकारों ने एक साल तक क्य नहीं किया। सर, यह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि पंजाब इस नहर को खोदेगा और इसको पूरा करेगा। सर, इन्होंने इस बारे में कुछ नही किया। उसके बाद फैसले में यह था कि अगर पंजाब इस नहर को नहीं खोदता तो भारत सरकार इस नहर को खोदेगी। सर, तीन महीने तक इनकी भी सरकार रही, बादल साहब की सरकार रही, लेकिन इन्होंने तब भी कुछ फैसला नहीं करवाया और न ही ये उसको चौलेंज करने के लिए कोर्ट में गए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश मलिकः स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि उस समय मुख्यमंत्री जी भी सांसद थे। उस समय पार्लियामैंट के चुनाव डिक्लेयर हो चुके थे। जिस तरह आज केन्द्र सरकार तीन महीने के लिए एक अंतरिम बजट लेकर आयी है उसी तरह से उस समय भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार केन्द्र में अंतरिम बजट लेकर आयी थी और उस बजट में 33 लाख रुपये का प्रावधान एस०वाई०एल० कैनाल के लिए किया था। अध्यक्ष महोदय, यह पार्लियामैंट की बात है मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जम्बू कश्मीर की विधान सभा ने जब एक बिल जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्ता देने के बारे में पास करके केन्द्र सरकार को भेजा था तो उस समय वहां की मुख्यमंत्री भी एन०डी०ए० की सरकार का हिस्सा था लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी टाईम कैबिनेट की बैठक बुलाकर उस बिल को रद्द कर दिया था। इसलिए अगर इनके प्रधानमंत्री भी चाहते तो उस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट को या राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते थे, वे उसी समय उसको कैंसिल कर सकते थे।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, यह बात नहीं है, यह मामला नहीं है आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Birender Singh : Sir, that is I am saying on oath. There was not even one correspondence regarding this decision neither with the Punjab Government nor with the Central Government. They were silent spectator and they did

nothing for it.

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर साहब, ...

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इन्होंने एस०वाई०एल० कैनाल के नाम पर हमेशा किसानों को गुमराह किया है। उनके हितों की रक्षा करूने के बजाए अपने हितों की इन्होंने रक्षा की है। अपने बेटों को, अपने पोतों को चुनाव में जिताने के लिए ये नाटकबाजी करते थे। इन्होंने हमेशा राजनीति में झूठ का सहारा लेकर किसानों को धोखा देकर राजनीति की है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सीता रामः स्पीकर साहब, ...

बैठक का समय पढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for another 20 minutes ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for another 20 minutes.

वर्ष 2009–2010 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): स्पीकर साहब, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एस०वाई०एल० कैनाल की खुदाई के लिए हरियाणा के हक में फैसला किया तो उसका आधार इंदिरा गांधी

अवॉर्ड माना, उसका आधार राजीव लौंगोवाल समझौता माना। स्पीकर सर, उसका विरोध किसने किया था? अगर एस०वाई०एल० कैनाल के निर्माण में विलम्ब हुआ तो 100 परसैंट इसकी जिम्मेवारी सामने बैठने वाली पार्टी की है क्योंकि इनकी बदनीयती से इसके निर्माण में विलम्ब हुआ है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैंने इरीगेशन के बारे में यह बात इसलिए कही है कि आज बहुत बड़े स्तर पर वाटर बॉडीजं को रिवाइव करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया है। हमारा यह मानना है कि हरियाणा में जो मानसून का पानी है उसको बचाकर अगर नहीं रखेंगे तो इनकी गलियों का खामियाजा हमारी अगली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। बीबी पुर लेक, भिडावास, ओटू बैराज व मसानी बैराज है अगर इनमें हम पानी स्टोर नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और हरियाणा के किसान के लिए काफी भयानक हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि चौधरी रणबीर सिंह जी ने जो प्रौजैक्ट कन्सीव किया था।.....(विघ्न)

श्री बलवंत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने हाउस में कहा कि स्व० चौधरी रणबीर सिंह जी ने किसाऊ डैम के बारे में 1950 में सोचा था कि बने। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उसके बाद से मंत्री जी कई बार इस विधान सभा में चुनकर आए और कई बार मंत्री बने। क्या इनको पहले कभी किसाऊ और लखवार बांध का ख्याल नहीं आया?

श्री अध्यक्षः चलो, जब ख्याल आ जाए तभी ठीक है।

डा० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के ज्यादातर मंत्री यह कहते हैं कि यह काम इस सरकार ने आकर किया है, वह काम इस सरकार ने आकर किया है इससे पहले किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पूर्व में जो कांग्रेस की सरकारें आईं, क्या वे सभी नक्कारा थी, निकम्मी थी, यह आप बताएं।

श्री अध्यक्षः अगर आप हर पैराग्राफ पर, हर सैंटेंस पर इंट्रप्ट करेंगे तो यह हाउस कैसे चलेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंहः स्पीकर सर, हम तो आपकी अनुमति लेकर ही प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्षः जो बात छपनी है वह तो छप ही जाएगी। चिंता न करो।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें सारी पार्टियां एक हुई थी। आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने अफसोस जाहिर किया था और हमारी पार्टी के छह सदस्यों को बुलाकर उनसे इस्तीफे दिलवाए गए थे। उस समय इतनी खतरनाक कुसंगति थी और हम ऐसे आदमी के मित्र थे कि बीज भी पैदा नहीं हुआ। उन बेचारी ने इतना त्याग किया फिर भी वे दोबारा जीतकर नहीं आए, जिन्होंने इस्तीफे दिये थे।

डॉ० राधे शाम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। आज जो हमारे सामने हांसी–बुटाना नहर बनी है इन विपक्ष के साथियों ने उसका पानी हमारे महेन्द्रगढ़ और नारनौल एरिया में जाने से रोका है इसके बावजूद भी ये वहां वोट मांगने के लिए जाते हैं इसके लिए इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। क्या ये अपने नेता से कहेंगे कि जो केस है इसको वापस लें।

श्री नरेश यादवः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो वाटर लैवल दक्षिण हरियाणा में है, खास तौर से जिला महेन्द्रगढ़ में जो नीचे जा रहा है क्या उसके लिए इस बजट में कोई स्कीम या प्रावधान रखा है? मेरे हल्के के 200–250 गांवों में पानी की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात बता रहा था। अगर इन्होंने मेरी बात समझी होती तो कहना ही न पड़ता। Let me reply मैंने अभी–अभी यह बात कही हे कि जो वाटर बाडीज हैं उनका सबसे पहला काम रीचार्जिंग का है। मैं पिछले 35 साल से हाउस का सदस्य हूँ। पानी की रीचार्जिंग का मैं शुरू से पक्षधर हूँ और मैंने ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस हमेशा से किसाऊ डैम की बात प्रायोरिटी पर कही है। आप साथियों की गलती जो है वह यह है कि आपने जो क्रीटीसिज्म इस इशू पर किया, उसकी वजह से हम 12 हजार क्यूसिक्स पानी अपने हिस्से

का नहीं ले पा रहे हैं। यह तो अच्छा है कि हमने किसाऊ और लखवार डैम के पानी को रैगुलेट कर दिया जिससे पानी उतनी मात्रा में नहीं तो उससे थोड़ी सी कम मात्रा में आता है। रैगुलेट करने से अव 12 महीने पानी डब्लू०जे०सी० सिस्टम से आ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें श्री रणबीर सिंह जी को हाउस की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देनी हे तो आज हमारे को यूनानीमसली इस बात के लिए एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि उस समय जो प्रोजैक्ट उन्होंने कन्सीव किया था उसको बनाने के लिए हम भरसक प्रयत्न करें। प्रयत्न करना ही हमारा धर्म है और यही हमारे को करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह प्रस्ताव यूनानीमसली ही पास हो गया है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। सर, ये जो हमारे विरोधी भाई हैं यह केवल दिखावा ही कर रहे हैं क्योंकि इनकी हरियाणा की तरक्की में कोई रुचि नहीं है।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, वह वात तो पण्डित जी ने कह ही दी है कि बीज भी नहीं जामता।

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, इनको यह बताना चाहिए कि इनका लीडर इतने दिनों से विधान सभा में आखिर क्यों नहीं आ रहा? मुख्यमंत्री जी ने सदन में इतनी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हें।

बजट प्रस्तुत हुआ है, हरियाणा के भविष्य की चर्चा विधान सभा में हो रही है। लेकिन वे हाउस में नहीं आ रहे हैं।

श्री अध्यक्षः उनको सदन में आना चाहिए। यह शोभनीय नहीं है।

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, ये तो शोक प्रस्ताव पर भी सदन को छोड़ कर सारे चले गये थे। यह कितनी शर्मनाक बात है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण लोगों और देश भक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक प्रस्ताव लाया गया था। .....

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, माननीय सदस्य को सदन में ठीक ढंग से बोलना चाहिए। ये हमारी पार्टी के नेता के बारे में अनाप–शनाप बातें कह रहे हैं इन्होंने जो शब्द बोले हैं उनको हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गौतम साहब ने जो कहा है उस शब्द को हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। Nothing to be recorded.

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, ...

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए मैं आपकी बात रिकार्ड करवाऊंगा जिन शब्दों के बारे में आप बात कर रहे हैं वे प्रोसिंडग्ज से निकाल दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान) Noting to be recorded.

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य अपनी सीटो पर खड़े हो गये और वैल की तरफ आकर जोर–जोर से बोलने लगे।)

श्री अध्यक्षः डॉ० इन्दौरा, आप अपनी सीट पर जाकर बोलें। आपकी बात रिकॉर्ड होगी। I allow Dr. Sushi! Indora to speak.

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी हमारे सम्मानित नेता है और उनके बारे में माननीय सदस्य द्वारा जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं इसके लिए इनको सदन से एन्स्पपैल किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सीता रामः .....

डा० सुशील इन्दौराः .....

श्री बलवंत सिंहः .....

श्री अध्यक्षः जो भी सदस्य बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए। इन्दौरा जी, आप अपनी सीट पर जाकर बोलें। I allow you to speak. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता रामः .....

डा० सुशील इन्दौराः .....

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram ji, I warn you. Please do not interrupt the House. आप अपनी सीट पर जाकर कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप अपनी सीट से बोलें तो वह बात रिकॉर्ड होगी। (शोर एवं व्यवधान) जो भी सदस्य बिना परमीशन के बोल रहे हैं वह रिकाह न किया जाए। इन्दौरा जी, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को बिठाएं, I allow you to speak. आप अपनी सीट पर जाकर बोलो। (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने जो बात कही थी वह एक्सपंज कर दी गई है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के सदस्य हाउस की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। इन्होंने जो बात एक्सपंज करने के लिए कही थी अध्यक्ष महोदय, आपने वह बात एक्सपंज करवा दी। ये एम०पी० भी रहे हैं। इनसे ये उम्मीद नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि चौटाला साहब इनके दुव्यर्वहार को देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉक्टर इन्दौरा जी, आप अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान) Indora Ji, please go to your seat. डॉक्टर साहब, इन्होंने जो गलत शब्दों को इस्तेमाल किया था वे एक्सपंज करवा दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो गलत शब्द कहे हैं, इस तरह के आचरण के लिए वे सदन में खड़े होकर माफी मांगे या माननीय सदस्य को सदन से एक्सपैल किया जाये।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, वे शब्द सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिए हैं। (शौर एवं व्यवधान)

Shri Ram Kumar Gautam : Speaker Sir, let me explain my position. (Noise and Interruptions).

डॉ० सुशील इन्दौराः सर, हम इनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) ये खड़े होकर सदन से माफी मांगे। (शोर एवं व्यवधान) हमारे से माफी मांगे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Hon'ble member is explaining his position. They should listen seriously. (Noise and Interruptions).

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, अगर गौतम साहब माफी मांगते हैं तो ठीक है लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, आप इनकी बात तो सुनें। ये माफी मांग रहे हैं या कुछ और कहना चाहते हैं पहले आप इन्हें सुन तो लें। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Rain Kumar Gautam : Speaker Sir, let me explain my position. (Noise and Interruptions).

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने रिग्रेट कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Kumar Gautam : Speaker Sir, I did not regret. (Noise and interruptions).

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य सदन की वैल में आ गये।)

श्री अध्यक्षः प्लीज, आप सभी अपनी–अपनी सीट पर जाकर बैठें। मैंने इनके वे शब्द सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिए हैं। यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं इनकी तरफ से रिग्रेट करता हूं। प्लीज आप बैठें।

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं लेकिन किसी सदस्य को सदन में इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: जी हां।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2009–2010 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भ)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि हमने रेणुका डैम पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रेणुका डैम के लिए लैंड एक्वीजेशन की कार्यवाही हमने शुरू कर दी है। पहले हरियाणा का इसमें हिस्सा नहीं था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह मामला सैंटर में उठाया और अब इसमें हमारा हिस्सा भी है। हम इसमें अपने हिस्से का पैसा भी दे रहे हैं, इस टैन्योर में इसकी लैंड एक्वीजेशन का काम शुरू हो जायेगा। इसके अतिरिक्त किशाऊ और लखवार डैम के लिए भी हम कार्यवाही कर रहे हैं। इनके लिए हमने एक कमेटी कान्स्टीच्यूट कर दी है।

Shri Birender Singh : Speaker Sir, before I conclude and request to the Hon'ble Members to pass Budget Estimates for the year 2009-10, I would like to give you

certain figures which are pertinent for the information of the Hon'ble Members. This year, annual plan which is of Rs. 10,000/- crore. This plan size has increased from Rs. 7100/- crore to Rs. 10,000/- crore but the most important factor is that this ratio of State G.D.P. is 4.50% which is highest ever in the State that means in the rest of annual plans, the State G.D.P. share used to be between 2% to 3.50%, Now, it has reached upto 4.50% i.e. State G.D.P. share percentage. Speaker Sir, number two point is that some of the Hon'ble Members have pointed out that the pension for the widows has not been given much of increase in proportion to old age pension. Speaker Sir, now I announce that Rs. 50/- more would be added in the enhanced pension of widows. इस प्रकार से उनकी पैंशन 550 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गई है।

श्री सुभाष चौधरीः स्पीकर सर, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से मैटल इण्डस्ट्री के ऊपर वैट कम करने की डिमाण्ड की थी। क्या मंत्री जी उस बारे में कुछ बतायेंगे?

श्री अध्यक्षः सुभाष चौधरी जी, वित्त मंत्री जी ने सभी मैम्बर के सुझावों को नोट कर रखा है। अगर सभी मैम्बर्ज इस प्रकार से अपने सुझावों के बारे में पूछेंगे तो मंत्री जी के लिए स्पैसिफिकली कलैरीफाई करना बहुत मुश्किल होगा। it is not possible.

प्रो० छत्तर पाल सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, आनरेंबल फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने जो कल मैंने हाईजनिक कडीशज के ऊपर विलेजिज में एनीमल्ज और

हयूमन बीग्स के ऊपर जिक्र किया था उन्होंने इस प्यायंट को टच किया है for which I am grateful to him. स्पीकर सर, दूसरा जो इम्पोटैंट इश्यू मैंने उठाया था वह यह था कि इरीगेशन विभाग में रिमॉडलिग की जिम्मेदारी इरीगेशन विभाग ने ले ली है और जो खाले कच्चे रह गये थे उनकों पक्का करने की जिम्मेदारी काडा को दे दी गई है। स्पीकर सर, एम०आई०टी०सी० ने कुछेक एक्सटेंशन के प्राविजन्स छोड़े थे, जो खाले एक्सटैंड होने थे जिन पर फार्मरज डिमाण्ड करते रहे हैं इस बारे में इरीगेशन विभाग ने आज तक यह डिसाईड नहीं किया कि उन खालों को इरीगेशन एक्सटैंड करेगा या काडा एक्सटैंड करेगा। स्पीकर सर, यह डिमाण्ड बहुत लम्बे समय से पेंडिंग है। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने गवर्नर एड्रैस पर भी और बजट पर भी इस बात को प्वायंट आऊट किया था कि जिला हिसार आधा राजस्थान से लगता है और सरकार की चिंतायें राजस्थान से लगती बैल्ट और जिलों के प्रति इतनी रही हैं जिस पर आपने हांसी–बुटाना लिंक नहर बनाने की योजना बनाई जो सरकार द्वारा उठाया गया बेहतरीन कदम है और इसके अलावा भाखड़ा के सिस्टम में महीने में 14 दिन पानी देने की बात की थी। स्पीकर सर, सरकार के बजट में सफाई और मैटीनैंस का भी बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया है। जबकि पिछली सरकारों के समय में सफाई और मैंटीनैंस के काम लोगों को स्वयं करने पड़ते थे। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूँगा कि भाखड़ा में पानी की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा है। अब जबकि

किसान की फसल पकने को तैयार है और पानी न मिलने की वजह से उनकी गेहूं और सरसों की फसल खराब हो जायेगी। मैं यह बात मिनिस्टर साहब के ध्यान में कई बार ला चुका हूं कि वे अपने पैराफरनेलिया को ठीक करके 16 दिन पानी देने की व्यवस्था को मैनटेन करें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि कच्चे खालों को पक्का करने और क्षतिग्रस्त खालों की रिपेयर का काम 1 अप्रैल से इरीगेशन डिपार्टमैंट से लेकर अब काडा को दे दिया गया है इसलिए अब यह काम काडा द्वारा किया जायेगा।

Mr. Speaker : Mr. Chhattar Pal, according to Irrigation Minister every work of the water course like repair and extension has been given to CADA. Now, please Finance Minister will continue his speech.

प्रो० छत्तर पाल सिंहः स्पीकर सर, फसल की पकाई का समय होने के कारण किसानों को पानी की सख्त जरूरत है इसलिए माननीय मंत्री जी को महीने में पूरे 16 दिन पानी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के बारे में कोई आश्वासन देना चाहिए। स्पीकर सर, यह फार्मर्ज के इंट्रेस्ट की बात हे इसलिए इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, इस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अभी

हमारे पास पानी की दिक्कत है क्योंकि आज कल पानी कम आ रहा है इसलिए अभी हमने महीने में सात दिन पानी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की है। स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब पानी की पोजीशन ठीक हो जायेगी उसके बाद हम महीने में 16 दिन पानी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर देंगे। इस बारे में मैं दूसरी बात यह बताना चाहूँगा कि हमें भिवानी जिले को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना पड़ रहा है क्योंकि वहां पीने के लिए भी पानी नहीं पहुंच रहा है।

प्रो० छत्तर पाल सिंहः लेकिन भाखड़ा में तो पानी की एवेलेबिलिटी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, श्री सुभाष चौधरी माननीय सदस्य ने सुझाव रखा था कि जगाधरी मैटल इंडस्ट्री की हालत चिन्ताजनक है। नेबरिंग स्टेट्स को वजह से उसकी कम्पीट करने की कैपेस्टी क्य हो रही है। वहाँ कम वैट रेट होने की वजह से वह कम्पीट नहीं कर पा रही है। हमने पिछले साल भी उनको यह आश्वासन दिया था और मैं आज भी यह बात रिइट्रेट कर रहा हूँ. कि हम उस इंडस्ट्री को रिवाईव करना चाहते हैं। मैंने आदरणीय विधायक को कहा था कि उनको लेकर वै हमारे महकमे के आफिसर्ज से बात करें और उस इंडस्ट्री को रिवाईव करने में, चाहे वैट में रिलैक्सेशन देनी हो जिससे उसको नेबरिंग स्टेट के साथ कम्पीट करने में फायदा हो तो हम उसके लिए तैयार है। इसी प्रकार से श्री के०एल० शर्मा जी ने सुझाव दिया था कि जो

विडोज हैं, उनके हाऊस टैक्स के एरियर हैं और वह डिस्प्यूटिड है, उस बारे में जो संबंधित मंत्री हैं उनको मैं कहूँगा कि उन पर विचार कर लें और जैसा सम्भव होगा विडोज को जो भी सहायता हम दे सकेंगे हम उसके लिए कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो जनरल मैल्ट डाऊन सारी दुनिया में है, इकॉनोमिक क्राइसिज, इकॉनोमिक डिप्रैसन है हरियाणा को उससे निकलने के लिए हम सब मिल कर प्रयत्न करें और उसका एक ही बड़ा तरीका है कि हम अपने लोगों की परचेजिंग पॉवर बढ़ा सकें। परचेजिंग पॉवर बढ़ने से यह होगा कि जो कारखाना में काम करने वाला है उसको काम मिलेगा, तो कारखानेदार उससे काम लेगा और जिन सैक्टर्ज को बचाने की जरूरत है उन्हें बचाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सारी प्रक्रिया में इस मंदी में भारत सरकार जितनी चिंतित है हरियाणा सरकार भी उतनी ही चिंतित है। श्री प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में यह कहा था कि despite the global economic down turn India's economy is expected to grow at 7 percent in 2008-09. अध्यक्ष महत्येय, इसको मेनटेन करने के लिए यह जरूरी है कि एक्सपोर्ट मार्केट is affected to some extent as their purchasing power had dropped but we are working with Industry to ensure. Thk is what Mr. Oscar Fernandes has stated in the press, but we are working with the industry to ensure that their production line keeps running. To tide over the crisis, industry should take initiative to export demands in newer markets i.e. what

he is stating in the Press. Now, in the last Sir, I would request the Hon'ble Members to see that in the crisis which country or world as a whole is facing, we should look to those areas where we can increase the purchasing capacity of our people. Speaker Sir, in the end, I would appeal to all the Hon'ble members who would instantaneously endorse it to our children, our women, our elders, our destitutes, our disableds, our orphans, our infirm, our ailing, our landless labourers and our weaker sections and so on.

15.00 बजे

They all are ours. What is the obligation of a democratic government to them ? Democracy, as Mr. Lincoln has defined it with a very popular proverb is - The government of the people, for the people and by the people.' This Floor is the temple of democracy and where we are here to contribute shaping the destiny of our people whom we represent i.e the entire Haryana. Rising above all the concerns which divide us and fighting shoulder to shoulder, the menace of recession that visit us once in several decades that should be faced bravely. We are passing through difficult times as we are warned earlier also. Posterity would grade us our intention, our ability, our shrewdness on what we do today on the floor of the House here and now. Mr. Speaker Sir, it is a momentous occasion whether we realize it or not what options do we have before us here. Everybody knows that the available resources are shrinking, be in the pocket of a Rikshawpuller or be in the pocket of a billionaire. Alongwith it, even the coffers of Government are also shrinking. So one option could have been to shut the shop of the Governent developmental initiatives

down and feel happy that we are a revenue surplus State once again. But it would mean leaving our children, our women, our elders, our destiture, our disabled, our orphans, our infirm, our ailing, our landless laborers and our weaker sections of the society to the mercy of God. Please be reminded that rising above all criteria, we are here to do something for the people as well. The other option as to do everything in our command to see to it that the most vulnerable does not suffer by reaching directly to them through appropriate helping hand and if money is available to be borrowed in the present circumstances, there could not be a more pious cause then it for a Government and that is of for and by the people. Government borrowing serves a dual purpose. I remind the Hon'ble Members that **I** have already stated, if we are to borrow from the banks (interruption)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that sitting of the House be extended for 15 minutes.

Voices : Yes, Yes.

Mr. Speaker : The time of the House is extended by 15 Minutes.

वर्ष 2009–2010 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था बजट ऐस्टिमेटस में भी जो हमारा राजस्व खर्चा है। that is 25800 and something और इन्होंने अपने इस भाषण में कहा है कि हमारी रेवेन्यू क्लैक्शन 22–23 हजार के करीब होगी। आपने अपनी स्पीच में यह भी कहा है कि next year we are going to make our expenditure of 35,000 crores, meaning thereby that there is a difference. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को भी इन्कलूड करते हैं जो सरप्लस है और जो डैफिशिट है उसको भी इन्कलूड करते हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इससे एक शंका पैदा होती हैं आज तो माननीय वित्त मैत्री जी ने कुछ नहीं कहा लेकिन इन्होंने खुद कहा है कि आने वाले समय में जो रिसोर्सिज हैं they are shrinking भी कम हो रहे हैं और कहीं हमें यह शक है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से कोई नया टैक्स लगा कर इस रिसोर्सिज को पूरा तो नहीं कर लेंगे।

Shri Birender Singh : Sir, our options are not closed. (Interruptions) You just listen what I say. There is a provision, when there are some excess expenditures in any of the Department, Finance Department has to come to the House for supplementary estimates. Your concern is only that whatever has been announcement of the Chief Minister, they may not be in the Budget, if at all it is not budget, we will come with the supplementary estimates. Where it is prohibited? Where it is said that we are not entitled for this?

What I am saying is that if we are borrowing from the banks that too to pump in the required money to the people of the State to develop their purchasing power, what is bad in it ? Sometimes some fresh tax is imposed, which we have not done for the last four years and we do not have the intention to impose or to levy new fresh taxes.

डॉ० सुशील इन्दौराः वित्त मंत्री जी, आपके बजट अभिभाषण में कृषि, लघु और कुटीर उद्योग तथा पशुपालन के बारे में यह देख रहा हुं कि आपने बजट में जो एलोकेशन की है वह बहुत ही कम है। आपने अभी बोलते हुए कहा है कि अगर कोई कमी रह जाती है तो फिर से बजट एस्टीमेटस में ला सकते हैं। ... .

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, आप बैठ जाए। (विघ्न)

Shri Birender Singh : Let me reply. Sir, it is very clear that Agriculture Department and the Health Departments are the two Departments, where we get lot of grants from the Government of India and those grants are not the part of the budget estimates. As far as this health budget is concerned, you can point out कि यहां पर अमाउंट कम हुआ है ऐसी और भी बहुत सी ग्रांटस हैं। मैं अभी भी यह कह रहा हूँ कि banks today have burnt their fingers and are looking for safer options to invest their credit and none but Government and public expenditure can guarantee them safe options. This may be a priority with the Banks but if we are to take some loan from the Bank, we are ready. Even if we are to have marketing or borrowing, we are ready for that. There is no hesitation. We

want to make it clear when the State coffers would be shrinking then atleast you are to find out some place to have additional amount to run the Government. Sir, but Government and public spending on the other hand would increase the purchasing power, enthusing demand and have the economy recovered. These are not my ideas. Enthusing demands are well established, tested and tried theories of macro economy designed to overcome the recession. These are the fundamentals to overcome the recession. They have gone up to proposing that in the absence of meaningful investment opportunities in such time of test, Government must undertake the activities of digging holes and getting the same filled up again but it must step in by increasing public spending, making up the loss due to depressed investments elsewhere. As against it, please try to understand and appreciate for a while, what this Government intends to do in this background before analyzing from where the money comes. I promise, I shall analyze that also. Please analyze where it is proposed to go. When Hon'ble Chief Minister announced a massive hike in old age pension, disability allowance, allowances to jobless youths and widows etc., he has reiterated the intention of the Government to reach directly to the elders, to the disabled, to the destitutes, to the widows etc. through the needed assistance while increasing their purchasing power in the economy. When it was proposed to make focused investment in the areas of health, sanitation, water supply, industrial housing, facilities for disabled, orphans, etc., the intention was to offer better facilities for all those who are likely to be worst hit by the recession. When it was proposed to renovate-village ponds and water courses, it was targeted to create opportunities, job opportunities for

unemployed and for the landless agriculture labourers. Mr. Speaker Sir, no other State has been reported so far to have initiated such timely well thought of and well intended measures at their own but we have done it. Let me assure you Sir, the Hon'ble Members would see themselves that our efforts would be followed by the other States and not only by the country alone but across the globe. Sir, the latest information with me is that Punjab Government which was going to present Vote on Accounts, they have withdrawn that also, with this plea that our annual plan has not been finalized. But we have been given assurance by the Planning Commission through a letter that you can go ahead with your plan of Rs. 10,000 crores. So, this shows our sound economic health. Sir, in the last addressing the concern of the market borrowing where it is true that we did not raise any such loan during the last several years. It is also not to say that it has become some kind of sacrosanct bench mark for all times to come. Borrowing is not bad if the resources are applied gainfully and productively for creating long term capital assets. It is an acknowledged norm across the globe. Further, it is also an acknowledged norm across the globe that to counter the regressive impact of recession. Government must increase the volume of public spending even by way of raising resources by market borrowings. Sir, as I explained earlier, recession does not mean lack of resources or ability to produce. It is all about lack of purchasing power and liquidity that we are providing. We are providing purchasing power to our people. We are providing liquidity to our people, to our entrepreneurs, to our industrialists, to our farmers, to our youths and to the sections of society which you can call handicapped and other disabled. So, in these circumstances, I

would request the Hon'ble Members that they should give their unanimous consent and pass the budget.

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, बजट को युनानीमसली पास करने में हम ऐग्री नहीं है क्योंकि इसमें ऐग्रीक्चर के बारे में एवं दूसरे मामलों में कई ऐसी बातें हैं जिनमें we are not agreed. It should not be considered as unaimously passed.

Mr. Speaker : O.K., you are performing your duty.

वर्ष 2009–2010 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the Demands for Grants on the Budget 2009-2010 will take place. As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands for grants (Nos. 1 to 25) on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand and they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding Rs. 25,20,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 643,34,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 2—General

Administration.

That a sum not exceeding Rs. 1616,92,24,000 for revenue expenditure and Rs. 45,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 445,42,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 115,87,58,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 5—Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 2242,66,62,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 6—Fina nce.

That a sum not exceeding Rs. 7617,72,000 for revenue expenditure and Rs. 6,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 869,77,28,000 for revenue expenditure and Rs. 1785,51,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 8—Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 5350,51,36,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 1693,89,34,000 for revenue expenditure and Rs. 824,50,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 10—Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 911,89,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 11—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 166,80,19,000 for revenue expenditure and Rs. 6632,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 12—Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1376,62,82,000 for revenue expenditure and Rs. 5,24,60,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in

respect of charges under Demand No. 13 Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 243,41,58,000 for revenue expenditure and R. 2834,41,28,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 14---Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 3810,69,90,000 for revenue expenditure and Rs. 1453,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 140,75,88,000 for revenue expenditure and Its. 146,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 16 Industries.

That a sum not exceeding Rs. 660,89,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 17 Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 328,23,28,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 27,74,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. I9—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 195,09,66,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 20—Forests.

That a sum not exceeding Rs. 1002,70,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 58,03,75,000 for revenue expenditure and Rs. 19,20,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 22—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 1067,95,50,000 for revenue expenditure and Rs. 169,81,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 2,40,81,000 for revenue expenditure and Rs. 12,75,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in

respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 1483,26,70,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House. Question is —

That a sum not exceeding Rs. 25,20,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. I —Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 643,34,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 1616,92,24,000 for revenue expenditure and Rs. 45,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 445,42,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 115,87,58,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 5—Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 2242,66,62,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 76,17,72,000 for revenue expenditure and Rs. 6,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 7—

Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 869,77,28,000 for revenue expenditure and Rs. 17,85,51,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 8—Building & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 5350,51,36,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 1693,89,34,000 for revenue expenditure and Rs. 824,50,00,000 for capital

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 10—Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 911,89,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 1 1—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 166,80,19,000 for revenue expenditure and Rs. 66,32,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 12—Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1376,62,82,000 for revenue expenditure and Rs. 5,24,60,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 243,41,58,000 for revenue expenditure and Rs. 2834,41,28,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under

Demand No. 14—Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 3810,69,90,000 for revenue expenditure and Rs. 1453,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 140,75,88,000 for revenue expenditure and Rs. 1,46,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 660,89,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 17—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 328,23,28,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 27,74,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 19 Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 195,09,66,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 20—Forests.

That a sum not exceeding Rs. 1002,70,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 58,03,75,000 for revenue expenditure and Rs. 19,20,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 22—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 1067,95,50,000 for revenue expenditure and Rs. 169,81,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 2,40,81,000 for revenue expenditure and Rs. 12,75,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 1483,26,70,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2009-10 in respect of charges under Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.

The motion was carried.

विधान कार्य

दि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी एंड श्री केदार नाथ शराइन बिल, 2009

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Urban Development Minister will introduce the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Sir, I beg to introduce the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri kedar Nath Shrine Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Shri Kapal Mchan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 41

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 41 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause-1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause-1 of Clause I stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Sir, I beg to move--

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा फायर सर्विस बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will introduce the Haryana Fire Service Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (ShriA.C. Chaudhary) : Sir, I beg to introduce the Haryana Fire Service Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Fire Service Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Fire Service Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is

That the Haryana Fire Service Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause-2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause-2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause-3 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause-3 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clauses 2 to 55

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 55 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause-1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause-1 of Clause 1 stands part of the Bill

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

प्रो० छत्तर पाल सिंह (धिराय): अध्यक्ष महोदय, सरकार यह जो हरियाणा अग्निशमन सेवा विधेयक नामक एक बहुत ही अच्छा बिल लेकर आई है इसके बारे में मेरा सुझाव है कि अप्रैल मई के महीने में देहात में गेहूं की फसलों में आग लगने कें बहुत सारें केसिज हमारे सामने आते हैं। जब हम इस बारे में जिला प्रशासन से बात करते हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मांग करते हैं तो वे इनसफीशिएट पाई–जाती हैं। कृपया मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि कम से कम हर ब्लाक लैवल पर फायर ब्रिगेड का सिस्टम कंपलीट हो ताकि ऐसी किसी स्थिति में राहत और बचाव किया जा सके।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for another 10 minutes ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for another 10 minutes.

दि हरियाणा फायर सर्विस बिल, 2009 पुनरारम्भ)

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर सर, बिलकुल इसी भावना से प्रेरित होकर ही हमारी सरकार ने यह संशोधन किया है और फायर सर्विसेज को इम्प्रूव करने का विचार किया है ताकि गांव में किसान की पूरी मेहनत से उगाई हुई फसल की कमाई को आग लगने की स्थिति में बचा लिया जा सके। इसमें यह भी प्रावधान रखा है कि आगे चलकर जो–जो चीजें जरूरत की होंगी then we will rush to the Finance Department and this will be done.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, सरकार हरियाणा अग्निशमन सेवा विधेयक नामक एक बहुत ही अच्छा बिल लेकर आई है मेरा इसके बारे में एक ही सुझाव है कि इस सदन में पिछले सत्र में डिजास्टर मैनेजमैंट के बारे में सरकार बिल लेकर आई थी और गवर्नर साहब ने भी उसको मान्यता दे दी थी और आज वह कानून बन चुका है। आज सरकार फायर सिस्टम का बिल लेकर आई है, इसके बारे में मेरा सुझाव है कि इसमें अकेले आग लगने के मामले को ही शामिल न किया जाए बल्कि हरियाणा के किसी भी शहर में कोई मीर प्राकृतिक आपदा आती है या अन्य कोई घटना इस तरह की घट जाती है जैसे भूचाल आ जाता है तो ये फायर सेफ्टी मेजर्ज उन तमाम घटनाओं के मौके पर भी इस्तेमाल किए जाएं, इन बातों को इन्हें इस बिल में सम्मिलित करना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष: आप इसको नैचुरल कलेमिटीज में शामिल कराना चाहते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए।

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, फायर सर्विसिज को सैंट्रलाईज करने का मतलब ही यह था कि जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी सरकार इमीडियेटली वहा पर लोगों की मदद के लिए पहुंच करके अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहेगी।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंडरैगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Su rjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas

(Amendment) Bill be taken into consideration at

once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

पंडित भगवत दयाल शर्मा युनिवर्सिटीज ऑफ हैल्थ साईसिज रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the. Parliamentary Affairs Minister will introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is--

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title ofthe Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parlimentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 2.00 P.M. on Friday, the 20th February, 2009.

***15.2 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Friday, the 20th February, 2009).